लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[तृतीय माला
Third Series]

[खंड 42, 1965/1887 (शक)
Volume, XLII, 1965/1887 (Saka)]

[20 अप्रैल से 1 मई, 1965 तक/30 चैत्र से 11 वशाख, 1887 (शक)तक
April 20 to May 1, 1965/Chaitra 30 to Vaisakha 11, 1887 (Saka)]

ग्यारहवां सत्र 1965/1886-87 (शक)
Eleventh Session, 1965/1886-87 (Saka)

[खंड 42 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XLII contains Nos. 41—50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची

अंक 47—बुधवार 28 अप्रैल, 1965 / 8 वैशाख, 1887 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1053	गोआ के नागरिकों को प्रतिकर	4439—4440
1054	नये विश्वविद्यालय . . .	4440—4443
1055	सांस्कृतिक सम्पत्ति के परिरक्षण का प्रशिक्षण .	4443—4445
1056	पोलैंड द्वारा उर्वरक संयंत्रों का सम्भरण	4445—4446
1057	बेरोजगार इंजीनियर .	4447—4450
1058	केन्द्रीय सचिवालय ढांचे में सुधार .	4450—4453
1059	इंजीनियर और तकनीशन	4453—4455
1060	अकेले विस्थापित व्यक्ति	4455—57
1061	पारे की कमी	4457—59
1062	भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करने के लिए अधिकारी	4459—61

प्रश्नों के लिखित उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या		
1063	लाइसेंस देना .	4461
1064	स्कूल शिक्षा को व्यावसायिक बनाना	4462
1065	सिन्दरी उर्वरक कारखाना .	4462—63
1066	लोकसभा के पटल पर रखे गये कुछ दस्तावेज	4463
1067	सोवियत निर्यात संगठन से पेट्रोलियम उत्पाद	4464
1068	रसायन उद्योग . .	4464—65
1070	शरणार्थियों का दण्डकारण्य छोड़ कर जाना	4465
1071	केन्द्रीय स्कूल .	4466
1072	हिन्दी के प्रयोग के बारे में परिपत्र	4466
1073	राष्ट्रीय एकता परिषद्	4467
1074	सीमा पुलिस दल बल	4467
1075	भारतीय दण्ड संहिता . . .	4468

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 47—*Wednesday, April* 28, 1965/*Vaisakha* 8, 1887 (*Saka*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**Starred Questions Nos.*	*Subject*	PAGES
1053	Compensation to Goan Nationals	4439-40
1054	New Universities	4440—43
1055	Training in Conservation of Cultural Property	4443—45
1056	Supply of Fertiliser Plants by Poland .	4445-46
1057	Unemployed Engineers	4447—50
1058	Reforms in Central Secretariat Structure .	4450—53
1059	Engineers and Technicians . . .	4453—55
1060	Single Family Displaced persons .	4455—57
1061	Shortage of Mercury	4457—59
1062	Special Officer to look into complaints of corruption	4459—61

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

**Starred Questions Nos.*		
1063	Issue of Licences . .	4461
1064	Vocational Bias to Schooling	4462
1065	Sindri Fertilizer Factory	4462-63
1066	Certain Documents laid on the Table of Lok Sabha	4463
1067	Petroleum Products from Soviet Export Organisation .	4464
1068	Chemical Industries . . .	4464-65
1070	Desertion of Dandakaranya by Refugees	4465
1071	Central Schools .	4466
1072	Circular on the Use of Hindi .	4466
1073	National Integration Council .	4467
1074	Border Police Force	4467
1075	Indian Penal Code	4468

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
2692	राजस्थान में योग्यता छात्रवृति . . .	4468
2693	राजस्थान में तकनीकी संस्थाओं में योग्यता छात्रवृतियां	4468–69
2694	राजस्थान में पैट्रोलियम की खपत	4469
2695	राजस्थान को सांस्कृतिक अनुदान	4470
2696	उड़ीसा में स्मारक . . .	4470
2697	मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को मैट्रिक उपरान्त छात्रवृतियां	4471
2698	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृतियां	4471–72
2699	मैट्रिक उपरान्त छात्रवृतियां .	4472
2700	शिक्षा संस्थाओं में स्थान सुरक्षित करना	4472–73
2701	एडिनवर्ग समारोह .	4473
2702	अवकाशप्राप्त सरकारी अधिकारी	4473
2703	विदेशों में जाने वाले उत्तर प्रदेश के छात्र	4473–74
2704	नियम पुस्तकों का अनुवाद	4474
2705	दिल्ली में नई जेल . . .	4474
2706	केरल की विय्यूर जेल में बन्दियों की अत्यधिक संख्या	4475
2708	कोट्टायम (केरल) में पोनकुन्नम हाई स्कूल की इमारत	4475
2709	हिन्दी निदेशालय	4475–76
2710	राजस्थान विश्वविद्यालय	4476
2711	नंगल में पालीटेक्नीक . .	4477
2712	रानी गिदालों के अनुयायियों की गतिविधियां	4477
2713	दिल्ली में माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक .	4477
2714	कलकत्ता विश्वविद्यालय को फोर्ड फाउंडेशन से सहायता	4478
2715	मंत्रियों के दौरे	4478
2716	भित्ति चित्रण . . .	4478–79
2717	भारतीय प्रशासन सेवा के लिये आपातकालिक भर्ती	4479
2719	अखिल भारतीय सेवा अधिकारी .	4479
2720	उड़ीसा को तकनीकी संस्थाओं के लिये अनुदान	4479–80
2721	विदेशों में व्यावहारिक प्रशिक्षण	4480
2722	सरकारी कर्मचारियों की ऋण ग्रस्तता	4480–81
2723	उड़ीसा में सांस्कृतिक केन्द्र .	4481
2724	अरब संसार तथा भारत संबन्धी गोष्ठी	4481
2725	अन्दमान और निकोबार .	4482
2726	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के कर्मचारी	4482
2727	निष्क्रांत भूमि पर अनधिकृत कब्जा	4482–83
2728	आदेशों का हिन्दी अनुवाद .	4483
2729	हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति	4484

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
2692	Merit Scholarship in Rajasthan	4468
2693	Merit Scholarships in Rajasthan Technical Institutes	4468–69
2694	Consumption of Petroleum in Rajasthan	4469
2695	Cultural Grants to Rajasthan	4470
2696	Monuments in Orissa	4470
2697	Post-Matric Scholarships to M. P. Students	4471
2698	Post-Matric Scholarships to S.C. and S. T.	4471–72
2699	Post-Matric Scholarships	4472
2700	Reservation in Educational Institutes	4472–73
2701	Edinburgh Festival	4473
2702	Retired Government Officers	4473
2703	U. P. Students going Abroad	4473–74
2704	Translation of Manuals	4474
2705	New Jail in Delhi	4474
2706	Overcrowding in Viyyoor Jail, Kerala	4475
2708	Ponkunnam High School Building, Kottayam (Kerala)	4475
2709	Hindi Directorate	4475–76
2710	Rajasthan University	4476
2711	Polytechnic at Nangal	4477
2712	Activities of Rani Guidaliu's followers	4477
2713	Secondary School Teachers of Delhi	4477
2714	Ford Foundation Aid to Calcutta University	4478
2715	Tours of Ministers	4478
2716	Fresco Paintings	4478–79
2717	Emergency Recruitment for A.I.S.	4479
2719	All India Service Officers	4479
2720	Grant to Orissa for Technical Institutes	4479–80
2721	Practical Training Abroad	4480
2722	Indebtedness among Government Servants	4480–81
2723	Cultural Centres in Orissa	4481
2724	Seminar on Arab World and India	4481
2725	Andaman and Nicobar	4482
2726	Central Hindi Directorate Employees	4482
2727	Unauthorised occupation of Evacuee Land	4482–4483
2728	Issue of Hindi Versions of Orders	4483
2729	Appointment of Hindi Officers	4484

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
2730	व्यावर का मुहम्मदअली स्कूल	4484
2731	भाषा शिक्षकों के वेतन . . .	4485
2732	केरल में वामपक्षी साम्यवादी नजरबन्दी	4485–86
2733	वैज्ञानिक अनुसन्धान . .	4486
2734	केरल पर्यटन केन्द्र . . .	4486
2735	बिहार के पहाड़ी जिलों में स्कूल .	4487
2736	मेरठ का क्षेत्रीय जनशक्ति सर्वेक्षण	4487
2737	पूर्वी-भारत में तूफान . . .	4487
2738	पंजाबी दिल्ली की सहभाषा के रूप में	4488
2739	मैसूर में लड़कियों की शिक्षा .	4488
2740	युवक होस्टल .	4488
2741	उर्वरक कारखाना	4488–89
2742	पूर्वी-पाकिस्तान राइफल्स द्वारा गोलीबारी .	4489
2743	पैट्रो-रसायनिक निगम	4489–90
2744	भारत-अमरीकी महिला अध्यापिकाओं का आदान-प्रदान कार्यक्रम .	4490
2745	राष्ट्रीय प्रयोगशालायें . . .	4490
2746	दिल्ली में यातायात समस्या .	4491
2747	सेवा निवृत प्रोफेसरों को अनुसन्धान-भत्ता .	4491
2748	केन्द्रीय यान्त्रिक इंजीनियरी अनुसन्धान 'संस्था' .	4492
2749	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में परमाणु अनुसन्धान केन्द्र	4492
2750	माध्यमिक शिक्षा .	4492–93
2751	अखिल भारतीय खेलकूद परिषद्	4493
2752	हिन्दी का प्रचार	4494
2753	पुलिस आवास योजना . .	4494
2754	मद्रास में नाइट्रोजन उर्वरक कारखाना	4494
2755	आसाम में शरणार्थी . .	4494–95
2756	उच्च-शिक्षा के लिये रूसी सहायता .	4495–96
2757	चीनी जासूसों की गिरफ्तारी . . .	4496
2758	केरल राज्य सेवा तथा अधीनस्थ सेवा निगम .	4496

सभा पटल पर रखे गये पत्र-- 4496–97

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

पैंसठवां प्रतिवेदन 4497

प्राक्कलन समिति--

बयासीवां प्रतिवेदन . . 4497

कार्य मंत्रणा समिति--

छत्तीसवां प्रतिवेदन . . . 4498

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS —*contd.*

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
2730	Mohammed Ali School of Biawar	4484
2731	Salaries to Language Teachers	4485
2732	Left Communist Detenus in Kerala	4485–86
2733	Scientific Research	4486
2734	Kerala Tourist Centres	4486
2735	Schools in Hilly Districts of Bihar	4487
2736	Area Manpower Survey of Meerut	4487
2737	Cyclone in Eastern India	4487
2738	Punjabi as Associate Language of Delhi	4488
2739	Girl's Education in Mysore	4488
2740	Youth Hostels	4488
2741	Fertilizer Factory	4488–89
2742	Firing by East Pak. Rifles	4489
2743	Petro-Chemical Corporation	4489–90
2744	Indo-American Women Teachers' Exchange Programme	4490
2745	National Laboratories	4490
2746	Traffic Problem in Delhi	4491
2747	Research Allowances to Retired Professors	4491
2748	Central Mechanical Engineering Research Institute	4492
2749	Nuclear Research Centre at B. H. U.	4492
2750	Secondary Education	4492–93
2751	All India Council of Sports	4493
2752	Propagation of Hindi	4494
2753	Police Housing Scheme	4494
2754	Nitrogen Fertilizer Plant for Madras	4494
2755	Refugees in Assam	4494–95
2756	Soviet Aid for Higher Education	4495–96
2757	Arrest of Chinese Spies	4496
2758	Kerala State and Subordinate Service Rules	4496
	Papers laid on the Table	4496–97
	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
	Sixty-fifth Report	4497
	Estimates Committee—	
	Eighty-second Report	4497
	Business Advisory Committee—	
	Thirty-sixth Report	4498

विषय	पृष्ठ
लोक सभा के स्थगन प्रस्ताव के पश्चात सभा के परिसर के प्रयोग के बारे में--	4498–99
कच्छ सीमा पर पाकिस्तान के सशस्त्र बलों द्वारा गोला बार-बार और लगातार किये जा रहे आक्रमणों से उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रस्ताव--	4499--4538
श्री लाल बहादुर शास्त्री	4499--4503, 4537–38
श्री रंगा	4506--08
श्री ही० ना० मुकर्जी	4508--11
श्री अन्सार हरवानी	4511–12
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती	4512
श्री भागवत झा आजाद	4512–13
श्री रघुनाथ सिंह	4513
श्री उ० मू० त्रिवेदी	4513—15
श्री शं० ना० चतुर्वेदी	4515–16
श्री ओझा	4516
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	4517--20
श्री बाकरअली मिर्जा	4520–21
डा० राम मनोहर लोहिया	4522–23
श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित	4523--25
श्री फ्रैंक एन्थनी	4525--28
श्री कृष्ण मेनन	4528--31
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी	4531–32
श्री सेझियान	4532–33
श्री जोकीम आल्वा	4533–34
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	4534
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	4534–35
श्री इकबाल सिंह	4535–36
श्री जी० भ० कृपालानी	4536–37
श्री नि० चं० चटर्जी	4537

Subject	PAGES
Re : Use of precincts of the House after the rising of Lok Sabha	4888—99
Motion *re* : situation arising out of repeated and continuing attacks by Armed Forces of Pakistan on Kuch border	4999—4538
Shri Lal Bahadur Shastri	4495—4503, 4537-38
Shri Ranga	4546—08
Shri H. N. Mukerjee	4508—11
Shri Ansar Harvani	4511-12
Shri P. K. Chakraverti	4512
Shri Bhagwat Jha Azad	4512-13
Shri Raghunath Singh	4513
Shri U. M. Trivedi	4513—15
Shri S. N. Chaturvedi	4515-16
Shri Oza	4516
Shri Surendranath Dwivedy	4517—20
Shri Bakar Ali Mirza	4520-21
Dr. Ram Manohar Lohia	4422-23
Shrimati Vijaya Lakshmi Pandit	4523—25
Shri Frank Anthony	4525—28
Shri Krishna Menon	4528—31
Shri Tridib Kumar Chaudhuri	4531-32
Shri Sezhiyan	4532-33
Shri Joachim Alva	4533-34
Shrimati Tarkeshwari Sinha	4534
Shri Prakash Vir Shastri	4534-35
Shri Iqbal Singh	4535-36
Shri J. B. Kaipalani	4536-37
Shri N. C. Chatterjee	4537

715 (Ai) LS—2

लोक–सभा

LOK SABHA

बुधवार, 28 अप्रैल, 1965/8 वैशाख, 1887 (शक)

Wednesday, April 28, 1965/Vaisakha 8, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

गोआ के नागरिकों को प्रतिकर

+

1053. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री रा० गि० दुबे :

क्या गृह-कार्य मंत्री 9 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 427 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने गोआ में उन व्यक्तियों को दिये जाने वाले प्रतिकर के बारे में अंतिम निर्णय कर लिया है जिनकी सम्पति पुर्तगाली शासन काल में जब्त कर ली गयी थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): 9 दिसम्बर, 1964 को तारांकित प्रश्न सं या 427 के एक पूरक के उत्तर में मैंने कहा था, "जहां तक जब्त की गई सम्पत्ति का सम्बन्ध है मेरा विचार है उन्होंने वह लौटा दी है"। जांच करने पर पता चला है कि वास्तव में जायदाद की ऐसी कोई जब्ती नहीं हुई थी और इसलिये प्रतिकर का सवाल ही नहीं उठता ।

श्री रा० गि० दुबे : मैं समझता हूं कि जो विवरण हमें दिया गया है उसके उस भाग में कुछ त्रुटि है जहां पर यह कहा गया है कि "सजायें कम कर दी गई हैं" । मेरा विश्वास है कि इस प्रश्न का संकेत उन राजनैतिक कैदियों की ओर है जिन्होंने गोआ-मुक्ति के लिए संग्राम किया था । सरकार के इस कथन का कि "सजायें कम कर दी गई हैं" क्या तात्पर्य है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न उन व्यक्तियों को दिये जाने वाले प्रतिकर के बारे में है जिनकी सम्पति जब्त कर ली गई थी । जब वह यह कहते हैं कि जायदाद की ऐसी कोई जब्ती नहीं हुई थी तो फिर प्रतिकर का सवाल ही नहीं उठता है । मंत्री महोदय के उत्तर में किसी विवरण का सभा-पटल पर रखे जाने का कोई निर्देश नहीं है ।

श्री रा० गि० दुबे : हमें दिये गये विवरण में एक समिति का उल्लेख किया है जिसका गठन इस प्रश्न का अध्ययन करने के लिए किया गया है ।

श्री हाथी : अध्यक्ष महोदय, वह तारांकित प्रश्न संख्या 427 के उत्तर को, जिसका मैंने यहां उल्लेख किया है, निर्दिष्ट कर रहे हैं।

Shri Achal Singh : May I know whether Government propose to give compensation to these political prisoners who fought for the liberation of Goa and who were awarded sentences ?

Mr. Speaker : This question is related to property.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : जैसा कि किसी भी अन्य राज्य में ऐसे राजनैकि पीड़ितों को जिन्होंने . . .

अध्यक्ष महोदय : यह पूर्णतया एक अलग प्रश्न है ।

New Universities

\+

*1054. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Jasvant Mehta :
Shri Subodh Hansda :
Shri S.C. Samanta :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether some State Governments have suggested the estblishment of some new universities ; and

(b) if so, when a decision is likely to be taken in this behalf ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) The University Grants Commission has finalised its recommendations on the subject.

Shri Prakash Vir Shastri : May I know as to which of the States had suggested to the University Grants Commission or to the Ministry of Education the establishment of universities in their States, and for which States the University Grants Commission has given their approval ?

Shri Bhakt Darshan : Sir, the position is this that suggestions are often made to this Commission, but the recommendations finally made by this Commission are as follows : they have expressed their consent with regard to establishment of two new universities by the end of the Five Year Plan

at Madurai (Madras), Kanpur (Uttar Pradesh), Meerut (Uttar Pradesh) Dibrugarh (Assam), Pondicherry, Goa and Gujarat. They have also suggested that no suggestions other than those regarding establishment of these universities may be considered during the Fourth Five Year Plan.

Shri Prakash Vir Shastri : Some states of South had, keeping in view the sentiments of students, requested the Ministry of Education to open some universities there with Hindi-medium. But the Government expressed their inability to establish such universities there due to some legal complexities. May I know whether Government propose to open such universities there after removing all the legal complexities in consonance with the circumstances ?

Shri Bhakt Darshan : According to the information available with me at present, neither any State Government had made such a suggestion to the Commission nor the Commission itself has made any recommendations in this behalf.

Shri Prakash Vir Shastri : The hon. Minister must recall that Mysore Government had requested for the establishment of a Hindi-medium University. It was referred to by Dr. Shrimali also.

Shri Bhakt Darashan : So far as I recall. The proposal was then considered and was not acceded to. But it is sufficiently old matter.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Government itself prefers to co-education not only at University level but at lower stages also. They are themselves introducing this system. But in Aligarh University, the other day when girls students were taking examinations they were assaulted by the male students. In view of this fact, may I know whether Government propose to abolish this co-education system ?

Mr. Speaker : It is a suggestion and the hon. Minister may get it examined.

श्री सुबोध हंसदा : क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने बेलूर में स्वामी विवेकानन्द के नाम पर एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया है था और, यदि हां, तो उस सुझाव पर क्या निर्णय लिया गया ?

श्री भक्त दर्शन : जी, हां । उन्होंने इस सम्बन्ध में एक विवरण सुझाव दिया था जिस पर आयोग ने विचार किया और उसने स्वामी विवेकानन्द की स्मृति में विश्वविद्यालय के बदले एक विशेष संस्था के स्थापित किये जाने की राय दी है जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 3 के अन्तर्गत कुछ समय बाद विश्वविद्यालय की तरह समझी जाने वाली संस्था के रूप में घोषित कर दिया जायेगा ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में कोई विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं और केन्द्र से उसे कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी ?

श्री भक्त दर्शन : जहां तक मुझे जानकारी है, ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है ।

Shri Vishwanath Pandey : Some States had requested the University Grants Commission that there are no Agricultural Universities in their States and as such Agricultural Universities should be set up there. I want to know the recommendation of the U.G.C. in this regard and the names of States for which recommendations have been made ?

Shri Bhakt Darshan : So far as I know, the University Grants Commission has not received any new suggestions regarding Agricultural Universities.

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों में किसी विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में आसाम सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ?

श्री भक्तदर्शन : एक प्रस्ताव था, और उसके लिए एक समिति नियुक्त कर दी गई थी। समिति के प्रतिवेदन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विचार कर रहा है। उन्होंने कोई अन्तिम सिफारिश नहीं की है ।

श्री केप्पन : क्या किसी राज्य से कोई रिहायशी विश्वविद्यालय खोलने के बारे में कोई प्रस्ताव आया है ?

श्री भक्त दर्शन : मुझे "रिहायशी विश्वविद्यालय" शब्द के बारे में पूरी जानकारी नहीं है ।

श्री मुथिया : क्या मद्रास सरकार के मदुरै विश्वविद्यालय स्थापित करने के निर्णय को केन्द्रीय सरकार ने अनुमोदित कर दिया है, यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार मद्रास सरकार को आवश्यक वित्तीय सहायता देगी ?

श्री भक्त दर्शन : जैसा कि मैंने पहले बताया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मदुरै में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव का पहले ही अनुमोदित कर दिया है। अब इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है और नियमानुसार आवश्यक धन राशि दी अवश्य ही जायेगी ।

Shri Yashpal Singh : In view of the fact that there is lack of technical education, may I know whether Government propose to open separate Universities for imparting technical education or arrangements will be made in these universities ?

Shri Bhakt Darshan : Several Universities of technical type have already been opened in our country, as several institutes have been set up with the assistance of foreign Governments. I have no information regarding Engineering Colleges to be opened next year.

Dr. Ram Manohar Lohia : May I know the names of those persons after whose names Universities have been established and whether any university has been opened after the name of Mahatma Gandhiji if not, whether, Government propose to establish a University to commemorate the memory and principles of Mahatma Gandhi ?

Shri Bhakt Darshan : We have not received any such proposal so far. As the hon. Member has given this suggestion, I shall transmit it to the University Grants Commission.

Dr. Ram Manohar Lohia : I wanted to know the names of such universities as have so far been opened after the names of some persons.

Shri Bhakt Darshan : Full information is not available with me at present Perhaps I remember about one or two. For example, it is Vallabh University of Anand, Gujarat.

Dr. Ram Manohar Lohia : Other names which he recalls may also be told. Sir, I really urge upon you to see the way the answers are given here.

Mr. Speaker : If the hon. Minister says that information is not readily available with him, you ask for it later on.

श्री कन्डप्पन : शिक्षा के स्तर सम्बन्धी हित को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का दृष्टिकोण यह है कि हमारे यहां इस समय जितने सम्बद्ध विश्वविद्यालय हैं उनसे अधिक हमारे पास एकात्मक तथा संघीय प्रकार के विश्वविद्यालय होने चाहिये। सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

श्री भक्त दर्शन : इसी दृष्टिकोण को सामने रखते हुए आयोग ने सिफारिश की है कि चौथी योजना के दौरान कोई भी नया विश्वविद्यालय न खोला जाये।

श्री कन्डप्पन : सम्बद्ध विश्वविद्यालयों को संघीय प्रकार के विश्वविद्यालयों में परिवर्तित कर दीजिये।

श्री भक्तदर्शन : मैं उसी के बारे में कहने वाला था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सिफारिश की है कि चौथी योजना के दौरान हमें अपने सभी प्रयत्न स्तर में सुधार करने अर्थात विस्तार के बजाय समेकन पर केन्द्रित करने चाहिये।

सांस्कृतिक सम्पत्ति के परिरक्षण का प्रशिक्षण

\+

*1055. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व एशिया में सांस्कृतिक सम्पत्ति, स्मारकों तथा पुरातत्वीय खोजों का परिरक्षण करने का प्रशिक्षण देने के लिये यूनेस्को की सहायता से भारत में एक संस्था खोली जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो यूनेस्को कितना व्यय वहन करेगा और अन्य क्या सहायता देगा ; और

(ग) प्रशिक्षण के लिये क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है और प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम में कौन-कौन देश भाग ले रहे हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबीर) (क) इस काय के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) और (ग) ऐसी प्रयोगशाला की स्थापना के निर्णय के बाद, वित्तीय सहायता तथा अन्य ब्यौरों के प्रश्न को अन्तिमरूप दिया जाएगा ।

श्री सुबोध हंसदा : चूंकि भारत में यह संस्था इस प्रकार की पहली संस्था होगी इसलिये क्या दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों से भी इस मामले में सलाह ली गई है ?

श्री हजरनवीस : वास्तव में जिन दो विशेषज्ञों ने हमारे यहां आने की कृपा की है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है । यद्यपि हमें इस रिपोर्ट की आम बातें मालूम हैं, परन्तु 'यूनेस्को' ने अपने विचारों की सूचना अभी नहीं दी है । यह सूचना मिलने पर ही हम यह जान सकेंगे कि हम भारत के अतिरिक्त अन्य देशों का भी सहयोग लेने योग्य होंगे अथवा नहीं यद्यपि हमारी इच्छा अवश्य ही ऐसा करने की है ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या सरकार ने यह संस्था भारत में स्थापित करने का निश्चय कर लिया है ? यदि हां तो किस स्थान पर ?

श्री हजरनवीस : हमारी इच्छा तो अवश्य ही यह है कि जहां तक सम्भव हो, यह संस्था भारत में स्थापित की जाए और दक्षिण एशिया में हमारे देश के अतिरिक्त और कोई देश अधिक उपयुक्त नहीं हैं । हमारी दृष्टि में इस समय नई दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय ही इस संस्था के लिये उपयुक्त है क्योंकि यहां हमारी अपनी एक केन्द्रीय प्रयोगशाला है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या हमारे देश में मानव-विज्ञान तथा पुरातत्व के परिरक्षण के प्रशिक्षण का कोई प्रबन्ध है ? यदि नहीं तो क्या इस समय कुछ व्यक्ति प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजे जाते हैं ?

श्री हजरनवीस : हमारे यहां पुरातत्व का एक स्कूल है जहां विद्यार्थी पुरातत्व का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं । मानव विज्ञान के बारे में सदस्य महोदय को अलग पूर्व-सूचना देनी होगी ।

Shri Raghunath Singh ; I want to know whether for the preservation of ancient manuscripts written on tree leaves (Talpatra and Bhojpatra) any arrangement for training is also included in this programme ?

Shri Hajarnavis : Yes Sir. This arrangement will certainly be made.

Shri Madhu Limaye : Some time back when I had the occasion to see the Bag caves, I found that due to bad arrangement, pictures as a whole have been damaged. I, therefore, want to know whether arrangement will be made for the preservation of these caves and such other things under the schemes, which are being prepared in this connection ?

Shri Hajarnavis : Yes. Good Specialists will be consulted on this matter and action will be taken accordingly.

Dr. Ram Manohar Lohia : This being the question of monuments and archaeological finds for Afghanistan to Combodia on the one side and upto Indonesia in the South on the other for which I am not using the words 'Greater India' for its smacks of pride, but as it concerns Jambu Island also, whether the Government is considering to conduct a Scientific, Cultural, Historical and ethnological study of the regions ?

Shri Hajarnavis : I am happy to say that the Government is in agreement with these views of Dr. Lohia.

Dr. Ram Manohar Lohia : If it be so, it is my good fortune.

Shri Bibhuti Mishra : Some ancient documents written on palm leaves are getting damaged. The Government should, through press inform the people that they should handover such documents to them and even if money is required, the Government should pay it immediately and save them from destruction.

Shri Hajarnavis : It has always been our endeavour to see that ancient documents and those on palm leaves should be preserved well and if anyone possesses them he should send them to us for better preservation.

पोलैंड द्वारा उर्वरक संयंत्रों का संभरण

*1056. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोलैंड भारत को गैर-व्यापारिक शर्तों पर उर्वरक संयंत्र देने तथा उनके लिए रुपयों में भुगतान स्वीकार करने के लिए तैयार हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पेशकश को उपयोग में लाने का विचार है ; और

(ग) यह पेशकश अमरीकी सहयोग द्वारा हाल में की गई पेशकश की तुलना में कैसी है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Yashpal Singh : What is the delay in accepting America's offer ?

श्री अलगेशन : हम अमरीकी दलों से भी बातचीत कर रहे हैं । दो बार बातचीत हो चुकी है और आशा है मई के पहले सप्ताह में बातचीत पुनः होगी ।

Shri Yashpal Singh : Shall we be able to set up these plants ourselves and when shall we become self-reliant ?

श्री अलगेशन : इस समय उर्वरक संयंत्र के बहुत से उपकरणों का हम निर्माण नहीं कर रहे हैं, हमें इनका आयात करना पड़ता है । शनैः-शनैः हम उर्वरक संयंत्र के निर्माण में आत्म-निर्भर हो जाएंगे ।

Shri Yashpal Singh : After how long ?

श्री दी० चं० शर्मा : क्या 'वैक्टेल' निगम कुछ उर्वरक संयंत्र स्थापित करने वाला है ? यदि हां तो कितने ? जहां तक पूंजी का संबंध है क्या भारत भी सहयोग करेगा, अथवा सारी पूंजी वह स्वयं लगाएगा ?

श्री अलगेशन : मूल विचार 2 लाख टन क्षमता वाले 5 संयंत्र स्थापित करने का है जिससे कुल 10 लाख टन नाइट्रोजन का उत्पादन होगा । जहां तक इसके वित्तीय पहलू का संबंध है, सरकार इसमें सहयोग देगी । स्वयं उनका संयंत्र स्थापित करने का प्रश्न ही नहीं है ।

श्री दाजी : कुछ समय पूर्व वित्त मंत्री जी ने कहा था कि इस निगम को मई तक का समय दिया गया है और यदि इसने सहयोग न दिया तो हम उनकी सहायता के बिना ही यह कार्य पूरा करेंगे । अब समाचार मिला है कि बातचीत अगले मास होनी निश्चित हुई है । इस मामले की अब तक की स्थिति क्या है ?

श्री अलगेशन : मैंने पहले ही बता दिया है कि बातचीत मई के पहले सप्ताह में होने की संभावना है ।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि जबकि इस निगम के अनुमान के अनुसार 200 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी, वहां भारतीय विशेषज्ञ के अनुसार 150 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिये क्या सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा है ?

श्री अलगेशन : कुल खर्च 202 करोड़ रुपये होगा, जिस में से 109 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में होंगे । परन्तु हमारे विचार में यह काफी अधिक है । बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि यह कोई स्थिर मूल्य नहीं है और सम्भव है कि फिर से हिसाब लगाने पर इसमें काफी कमी हो जाये ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The hon. Minister has stated that two rounds of talks have been completed and that a third round is round the corner. I want to know the results of the two rounds and the nature of assistance promised by America ?

श्री अलगेशन : बातचीत अभी जारी है और इसलिए इसके बारे में बताना सम्भव नहीं है । बातचीत समाप्त हो जाने पर हम इस के बारे में बता सकेंगे ।

श्री क० ना० तिवारी : उर्वरक की तुरन्त आवश्यकता तथा महत्व और उसके अभाव का विचार करके क्या सरकार भारत के सहयोग से उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिये किसी अन्य देश से बातचीत कर रही है ?

श्री अलगेशन : 'वैक्टेल' के अतिरिक्त दूसरे कई दलों ने भी हमारे साथ सहयोग करने का नियंत्रण भेजा है । यह सुझाव हमें प्राप्त हो चुके हैं और विचाराधीन हैं ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या मैं जान सकता हूं कि निजी क्षेत्र की क्या शिकायत है और उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिये मशीनें मंगाने के लिये उन्हें आवश्यक विदेशी मुद्रा क्यों नहीं दी जा रही है और यथाशीघ्र यह संयंत्र लगाने में सहायता करने की दृष्टि से क्या निजी क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरी नहीं की जा सकती ?

श्री अलगेशन : यह दो बातें अलग अलग हैं । हमारे लिये निजी क्षेत्र को विदेशी मुद्रा न देने का कोई प्रश्न ही नहीं है । हमारी रुचि जितनी सरकारी क्षेत्र में है उतनी ही निजी क्षेत्र में है और हमने निजी क्षेत्र के कारखानों के लिये भी विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध किया है । कोरोमेंडल तथा कोठागुडम उर्वरक कारखानों को विदेशी मुद्रा देने का वचन दिया जा चुका है ।

बेरोजगार इंजीनियर

+

*1057. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा स्नातक इंजीनियरों के उपयोग के बारे में किये गये सर्वेक्षण से इस बात का पता चलता है कि प्रति तीन स्नातक इंजीनियरों में से एक इंजीनियर को संतोषजनक कार्य नहीं मिलता है जिसके कारण वह निराश रहता है और उत्पादित कम होती है ;

(ख) क्या यह सर्वेक्षण सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनो क्षेत्रों के औद्योगिक संस्थानों में किया गया था ;

(ग) क्या यह सच है कि जिन संस्थानों का सर्वेक्षण किया गया था उनके प्रबन्धकों के विचारानुसार उद्योगों में प्रवेश करने वाले नये व्यक्तियों के लिए स्थितिज्ञान सम्बन्धी पाठ्यक्रमों (ओरियन्टेशन कोर्सेस) का होना आवश्यक है ; और

(घ) क्या सरकार ने सर्वेक्षण की खोजों पर विचार किया है और युवक इंजीनियरों की सेवाओं का प्रभावी उपयोग करने के तरीके खोजे हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) (क) जी, हां। लगभग 4000 स्नातक इंजीनियरों के उपयोग के बारे में किये गये एक सर्वेक्षण की अन्तरिम रिपोर्ट के अनुसार।

(ख) सर्वेक्षण में 14 सरकारी और 8 गैर-सरकारी औद्योगिक संस्थानों को शामिल किया गया था।

(ग) अधिकांश व्यवस्थापनों का यह मत था, कि विश्वविद्यालयों और कालेजों में उनके उद्योग के उपयुक्त इंजीनियर तैयार किए जाते हैं, लेकिन उनकी राय थी कि इन नए स्नातकों को काम के आरंभिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

(घ) जी नहीं। सर्वेक्षण की अन्तिम रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि सर्वेक्षण के अनुसार 37 प्रतिशत से अधिक इंजीनियर उन स्थानों पर नियुक्त हैं, जहां से प्रमाण-पत्र प्राप्त व्यक्ति आसानी से कार्य कर सकते हैं ? यदि हां, तो यह स्थिति ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन : यह सच है कि कुछ श्रेणियों में कुछ व्यक्ति अपनी इच्छा से ऐसे पदों पर कार्य कर रहे हैं जिन पर प्रमाण-पत्र प्राप्त व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। परन्तु यह एक

दृष्टिकोण है। साथ ही यह भी सच है कि बहुत बार इंजीनियर पहले छोटे पदों पर रखे जाते हैं और बाद में उन्हें पदोन्नति दी जाती है—यह एक दूसरा दृष्टिकोण है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि इंजीनियरों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण की वर्तमान प्रणाली पर्याप्त मात्रा में विस्तृत आधार वाली तथा लाभदायक नहीं है ? यदि हां, तो क्या इस शिक्षा एवं प्रशिक्षण के नवीकरण की कोई योजना बनाई गई है ?

श्रीमती सोन्दरम रामचन्द्रन : कुछ कामों के लिये एक विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और कुछ सरकारी उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रम यह प्रशिक्षण देते हैं जिसकी अवधि 3 मास से ले कर 2 वर्ष तक होती है। आम तौर पर यही पता चला है कि जिन कामों के लिये जो इन्जीनियर रखे गये हैं वे काफी अच्छा ज्ञान रखते हैं।

Shri Yashpal Singh: Distinguished engineers have gone abroad to work there and only third rate engineers are left in the country. What remedy does the hon. Minister suggest so that our engineers should leave their foreign jobs and come home ? What steps are being taken to raise their standard ?

Shrimati Soundram Ramchandran: This is not a fact.

Shri Yashpal Singh : A list of those engineers who have left the country after completing their education will bear out in my contention.

Shrimati Soundram Ramchandran: The enquiry conducted in this regard has revealed that whereas certain industrial undertakings consider foreign training useless, others think that foreign practical training in certain industries certainly improves their work.

Shri Madhu Limaye: If no coordination exists between the two schemes of industrialisation and education. Whether the present situation is due to this or due to lack of proper arrangement for training in the factories etc. ? If the latter is true, what steps Government propose to take to provide training ?

श्रीमती सोन्दरम रामचन्द्रन : पहले इंजीनियरिंग की तीन शाखाएं अर्थात् मैकेनिकल, सिविल तथा इलेक्ट्रीकल, होती थीं। अब, देश में तीव्र गति से हो रहे औद्योगिकरण के कारण इंजीनियरिंग के विविध क्षेत्र बन गए हैं और कई इंजीनियरिंग कालेजों तथा संस्थाओं में ऐच्छिक एवं चुने हुए बहुत से विषयों में प्रशिक्षण दिया जाता है। सदा ही केवल एक क्षेत्र-विशेष के लिये विशेष प्रकार का प्रशिक्षण देना सम्भव नहीं है क्योंकि सामान्य प्रविधियों एवं विज्ञान में एक विशेष स्तर का मूल प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है, और यही प्रशिक्षण इंजीनियरों को यहां दिया जाता है ताकि विदेश जाने पर वे उस विशेष काम के योग्य हो सकें, यदि यह बिना प्रशिक्षण सम्भव हो सके और यदि आवश्यक हो तो कुछ प्रशिक्षण दिया जा सकता है। परन्तु अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् जो समय समय पर अपनी बैठकें बुलाती हैं और पाठ्यक्रमों का अध्ययन करती हैं, छोटी-अवधि के पाठ्यक्रमों का प्रबन्ध करती हैं और जहां कहीं आवश्यक होता है, पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण भी करती हैं।

Shri Kishen Pattnayak: May I know whether it is a fact that the degree awarded by Mining Engineering Institute, Dhanbad a central Government Institute are not acceptable for Government Service even ?

श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन : यह संस्था कोलयरी क्षेत्र में काम करने के लिये इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने के लिये है । इसलिये एक विशेष काम के लिये विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है । मुझे तो ऐसा ज्ञात नहीं है कि जब यह संस्था सरकार द्वारा चलाई जाती है परन्तु फिर भी इसकी डिग्री को सरकारी रोजगार के लिए मान्यता प्राप्त नहीं है ।

Dr. Ram Manohar Lohia : May I know whether it is a fact that engineers are being put on the job for artisan because (i) all work has to be translated in English and the artisans are not able to do it properly in the native language ; (ii) There is a big gap in the salaries of the two, (ranging from 1 : 5 to 1 : 10) whereas it is hardly 2 : 3 in foriegn countries ; and (iii) There is marked difference in the salaries of Indian and foreign engineers ?

श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन : वास्तव में मैं यह प्रश्न नहीं समझ सकी ।

Dr. Ram Manohar Lohia : Have I not been understood ? But I have taken a bow not to speak in English here.....

Mr. Speaker : You may please repeat it in Hindi itself.

Dr. Ram Manohar Lohia My first point is that the work is carried on in English and consequent to this, the skilled artisans are replaced by engineers. The second point is that on the basis of justice and reason there should not be much difference between the pay drawn by an artisan and that drawn by an engineer. In India, this difference is from 5 to 20 times. The result is that the employers and for that matter the Government appoint the engineers in the vacancies meant for artisan so that they may not have to pay them more. However foreign engineers are paid more than the local engineers. Engineers are appointed in place of the artisans so that they are paid less and the work is carried on in English. May I know whether this is fact ?

श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन : पहली बात तो यह है कि इंजीनियरिंग कालेजों तथा पालीटेकनिकों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है । जब ये इंजीनियर तथा पालीटेकनीशन विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, चाहे वे स्थान सरकरी हों अथवा गैर-सरकारी, तो वे क्षेत्रीय भाषा. सीख लेते हैं। इसलिये मेरे विचार में भाषा की कठिनाई कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे कि प्रशासन अंग्रेजी में चलाया जाये और इंजीनियर नियुक्त किये जायें। मेरे विचार में यह ठीक नहीं है ।

जहां तक वेतन की विषमता का सम्बन्ध है, हमारी राज्य सरकारों में अध्यापकों, इंजीनियरों तथा डाक्टरों के वेतनों में भी विषमता है। निस्संदेह केवल वही एक कारण नहीं हो सकता । अन्य सेवाओं में भी वेतनों में इसी प्रकार असमानता है । इसलिये मेरे विचार में डिप्लोमा–प्राप्त व्यक्ति, इस आधार पर कि वे एक जैसा काम कर रहे हैं, वही वेतन नहीं मांग सकते जो इंजीनियरों को दिया जाता है अथवा इंजीनियरों को डिप्लोमा-प्राप्त व्यक्तियों को दिये जाने वाला वेतन नहीं दिया जा सकता ।

जहां तक विदेशी इंजीनियरों का सम्बन्ध है, उन्हें निश्चित वर्षों के लिये निश्चित वेतन-क्रम तथा अतिरिक्त भत्ते अथवा परिलब्धि पर ठेके दिये जाते हैं। इसलिये, मेरे विचार में, हम इसे बन्द अथवा नियमित नहीं कर सकते क्योंकि ये ठेके कुछ समझौतों द्वारा दिये जाते हैं ।

Dr. Ram Manohar Lohia : I asked about the mistries. Mr. Speaker, may I know whether you are satisfied with the answer given. I will keep silent, but I would like to know whether you are satisfied with the answer ?

Mr. Spekaer : There is no question of my satisfaction or otherwise. I allowed you to put up a question and again allow you to do the same. वह यह कहना चाहते थे कि इंजीनियरों को कम वेतन देने तथा बचत करने के उद्देश्य से उन्हें मिस्त्री के पदों पर नियुक्त किया जाता है और क्योंकि काम अंग्रेजी में होता है, मिस्त्री इसे नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती । इसलिये इन पदों पर इंजीनियरों को नियुक्त किया जाता है । Have I followd the hon. Member correctly.

Dr. Ram Manohar Lohia: If you do not follow me, who else will follow ?

श्रीमती सोन्दरम रामचन्द्रन : मुझे ज्ञात है कि ऐसे पदों पर इंजीनियरों को नियुक्त किया जाता है जहां डिप्लोमा प्राप्त व्यक्ति नियुक्त किये जाने चाहियें परन्तु यह भाषा अथवा कम वेतन के कारण नहीं किया जाता । हमारे तकनीकी संस्थानों से इंजीनियर कम तथा डिप्लोमा-प्राप्त व्यक्ति अधिक निकल रहे हैं । इसीलिये हम इस बात पर जोर देते रहे हैं कि अधिकाधिक पालिटेकनिक स्कूल तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने चाहियें । चूंकि इंजीनियर अधिक संख्या में हैं, इसलिये यह स्वाभाविक ही है कि वे ऐसे पदों पर काम करना स्वीकार कर लेते हैं, जो डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों के लिए होते हैं ।

डा० सरोजिनी महिषी : अर्हता प्राप्त ऐसे कितने इंजीनियर हैं जिन्हें विदेशों में इंजीनियरी की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस शर्त पर भेजा गया था कि उन्हें वापस आ कर भारत में ही नौकरी करनी पड़ेगी परन्तु वे वहां ही स्थायी रूप से बस गये हैं ; और इस देश के पूल में कितने हैं ।

श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन : यह एक पृथक प्रश्न है । मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, परन्तु मैं इतना कहना चाहती हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

केन्द्रीय सचिवालय ढांचे में सुधार

\+

*1058. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री रा० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **गृह–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय तथा इसके सम्बद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के पिरामिडीय ढांचे के पुनर्गठन को उच्चतम प्राथमिकता देने का निश्चय किया है ।

(ख) पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत सम्बद्ध कार्यालयों को कितना कार्य सौंपने तथा उसके फलस्वरूप सचिवालय के कर्मचारियों का काम कम करने का विचार है ; और

(ग) क्या फालतू जन शक्ति का निपटान सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) मंत्रालयों तथा उनके सम्बद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारियों की नियुक्ति के स्वरूपों के अध्ययन शुरू कर दिये गए हैं। सचिवालय में सम्बद्ध कार्यालयों से सम्बन्धित काम को करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति की समस्या को सब से पहले प्राथमिकता दी जा रही है ।

(ख) और (ग). इस बारे में मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांत प्रशासनिक सुधार विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुच्छेद 2 और 3 में दिए गए हैं।

श्री प० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रक्रमों पर भिन्न-भिन्न टिप्पणियां लिखी जाती हैं और इसके बाद अधिकारियों के सामने मामले पेश किये जाते हैं और इसके परिणामस्वरूप अधिक कर्मचारी नियुक्त करने पड़ते हैं? क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई नई प्रणाली चालू कर रही है कि अधिकारी अपनी टिप्पणियां आप ही लिखें ?

श्री ल० ना० मिश्र: यह एक अलग प्रश्न है परन्तु कर्मचारियों की संख्या कम करने के दृष्टिकोण से इस सम्बन्ध में भी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकता हूं कि गृह-कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक कर्मचारी एक निश्चित प्रक्रिया बना रहे हैं जो दिल्ली और दिल्ली के बाहर के अधिकारियों पर लागू होगी ताकि फाइल यहां न लाई जाये ?

श्री ल० ना० मिश्र : यदि प्रशासनिक सुधार के हमारे प्रयासों के ठोस परिणाम निकलेंगे तो इनका लाभ केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह राज्यों तक भी पहुंचेगा ।

Shri Bibhuti Mishra: The hon. Minister has just now said that reforms have been made. I would like to know to what extent the Government have made reforms in the pyramidal structure of Secretary, Additional Secretary, Joint Secretary, Deputy Secretary and Under Secretary etc.

Shri L. N. Mishra : Whether there is pyramidal structure or not is the very question. The hon. Member has expressed his own idea. In connection with this, the hon. Home Minister spoke yesterday in detail and observed that the Government was going ahead in this direction and striving for administrative reforms and making such arrangements to see that the work is carried on properly and there is no delay ?

Shri R. S. Pandey : The clerk is placed lowest in the present administrative set up. It is he who prepares the file and does noting and then puts up that file for decision. The decision is taken at the Secretary level. There are classes in between these two categories who only forward these files ahead. I would like to know the steps that are being taken to remove this shortcoming.

Shri L. N. Mishra: There are some people who say that this procedure has both advantages and disadvantages. But this motion is wrong that whatever the clerk writes *is* accepted by the secretary. Efforts are being made to remove the shortcomings.

श्री राम सहाय पाण्डेय : अधिकतम कार्य तो क्लर्क ही करता है ।

श्री शशिरंजन : क्या यह सच है कि अब एक नई प्रक्रिया अपनाई जा रही है जिसके अनुसार फाइल पर 'कृपया बातचीत कीजिए" (प्लीज डिस्कस) लिख दिया जाता है और इससे फाइलों के निपटाने में विलम्ब होता है ?

श्री ल० ना० मिश्र: इससे जल्दी भी हो सकती है तथा इससे देर भी हो सकती है। यह पृथक-पृथक मामलों पर निर्भर करता है ।

श्री शशिरंजन : निश्चय ही इससे विलम्ब होता है ।

Shri Siddheshwar Prasad: Sir, I would like to know whether because of the reforms made in the pre-independence pyramidal structure of the Secretariat during the last fifteen to seventeen years, the number of officers has increased or decreased ? The hon. Home Minister observed that steps have been taken in this connection in some departments. I would also like to konw why such steps are not taken in other departments too ?

Shri L. N. Mishra: This work has been started in some departments. We shall cover more departments. The hon. Member has observed that the number of officers has increased. I would like to say that it is because the work has also increased. We don't deny this but the number of officers has not increased more in proportion to the work.

श्री कपूर सिंह : क्या केन्द्रीय सचिवालय के पिरामिडल ढांचे का पुनर्गठन इस प्रकार किये जाने का प्रस्ताव है कि इसका पिरामिडल ढांचा भी रहने दिया जाये अथवा इसे इस प्रकार पुनर्गठित किया जाये कि पिरामिडल ढांचा समाप्त कर दिया जाये ?

श्री ल० ना० मिश्र : प्रश्न दक्षता, काम ठीक प्रकार से किये जाने तथा बचत का है। पिरामिडल ढांचे तथा किसी दूसरे ढांचे का इतना महत्व नहीं है।

श्री कपूर सिंह : श्रीमान्, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने कुछ और ही उत्तर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : वे कहते हैं कि उद्देश्य तो दक्षता तथा गति है चाहे पिरामिडल ढांचा हो अथवा इसका उलट हो, इस बात से कुछ अन्तर नहीं पड़ता।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : कर्मचारियों के ढांचे तथा सम्बद्ध कार्यालयों को अधिक कार्य सौंपे जाने के प्रश्न के अलावा क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह ज्ञात है कि केन्द्रीय सचिवालय संगठन के मुख्य कार्य-विभाग अर्थात् केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कर्मचारी उनके लिये पदोन्नति के रास्ते समान न होने के कारण बिल्कुल असंतुष्ट हैं और यदि हां, तो क्या सरकार इस ओर ध्यान दे रही है ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह एक अलग प्रश्न है । परन्तु यह एक महत्पूर्ण प्रश्न है और हम इस ओर ध्यान न दे रहे हैं।

श्री दाजी : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि जहां तक कर्मचारियों के ढांचे का संबंध है, एक कर्मचारी को पदोन्नति के लिये 7 से 14 तक पैड़ियां चढ़ना आवश्यक है जैसा कि सुझाव दिया गया था। पिछली आयव्ययक मांगों के दौरान गृह-कार्य मन्त्री ने अपने उत्तर में कहा था कि एक समिति नियुक्त की जायेगी और अब एक वर्ष के बाद भी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है विशेषकर 7 से 14 पैड़ियों को पार करने के संबंध में। क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है और क्या यह दल अथवा समिति भी इन सात से चौदह पैड़ियों के नीचे दब तो नहीं जायेगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : ऐसी कोई समिति नहीं थी। इस संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग कार्यवाही करता है। भिन्न भिन्न विषयों के लिये भिन्न भिन्न बातें हैं जैसा कि गृह-कार्य मंत्री ने कल बताया था। परन्तु जहां तक 7 से 14 पैड़ियों के इस विशेष प्रश्न का संबंध है मुझे इसका पता नहीं है और मैं इस संबंध में जानकारी प्राप्त करूंगा।

Shri Sarjoo Pandey : There is a net work of officers in various departments now-a-days. Is this Committee making some suggestions for fixing a time-limit for disposal of files in order to expedite matters ?

Shri L. N. Mishra : This has to be ensured, otherwise how will the work be expedited.

इंजीनियर और तकनीशन

*1059. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में इंजीनियरों तथा तकनीशनों की तुलनात्मक आवश्यकता का कोई विश्लेषण किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि तकनीशनों की अपेक्षाकृत भारी कमी थी ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) पूर्वी, केन्द्रीय और उत्तरी क्षेत्रों के राज्यों से कमी की सूचना प्राप्त हुई है।

(ग) तकनीशनों के प्रशिक्षण के लिये सुविधाएं देने और पौलिटेकनिकों में अपव्यय को रोकने के लिये उपाय किए गए हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : देश में इंजीनियरों तथा तकनीशनों की अपेक्षाकृत आश्यकता के संबंध में तथ्य तथा आंकड़े क्या हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : हमें इंजीनियरों की कमी नहीं है। हमें तकनीशनों, मिकैनिकों तथा पौली-तकनीशनों की कमी है। यही प्रश्न डा० लोहिया ने भी पूछा था।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने पहले ही जबकि विभिन्न इंजीनियरिंग कालेज तथा पालीटैक्निक्स स्थापित किये गये थे, तकनीशनों तथा इंजीनियरों की भावी आवश्यकता के बारे में अध्ययन किया था और यदि हां, तो इसका क्या कारण है कि हमारे पास अब भी पर्याप्त संख्या में तकनीशन नहीं हैं। क्या वेतन-क्रमों में सुधार करने पर भी विचार किया जा रहा है ?

श्री ल० ना० मिश्र : निस्सन्देह भविष्य में पैदा होने वाली आवश्यकता के बारे में अध्ययन किया गया था। मैं इस संबंध में आवश्यक आंकड़े देता हूं। तीसरी योजना के लिये 51,000 इंजीनियरों की मांग थी तथा इनका सम्भरण 51,000 था। एक लाख तकनीशनों की मांग थी परन्तु सम्भरण 82,000 था ; इस मद में कमी रह गई। चौथी योजना में 1,06,000 इंजीनियरों की आवश्यकता पड़ेगी और 86,000 इंजीनियरों के सम्भरण की आशा है। 1,93,000 तकनीशनों की आवश्यकता पड़ेगी तथा 1,14,000 तकनीशनों के सम्भरण की आशा है। जहां तक कार्यक्रम का संबंध है, मैं यह कह देना चाहता हूं कि वर्ष 1960 में डिग्री पाठ्यक्रम के संस्थान 49 थे और आज इनकी संख्या 117 है। 1950 में दाखिल किये गये विद्यार्थियों की संख्या 4,119 थीं ; आज यह संख्या 27,200 है। 1950 में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संस्थान 86 थे ; आज इन की संख्या 263 है। 1950 में 5,093 लड़के दाखिल हुये आज इनकी संख्या 50,709 है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : इंजीनियरी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये यहां से विद्यार्थी विदेशों में जाते हैं। वे वापस नहीं आना चाहते और अच्छी नौकरी के लिये वहां प्रयत्न करते हैं। इस लिये मैं यह जानना चाहता हूं कि इस से पहले कि सरकार उन्हें विदेशों में जाने की अनुज्ञा दे, उनके यहां वापस आने के संबंध में क्या कोई शर्त लगाई जायेगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : मेरे विचार में विदेशों में बहुत इंजीनियर नहीं जाते। कुछ दिन पहले भी इस के बारे में सभा में निर्देश किया गया था। निस्संदेह, कुछ लोग जाते हैं, परन्तु बहुत नहीं।

श्री अ० ना० विद्यालंकार : जैसा कि माननीय मन्त्री ने कहा है कि सरकार के पास सदैव यह सूचना रहती है कि इंजीनियरों तथा तकनीशनों की कितनी आवश्यकता है। इस का क्या कारण है कि परीक्षा पास करने के बाद बहुत से इंजीनियरों तथा तकनीशनों को नौकरी प्राप्त करने के लिये इधर-उधर भटकना पड़ता है ?

श्री ल० ना० मिश्र : इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। यह हो सकता है कि वे अपनी वर्तमान नौकरी से सन्तुष्ट न हों और अच्छी नौकरियां ढूंढते हों। परन्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत कम लोग जाते हैं। दक्षिण भारत के कुछ लोग उत्तरी भारत को जाने के लिये तैयार नहीं ; यदि पूर्वी भारत में कोई स्थान खाली है तो कुछ लोग वहां जाना पसन्द नहीं करते। जैसा कि मैंने अपने मुख्य उत्तर में कहा है कुल स्थिति बुरी नहीं है, परन्तु कुछ क्षेत्रों में कमी है।

श्री बसुमतारी : क्या उन विद्यार्थियों के लिये, जो विदेशों में भेजे जाते हैं, यहां वापस आने के लिय कोई शर्त लगाई जाती है ?

श्री ल० ना० मिश्र: यदि सरकार उन्हें कोई छात्र-वृत्ति देती है तो शर्त लगाई जाती है और यदि वे अपनी इच्छा से जायें तो कोई शर्त नहीं लगाई जाती।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार ऐसे स्थानों में जहां फालतू इंजीनियर हैं, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में, स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने का विचार कर रही है ताकि उच्चतम प्रतिभा वाले विद्यार्थी आकर्षित हों और उन्हें उपयोगी सेवाओं में लगाया जाये ?

श्री ल० ना० मिश्र : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व-सूचना चाहिये।

डा० रानेन सेन : दो वर्ष हुए इस संसद् ने शिशिक्षुता अधिनियम बनाया था। क्या सरकार ने यह पता लगाया है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत कारखानों में कितने तकनीशनों ने शिशिक्षुता प्राप्त की है, और यदि हां, तो आगे आने वाले वर्षों में इनकी संख्या क्या होगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं ठीक ठीक संख्या नहीं बता सकता। इसके बारे में पता लगाया गया है। योजना आयोग तथा श्रम मंत्रालय इस सम्बन्ध में कार्य करते हैं।

Shri Yashpal Singh : May I know whether the Government will improve the standard of training in such colleges wherefrom the students pass their examinations and undergo training for four years but they are unable to work with the senior engineers.

Shri L. N. Mishra : I don't know the colleges where the conditions are such that even after four years' training, good engineers are not produced, but in respect of training being imparted in the colleges, the people who are really able and who are awarded degrees must be getting jobs.

डा० सरोजिनी महिषी : क्या मैं जान सकती हूं कि जो इंजीनियर पूल में थे, उनमें से कितनों को 1964–65 में पर्याप्त नौकरी मिली ?

श्री ल० ना० मिश्र : इस समय मेरे पास यह सूचना नहीं है।

प्रश्न संख्या 1060 के बारे में

***Re.* Question No. 1060**

Shri Yashpal Singh : I could not follow this qustion. It is written differently in English and in Hindi. It should be correct.

Mr. Speaker : Wherefrom the third language be brought in which it may be written correctly ?

Shri Yashpal Singh : It may be corrected, it should not be written wrongly.

अकेले विस्थापित व्यक्ति

*1060. + { डा० रानेन सेन : / श्री स० मो० बनर्जी : }

क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निश्चय किया है कि अकेले विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास के लिये हकदार नहीं होंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) और (ख). अकेले विस्थापित परिवार जिनमें बूढ़े या कमजोर व्यक्ति, या हरिजन महिलायें या वे व्यक्ति जिनकी आयु 16 वर्ष से नीचे

हो, सभी सहायता या आवाजाही शिवरों में प्रवेश के पात्र हैं और उनको पुनर्वास सुविधायें भी दी जाती हैं। तथापि उन मामलों में जिन में अकेले विस्थापित परिवार के बालिग तथा कुशल पुरुष सदस्य हों जो अपने पावों पर खड़े हो सकते हैं, उनको रोजगार कार्यालय द्वारा रोजगार दिलाने में सहायता की जाती है।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि माना कैम्प तथा अन्य स्थानों से एकल सदस्य परिवारों को इस बात के बावजूद निकांल दिया गया कि वे नौकरी चाहते थे ? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

श्री कपूर सिंह : श्रीमन्, एकल सस्दय परिवार क्या होता है ? ऐसा कभी सुना नहीं गया है। अकेला पुरुष हो सकता है, स्त्री हो सकती है या अकेला व्यक्ति हो सकता है परन्तु एकल सदस्य परिवार क्या होता है ? मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री दाजी : क्या इस प्रश्न का सम्बन्ध मंत्री महोदय के एकल सदस्य होने से है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है कि श्री त्यागी एकल सदस्य परिवार हैं।

श्री त्यागी : श्री कामत भी हैं। मेरे बच्चे हैं।

मुझे उन एकल सदस्य परिवारों के सम्बन्ध में जिन्हें कैम्पों में नहीं रहने दिया गया था ठीक ठीक आंकड़ों का पता नहीं है। वास्तव में जब 1957–58 में पहली बार जांच की गयी तो यह पता लगा कि काफी संख्या में एकल सदस्य परिवार हैं जो कम्पों में वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। तब यह आदेश जारी किये गये कि यदि वे समर्थ शरीर वाले व्यक्ति हों और वही और काम कर सकते हों तो उन्हें वित्तीय सहायता न दी जाये। तब से यह नियम है कि उन्हें केवल नौकरी ढूंढने में सहायता दी जाये और उन्हें कैम्पों में वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाई जा रही इस प्रक्रिया पर आपत्ति की है ? यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है।

श्री त्यागी : यह निर्णय 1957–58 में पश्चिमी बंगाल की सरकार के परामर्श से किया गया था और अभी तक उस निर्णय को लागू किया जा रहा है।

श्री बसुमतारी : क्या मैं पाकिस्तान को वापिस भेजे गये विस्थापित परिवारों की संख्या जान सकता हूं ? उन्हें पाकिस्तान वापिस कैसे भेजा गया ?

श्री त्यागी : श्रीमन्, ठीक आंकड़ों की जानकारी नहीं है परन्तु पाकिस्तानी पारपत्रों के साथ भारत आने वाले 1,97,345 व्यक्तियों में से 1,61,000 वापिस चले गये हैं। यह साधारण प्रक्रिया थी कि पारपत्रों के साथ आने वाले लोगों को भी शरणार्थी समझा जाता था परन्तु वास्तव में वे लोग पारपत्रों के साथ आये और वापिस चले गये।

श्री रघुनाथ सिंह : कैम्पों में असहाय स्त्रियों, बूढ़ों तथा निर्बल व्यक्तियों और अनाथों की संख्या कितनी है ?

श्री त्यागी : इस समय कैम्पों में वित्तीय सहायता तथा सहायता प्राप्त करने वाले बूढ़े तथा दुर्बल व्यक्तियों की संख्या 760, असहाय स्त्रियों की संख्या 1668 तथा अनाथों की संख्या 11 है ।

Dr. Ram Manohar Lohia : Tamil Government has arranged for . .

Some hon. Members : What is Tamil Government ?

Dr. Ram Manohar Lohia : It is Tamil Government for me. It may be Madras Government for English speaking people. Tamil Government have made arrangements for Tamil displaced persons. What arrangement do you intend to make for the displaced persons belonging to Punjab and Uttar Pradesh ?

Shri Tyagi : I would request to Dr. Lohia to give a separate notice for this question. Since this question is not related with the main question, I do not have this information. The people belonging to Madras, Punjab and Uttar Pradesh have gone to their respective places, but proper arrangements will be made for them.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने असम, त्रिपुरा तथा पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकारों को पुनर्वास की सुविधायें देने के लिए स्वविवेकीय शक्तियां दी हैं । यदि हां, तो इन स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग किन शर्तों पर किया जा सकता है ।

श्री त्यागी : श्रीमन्, प्रश्न का सम्बन्ध एकल सदस्य परिवारों को सहायता तथा पुनर्वास सम्बन्धी सुविधाओं से है । इसमें कोई स्वविवेक नहीं है । नियम बिलकुल स्पष्ट हैं कि कैम्पों में असहाय स्त्रियों, बूढों तथा निर्बल व्यक्तियों को और 16 वर्ष से कम आयु वाले अनाथों को नियमित रूप से सहायता दी जाती है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : माननीय मंत्री ने कहा है कि कोई भी योग्य एकल सदस्य परिवार वाला व्यक्ति यहां आयेगा तो सरकार नौकरी प्राप्त करने के लिए उसकी सहायता करेगी। ऐसे कितने व्यक्तियों को नियोजन कार्यालय द्वारा नौकरियां दिलाई गई ?

श्री त्यागी : मेरे लिए ऐसे आंकड़े इकट्ठे करना कठिन है क्योंकि उन्हें विभिन्न स्थानों पर नौकरी मिली हुई है । वे केवल कैम्पों में ही नहीं हैं बल्कि बाहर भी हैं ।

पारे की कमी

\+

*1061. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्री कृ० चं० पन्त :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री म० रं० कृष्ण :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पारे की भारी कमी के कारण कास्टिक सोडा उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) असहज विदेशी मुद्रा स्थिति के कारण पारे के आयात में कुछ कठिनाई है, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि कास्टिक सोडा उद्योग संकट में है।

(ख) उक्त उद्योग की तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य व्यापार निगम ने 50 मीटरी टन पारे का आयात किया है तथा दिसम्बर, 1965 के अन्त तक और 100 मीटरी टन पारे की प्राप्ति का आदेश दिया है। और अधिक पारे को प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या उद्योग द्वारा यह लगातार शिकायत की गई है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा जो वितरण किया जाता है वह न्यायोचित नहीं है जिसका परिणाम यह है कि उनको राज्य व्यापार निगम से अपेक्षित मात्रा नहीं मिल रही है, यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करेगी और इसे ठीक करेगी।

श्री अलगेशन : हमें उद्योग से ऐसी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। यदि माननीय सदस्य मुझे ब्यौरा देंगे तो मैं इस सम्बन्ध में जांच करूंगा। हम इस बात के लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि उद्योग द्वारा पारे की मांग पूरी की जाये।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : यह स्थिति कब तक जारी रहेगी ? क्या इस बात के लिए कोई वास्तविक प्रयत्न किये गये हैं कि पारे के आयात के लिए विदेशी मुद्रा आवंटित की जाये ताकि उद्योगों का काम चालू रहे।

श्री अलगेशन : जैसा कि मैंने कहा है, पहले ही 50 मीटरिक टन आयात किया जा चुका है और इस वर्ष के दौरान 100 मीटरिक टन प्राप्त हो जायेगा। इसके लिए 12 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा आवंटित कर दी गई है और हम अधिक राशि के लिये प्रयत्न कर रहें हैं।

Shri R.S. Pandey: How much does the production of Caustic Soda fall short of the demand ?

श्री अलगेशन : कास्टिक सोडे के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। पिछले वर्ष उत्पादन 1,84,026 मीटरिक टन था और हमें 73,000 मीटरिक टन आयात करना पड़ता था। हम और कारखानों को लाइसेंस दे रहे हैं और चौथी योजना का लक्ष्य 600,000 मीटरिक टन निर्धारित किया गया है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: May I know whether any particular person has been given a licence in the private sector as a result of which soda has become dear in the market ? Is it also a fact that imported soda was cheaper but now the import has been stopped ?

श्री अलगेशन : हमने आयात बन्द नहीं किया है। हम अभी तक आयात कर रहें हैं। जैसा कि मैंने बताया है, हमने पिछले वर्ष लगभग 73,000 मीटरिक टन, सोडा आयात किया था। दिसम्बर, 1963 में विनियंत्रण के बाद मूल्य कुछ बढ़ गये हैं। हम इस बात के लिए उपाय कर रहे हैं कि मूल्य उचित सीमा के अन्दर हों।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Did the Government give a licence to a particular person in the private sector and on his recommendation the import was stopped ?

Mr. Speaker : The import has not been stopped.

क्या यह सच है कि एक विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए उसे लाइसेंस दिया गया और इसी कारण आयात कम कर दिया गया ?

श्री अलगेशन : जी, नहीं ।

Shri Onkar Lal Berwa : There is a soda quarry in Didwana in Rajasthan and 13 tonnes of soda is extracted from that quarry. Do the Government have any objection to increase its production ? If the production is increased, we will get more soda.

श्री अलगेशन : मैं उसकी जांच करूंगा ।

भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करने के लिये विशेष अधिकारी

+

*1062. श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री कोया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विलम्ब तथा भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय में एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख): सरकार ने निश्चय किया है कि जून, 1964 में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायतों के अतिरिक्त शिकायतों पर कार्यवाही करने के प्रबन्धों को सख्त करने के बारे में जारी की गई हिदायतों के अनुसार प्रत्येक मंत्रालय द्वारा पहले ही उठाये गये कदमों का पुनर्विलोकन किया जाना चाहिये और जनता की शिकायतों को

निपटाने तथा जन सम्पर्क के लिए प्रत्येक मंत्रालय में उपयुक्त प्रबन्ध किये जाने चाहिय जिनमें जहां कहीं जरूरी हो वहां एक पूर्ण-कालिक अधिकारी की नियुक्ति भी शामिल है । यह भी निश्चय किया गया कि गृह मंत्रालय में एक अधिकारी नामित किया जाये जो विभिन्न मंत्रालयों के प्रयत्नों में तालमेल रखने और छः महीने बाद इस पद्धति में सुधारों के सुझावों के साथ अपना प्रतिवेदन सरकार को देने के लिए कार्यप्रणाली की समीक्षा करता रहेगा ।

श्री मती रेणुका बड़कटकी : क्या यह विशेष अधिकारी सम्बन्धित मंत्रालयों में काम कर रहे व्यक्तियों में से चुना जायेगा या गृह-कार्य मंत्रालय में से चुना जायेगा और उनका पद क्या होगा ?

श्री हाथी : विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी सम्बन्धित मंत्रालयों में से लिये जायेंगे । समन्वय अधिकारी गृह-कार्य मंत्रालय में से होगा ।

श्रीमती रेणुका बड़कटकी : क्या सरकार का कोई ऐसा प्रस्ताव है कि बदला लेने या भविष्य में होने वाले आर्थिक लाभ की दृष्टि से स्वविवेक या प्रत्यायोजित अधिकार के मनमाने प्रयोग सम्बन्धी शिकायतों की जांच करने की शक्ति उन अधिकारियों को दी जाये ।

श्री हाथी : निर्णय या विलम्ब या शक्ति के प्रयोग सम्बन्धी किसी भी शिकायत की जांच यह अधिकारी करेगा और फिर यह मामला गृह-कार्य मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जायेगा ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: May I know whether in the interest of the Government and the country do the Government propose to constitute a Committee of non-Governmental Members including Members of Parliament ? Are the Government prepared to accept the motion moved by Dr. Singhvi ; if not, on what grounds ?

Shri Hathi: So far as Dr. Singhvi's motion is concerned, discussion on it has taken place and I have replied to it. The steps taken by us were in the interest of the Government and the public.

Shri Jagdev Singh Siddhanti: May I know whether a complaint by the staff of any Ministry or their families would be loobed into by officers of that particular Ministry or by any person selected by the Ministry of Home Affairs ?

Shri Hathi: This scheme relates to those members of public who have some connections with a particular Ministry. It is meant for their grievances.

Shri Sarjoo Pandey: Officers have been appointed for separate Ministries. Apart from that vigilance Commission has also been appointed. I would like to know how their work will be coordinated.

Shri Hathi: These are two separate things. The work of Central vigilance Commission is different. Central vigilance Commission would look into the complaints of corruption and the officers appointed under this scheme would look into the complaints of delay.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : जांच तथा शिकायतों के निवारण सम्बन्धी मूल सिद्धांत यह है कि वह व्यवस्था निष्पक्ष होनी चाहिये और विभाग के प्रभाव से मुक्त होनी चाहिये।

क्या सरकार ने इस सिद्धांत पर विचार किया है और इस सिद्धांत की दृष्टि में ऐसी व्यवस्था बनाने के सम्बन्ध में सोचा है जो विभागीय प्रभाव से मुक्त हों ताकि ऐसी व्यवस्था एक प्रकार का विश्वास उत्पन्न कर सके।

श्री हाथी : एक प्रकार से इस मामले का सम्बन्ध इस बात से है कि क्या स्वतंत्र व्यवस्था होनी चाहिये या इस प्रकार की व्यवस्था होती चाहिये। इस मामले पर विचार किया जा रहा है । जहां तक इस का सम्बन्ध है हम ने काम तो स्वयं प्राधिकारियों से ही लेना है। दूसरे प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

Shri Vishwa Nath Pandey: It has been mentioned in the statement just now laid on the Table of the House by the Minister that an officer of the Ministry of Home Affairs will be nominated to coordinate the work in various Ministries and will submit his report along with the suggestions for improvement after a period of six months. A period of six months has lapsed after the appointment of this officer. I would like to know whether that officer nominated after June, 1964 has since submitted his report alongwith suggestions for improvement. If so, what is the outline of that report and how far have the Government implemented his recommendations ?

Shri Hathi: The Instructions issued in June, 1964 related to making some such arrangement in each Ministry. The decision now taken is that there will be an officer in each Ministry and there will be a coordination officer in the Ministry of Home Affairs. This decision was taken only a few days ago and, therefore, the question of submitting the report does not arise.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

लाइसेंस देना

*1063. **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री हरिशचन्द्र माथुर :
श्री कोया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्द्ध-न्यायिक निकाय को लाइसेंस, परमिट तथा कोटा मंजूर करने का प्राधिकार देने का प्रस्ताव भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं समझा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). जैसाकि 10 मार्च, 1965 को तारांकित प्रश्न संख्या 374 के उत्तर में सूचित किया गया था, प्रशासनिक सुधार विभाग, एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय को लाइसेंस, परमिट आदि मंजर करने का काम सौंपने के सुझाव के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के लाइसेंस, परमिट आदि जारी करने की प्रक्रियाओं के बारे में, आवश्यक आंकड़े एकत्रित कर रहा है । इस बारे में कोई ठोस बात बता सकने के लिए कुछ समय लगेगा ।

स्कूल शिक्षा को व्यावसायिक बनाना

*1064. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपाधि पाठ्यक्रम से पहले की स्कूल शिक्षा की अवधि 11 वर्ष से बढ़ा कर 12 वर्ष करने तथा उसे अधिक व्यावसायिक रूप देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन्) : (क) से (ग). हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम तक ऊंचा करने की एक योजना, जो कई वर्षों से चल रही है, 11 वर्षीय हाईस्कूलों की शिक्षा की अवधि को बढ़ा कर 12 वर्षीय करने के लिए चलाई गई थी। शिक्षा मंत्रियों के एक सम्मेलन में इस बात की ओर संकेत किया गया है कि स्कूल शिक्षा का 12 वर्षीय पाठ्यक्रम ही वह अंतिम उद्देश्य है जिसकी दिशा में देश को बढ़ना चाहिए । फिर भी इस संबंध में कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है । शिक्षा आयोग में शिक्षा पद्धति और स्कूल शिक्षा अवधि सेशनों का परीक्षण भी किया जा रहा है ।

स्कूल शिक्षा को अधिक व्यावसायिक बनाने का प्रस्ताव बहुउद्देशीय स्कूलों और जूनियर तकनीकी स्कूलों की योजना के द्वारा लागू किया गया था । इस विषय पर किए गए वर्तमान सोच विचार से यह पता चलता है कि बहुउद्देशीय स्कूलों में व्यावहारिक पाठ्यक्रमों की विषय वस्तु को बढ़ाना पड़ेगा और माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन करना होगा ताकि देश की विकासशील अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। और वह प्रारंभिक अवस्था या अध्ययन से गुजरने वाले बच्चों की क्षमताओं और अभिरुचियों के अनुकूल बन सके ।

इस उद्देश्य के लिये चौथी आयोजना में आवश्यक व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । इस बीच भारत सरकार ने 1965–66 में ही माध्यमिक अवस्था तक कृषि, प्राद्योगिकी जैसे विषयों के विशेष पाठ्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने का एक कार्यक्रम मंजूर किया है ।

सिन्दरी उर्वरक कारखाना

*1065. **श्री प्रिय गुप्त** :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्व नाथ पाण्डेय :
श्री मुरली मनोहर :
श्री मधु लिमये :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिन्दरी उर्वरक कारखाने में पिछले पांच वर्षों से लगातार घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में कुल कितना घाटा हुआ और प्रति वर्ष कितना घाटा हुआ ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सिन्दरी उर्वरक कारखाने का विस्तार करने की कोई योजना है, यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं । 1959–60 से लेकर 1963–64 वर्षों तक कारखाने का कुल लाभ और शुद्ध लाभ (net profit) क्रमशः लगभग 18.82 तथा 2.37 करोड़ रुपये था ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं । स्थापित सुविधाओं के पूर्ण इस्तेमाल के लिए सिन्दरी कारखाने के वर्तमान उत्पादन के वैज्ञानिक (rationalisation) के लिए एक योजना विचाराधीन है ।

लोक-सभा के पटल पर रखे गये दस्तावेज

*1066. **श्री हरि विष्णु कामत**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री मंत्री परिषद् में अविश्वास प्रस्ताव पर 15 मार्च, 1965 को शिक्षा मंत्री द्वारा दिये गये उस भाषण के सम्बन्ध में, जिस में उन्होंने कहा था कि सदन के एक सदस्य द्वारा 3 मार्च, 1965 को सभा-पटल पर रखे गये कुछ दस्तावेज "चुराये हुए दस्तावेज" थे, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के उद्देश्य से कि दस्तावेज किसने चोरी किये थे तथा किस से चोरी किये थे, कोई जांच अथवा छानबीन की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) : सरकार माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहती है कि शिक्षा मंत्री ने वास्तव में क्या कहा था । जो कुछ उन्होंने कहा था वह 15 मार्च 1955, को लोक-सभा की कार्यवाही के अधिकृत रिकार्ड में देखा जा सकता है । माननीय सदस्य का ध्यान श्री एच० सी० माथुर द्वारा लोक-सभा में 14 अप्रैल, 1965 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 862 के उत्तर में बताये गये सरकारी रवैये की ओर भी आकृष्ट किया जाता है । उस उत्तर में बताई गई स्थिति से आगे बताने के लिये सरकार के पास और कुछ भी नहीं है ।

सोवियत निर्यात संगठन से पैट्रोलियम उत्पाद

*1067. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री राम हरख यादव :
श्री कनकसबै :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 मार्च, 1965 को इण्डियन आयल कारपोरेशन और सोवियत निर्यात संगठन के अध्यक्ष ने पैट्रोलियम उत्पादों के अतिरिक्त संभरण के लिए कोई करार किया था ;

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं ?

(ग) क्या संभरण के लिए भुगतान रुपयों में किया जायेगा ; और

(घ) आयात किये जाने वाले कुल पैट्रोलियम उत्पादों से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन् कबिर) : (क) जी हां ।

(ख) ठेके में 1965 और 1966 में 7,75,000 मीटरी टन के पैट्रोलियम उत्पादों के अतिरिक्त सप्लाई की व्यवस्था है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इन अतिरिक्त मात्राओं (Additional Quantities) की सप्लाई के कारण लगभग 7 करोड़ रुपये की "फ्री" (free) विदेशी मुद्रा में बचत होगी ।

रसायन उद्योग

*1068. श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री प्र० चं० शर्मा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी विनियोजन तथा औद्योगिक विकास मिशन ने इस देश में रसायन उद्योगों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव रखा है ;

(ख) यदि हां, तो वे प्रस्ताव क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

शरणार्थियों का दण्डकारण्य छोड़ कर जाना

*1070. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन शरणार्थियों को दण्डकारण्य में बसाया गया था वे बड़ी संख्या में उसे छोड़ कर जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) 8398 परिवार जिन्हें दण्डकारण्य में बसाया गया था उनमें से पिछले 5 वर्षों में जो गांव छोड़ कर चले गये हैं उनकी संख्या 7 प्रतिशत से कम है ।

(ख) दण्डकारण्य विकास प्राधिकार द्वारा जो मूल्यांकन किया गया है उसके अनुसार गांव छोड़ने वाले परिवारों के कारण निम्न में दिये गये हैं :—

(1) परिवारों को सहायता देने के लिये पुनर्वास की आरम्भिक अवस्था में परिवारों को नये गांवों में बसाने के उपरान्त दो वर्ष तक निर्वाह उपदान दिया जाता है । जब उपदान बन्द कर दिया गया तो बहुत से परिवार 1964–65 में गांव छोड़ कर चले गये ;

(2) कुछ परिवार दूसरे स्थानों पर उनके परिवार के बसे हुये अंगों के पास चले गये हैं;

(3) कुछ क्षेत्रों में अनचाहे तत्वों ने विस्थापितों को दूसरे स्थानों में उत्तम पुनर्वास की आशा दिलाई और कुछ परिवार उनके इस प्रचार के धोके में आ गये;

(4) 1964 के वर्ष में विशेषकर उमरकोट जोन में मानसून बड़ी अनियत हुई । मानसून के कारण फसलें बरबाद हो गई । बहुत से परिवार कम उपज के कारण गांवों को छोड़ कर चले गये;

(5) 1964 में बहुत संख्या में परिवार अपने आपको नये विस्थापित घोषित करने तथा नकद सहायता प्राप्त करने की इच्छा से चले गये ।

छोड़ कर जाने वालों की संख्या को कम करने के लिये निम्न लिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) निर्माण कार्य को लेने से रोजगार के अवसर बढ़ा दिये गये हैं और रोजगार के मामले में उन परिवारों को तरजीह दी जाती है जिनकी उपज कम हुई है ।

(2) जहां आवश्यक हो मुफ्त सहायता भी दी जाती है ।

(3) सीढ़ीदार खेत बनाने की एक योजना लागू कर दी गई है ताकि जोत को धान की खेती के लिये अधिक उपयुक्त बनाया जा सके ।

केन्द्रीय स्कूल

*1071. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्धनों के बच्चों के लिये पब्लिक स्कूलों की तरह के अनेक केन्द्रीय स्कूल स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये चौथी योजना के अन्तर्गत यदि कोई उपबन्ध किया जा रहा है तो वह क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) से (ग). केन्द्रीय स्कूल, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने-जाने वाले व्यक्तियों के बच्चों के लिए हैं जो योजना में अपनाई गई शिक्षा की एकसी पद्धति चाहते हैं । वर्तमान कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजनेतर कार्यकलाप के रूप में ऐसे करीब एक सौ स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं ।

हिन्दी के प्रयोग के बारे में परिपत्र

*1072. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री चांडक :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री प० ह० भील :

क्या **गृहकार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 जनवरी, 1965 के बाद संघ के किसी मन्त्रालय द्वारा इस आशय का परिपत्र जारी किया गया था कि हिन्दी संघ की राजभाषा बन गई है और आगे सारा काम हिन्दी में किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो उन मन्त्रालयों के नाम क्या हैं जिन्होंने ऐसा करने में पहल की ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बाद में परिपत्र वापस ले लिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय द्वारा 30 जनवरी, 1965 को उस मन्त्रालय में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न पदनामों के हिन्दी पर्याय बताने वाला एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया । उस ज्ञापन के पहले वाक्य में यह कहा गया था कि क्योंकि अब हिन्दी संघ की राज भाषा बन गई है । अतः अब से आगे सभी सरकारी काम के लिये हिन्दी का प्रयोग शुरू हो जायेगा । क्योंकि उस वाक्य के पिछले अंश के गलत मायने लगा लिये गए थे, इस लिये उस कार्यालय ज्ञापन को वापिस लेने का फैसला किया गया ।

राष्ट्रीय एकता परिषद्

*1073. श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजभाषा सम्बन्धी राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्या को हल करने के लिये एक राष्ट्रीय एकता परिषद् स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो परिषद् के सदस्यों को नियुक्त करने की कसौटी क्या है ;

(ग) इसका कब तक गठन हो जायेगा ; और

(घ) इसके मख्य कार्य क्या होंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख). सितम्बर-अक्तूबर, 1961 में हुए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन द्वारा किये गये एक निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय एकता से सम्बन्धित सभी मामलों का पुनरवलोकन करने तथा उन पर सिफारिशें देने के लिये राष्ट्रीय एकता परिषद् की स्थापना की गई थी ।

(ग) और (घ): इस परिषद् के 30 सदस्य हैं जिनमें प्रधान मन्त्री (अध्यक्ष),केन्द्रीय गृह मन्त्री और सभी राज्यों के मुख्य मन्त्री, संसद् में प्रतिनिधित्व रखने वाले दलों के नेता, चुने हुए शिक्षा शास्त्री और अन्य प्रमुख व्यक्ति शामिल हैं ।

सीमा पुलिस बल

*1074. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रिय गुप्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समूचे सीमा पुलिस बल को पुनर्गठित करने तथा सुदृढ़ बनाने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो बल को पुनर्गठित करने की योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख): सीमा क्षेत्रों के सशस्त्र पुलिस बल के पुनर्संगठन का प्रश्न इस समय विचाराधीन है ।

भारतीय दण्ड संहिता

*1075. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय दण्ड संहिता जम्मू तथा काश्मीर राज्य में भी लागू कर दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) भारतीय दण्ड संहिता का सम्मिलित सूची की प्रविष्टि से सम्बन्ध है । यह प्रविष्टि जम्मू तथा काश्मीर के विषय में केवल उन अपराधों के बारे में लागू होती है जिनका सम्बन्ध उस सूची की उन प्रविष्टियों से है जो पहले ही लागू कर दी गई है । जब तक इस प्रविष्टि को बिना किसी संशोधन के लागू नहीं कर दिया जाता तब तक भारतीय दंड संहिता को जम्मू तथा काश्मीर पर लागू करना सम्भव नहीं है ।

राजस्थान में योग्यता छात्रवृत्ति

2692. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 1964–65 में विश्वविद्यालय शिक्षा जारी रखने के लिये गरीब छात्रों को योग्यता छात्रवृत्ति देने के लिये राजस्थान सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ख) राज्य सरकार ने इसमें से कितनी राशि खर्च की ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) 1,42,000 रुपए ।

(ख) 1,19,614 रुपये ।

राजस्थान में तकनीकी संस्थाओं में योग्यता छात्रवृत्तियां

2693. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में राजस्थानमें प्रत्येक तकनीकी संस्था को योग्यता व साधन छात्रवृत्तियों के लिये कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) 1965–66 में उस राज्य को कितनी धनराशि दिये जाने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) संस्था का नाम	दी गई रकम
डिग्री	
1. बिरला कालेज पिलानी . .	4,696.44 रुपए
2. बिरला कालेज आफ इंजीनियरिंग, पिलानी .	95,556.51 रुपए
3. इंजीनियरिंग प्रभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय, (एम० बी एम० इंजीनियरिंग कालेज, जोधपुर) . .	63,777.39 रुपए
डिप्लोमा	
4. उदयपुर पोलीटैकनीक, उदयपुर . .	3,794.52 रुपए
5. जोधपुर पोलीटैकनीक, जोधपुर	15,829.08 रुपए
6. अजमेर पोलीटैकनीक, अजमेर .	11,935.20 रुपए
7. अलवर पोलीटैकनीक, अलवर	3,156.75 रुपए
8. गवर्नमैंट पोलीटैकनीक, कोटा	11,115.20 रुपए
9. बीकानेर पोलीटैकनीक, बीकानेर	4,916.12 रुपए
कुल .	2,14,777.21 रुपए

(ख) (लगभग) 2,60,000 रुपए।

राजस्थान में पैट्रोलियम की खपत

2694. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री राम चन्द्र उलाका :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में राजस्थान में पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम से बनी हुई चीजों की कुल कितनी खपत हुई ; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) यह अनुमान लगाया गया है कि 1964–65 में राजस्थान में पैट्रोलियम उत्पादों की कुल खपत लगभग 2.15 लाख मीटरी टन होगी।

(ख) यह खेद है कि भारतीय रक्षा नियमावली के अन्तर्गत लगाये गये प्रतिबन्धों को दृष्टि में रखते हुए ब्यौरे को बताया नहीं जा सकता।

राजस्थान को सांस्कृतिक अनुदान

2695. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में सांस्कृतिक योजनाओं के लिये राजस्थान सरकार को कोई अनुदान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) 1965–66 में इस प्रयोजन के लिये उस राज्य को कितनी राशि देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय के सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(i) सांस्कृतिक मण्डलियों के अन्तर्राज्य विनिमय की योजना के अन्तर्गत 7,114 रुपये 32 पैसे ।

(ii) अग्रिम क्षेत्रों में सशस्त्र सेनाओं के आमोद-प्रमोद के लिए सांस्कृतिक मण्डलियों के प्रायोजन की योजना के अधीन 9,300 रुपये ।

(iii) राज्य में अभिलेखों तथा ऐतिहासिक प्रलेखों के राष्ट्रीय रजिस्टर के संकल्लन की योजना के अन्तर्गत 1,500 रुपये ।

(iv) संग्रहालयों के पुनर्गठन तथा विकास की योजना के अन्तर्गत 81,750 रुपये ।

(ग) राज्य सरकारों को ग्राह्य अनुदान पहले से निर्धारित नहीं होते हैं । सहायता की मात्रा प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के अनुसार निश्चित की जाती है । फिर भी संग्रहालयों के पुनर्गठन तथा विकास की योजना के अन्तर्गत 1965–66 के लिए राज्य सरकार को 50,000 रुपये का नियतन किया गया है ।

उड़ीसा में स्मारक

2696. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या शिक्षा यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या 1963–64 और 1964–65 में उड़ीसा सरकार को एतिहासिक महत्व के प्राचीन स्मारकों के परिरक्षण के लिये कोई वित्तीय सहायता दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उपयुक्त अवधि में प्रत्येक वर्ष में कितनी राशि दी गई और

(ग) इस प्रयोजन के लिये 1965–66 में उड़ीसा को कुल कितनी रकम देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) केवल 1964–65 के दौरान सहायता अनुदान दिया गया था ।

(ख) 1964–65 में 3,750 रुपए ।

(ग) इस स्तर पर कुछ कहना कच्ची बात होगी ।

मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्तियां

2697. **डा० चन्द्रभान सिंह** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962–63, 1963–64 तथा 1964–65 में मध्य प्रदेश में मैट्रिक उपरान्त अध्ययन के लिये छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत कितनी केन्द्रीय सरकारी छात्रवृत्तियां दी गइ: और

(ख) इनके लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क)

(i) 1962–63	. 85 छात्रवृत्तियां
(ii) 1963–64	. 85 छात्रवृत्तियां
(iii) 1964–65	90 छात्रवृत्तियां

(ख) कोई आवेदन पत्र नहीं मंगवाए गए, राज्य के भिन्न भिन्न परीक्षा-प्राधिकारियों से योग्यता सूची उपलब्ध की जाती है और उस राज्य से नियत कोटे के अनुसार इन सूचियों में से योग्यता के आधार पर छात्रों का चुनाव किया जाता है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियां

2698. **डा० चन्द्रभान सिंह :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री उइके :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक उपरान्त शिक्षा के लिये इस समय मासिक कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है;

(ख) यह छात्रवृत्तियां कब से निश्चित की गई हैं;

(ग) क्या सरकार इन छात्रवृत्तियों को पर्याप्त समझती है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन छात्रवृत्तियों की राशि बढ़ाने का है ?

शिक्षा मंत्रालय के सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) छात्रवृत्ति की रकम में फिलहाल निम्नलिखित खर्च शामिल हैं :—

(i) मासिक भरण-पोषण व्यय, जो अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुसार पूर्व विश्वविद्यालय/इण्टरमीडिएट और डिग्री पाठ्यक्रमों के दिन के छात्रों के लिए 27 रुपये और छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए 40 रुपये तथा मेडिसिन, इंजीनियरी आदि व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रमों के दिन के छात्रों के लिए 60 रुपये और छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए 75 रुपये हैं;

(ii) विद्यार्थी द्वारा संस्था अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड को दी जाने वाली और वापस न की जाने वाली सभी अनिवार्य फीस जैसे :—भर्ती/रजिस्ट्रेशन, ट्यूशन, खेल, पुस्तकालय, चिकित्सा, परीक्षा आदि की फीस;

(iii) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को अधिकतम 100 रुपये तक प्रतिवर्ष अध्ययन-पर्यटन खर्च; और

(iv) प्रत्येक शोध विद्यार्थी को अधिकतम 100 रुपये तक थीसिस का टाइप/मुद्रण खर्च।

(ख) छात्रवृत्ति की ये दरें 1954—55 से लागू हैं।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्तियां

2699. **श्री सिद्धय्या** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने एस० एस० एल० सी० पब्लिक परीक्षा पास कर ली है और जो उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियां (मैट्रिक उपरान्त) पाने के पात्र हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या मैसूर राज्य के समाज कल्याण निदेशक को हिदायत दी जायेगी कि वह उपरोक्त विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों पर पुनर्विचार करें जो उन्होंने इस आधार पर अस्वीकृत कर दिये थे कि यद्यपि उन्होंने एस० एस० एल० सी० पब्लिक परीक्षा पास कर ली है किन्तु वे उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ रहे हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी, हां।

(ख) जरूरी पत्र-व्यवहार पहले ही किया जा चुका है।

शिक्षा संस्थाओं में स्थान सुरक्षित करना

2700. **श्री सिद्धय्या** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों, संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों तथा देश के सभी विश्वविद्यालयों से प्रत्येक के अधीन शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये स्थान सुरक्षित करने तथा अन्य रियायत देने के लिये प्रार्थना की थी;

(ख) यदि हां, तो प्रार्थना में सुरक्षित स्थानों तथा जिन अन्य रियायतों का उल्लेख किया गया है उन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों तथा विश्वविद्यालयों की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 4292 / 65]

एडिनबर्ग समारोह

2701. श्री राम हरख यादव : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इस वर्ष एडिनबर्ग समारोह में भाग लेगा;

(ख) यदि हां, तो किन किन बातों में भाग लेगा; और

(ग) इसमें कौन कौन देश भाग लेंगे ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी हां ।

(ख) बिस्मिल्ला खां (शहनाई), विलायत खां (सितार) और के० वी० नारायणस्वामी (कर्नाटक-गायन) ।

(ग) अन्तिम कार्यक्रम की जानकारी अभी तक नहीं है । फिर भी यह एक अन्तर्राष्ट्रीय समारोह है जिसमें अनेक देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं ।

अवकाशप्राप्त सरकारी अधिकारी

2702. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासन सेवा के ऐसे अधिकारियों के नाम, उनके वेतन तथा पद क्या हैं जिन्हें सेवानिवृत्त होने के पश्चात् अप्रैल, 1962 से मार्च, 1965 की अवधि के बीच सरकारी अथवा गैर-सरकारी उपक्रमों में नौकरी करने की अनुमति दी गई; और

(ख) भारतीय असैनिक सेवा तथा भारतीय प्रशासन सेवा के ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों की संख्या और नाम क्या हैं जिन्होंने अप्रैल, 1947 से मार्च, 1965 की अवधि में राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

U.P. Students going Abroad

2703. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the total number of Uttar Pradesh Students who have gone abroad for studies during 1963-64 and 1964-65 by taking loans from the Government of India ;

(b) the names of countries to which they have gone ; and

(c) the number of those students of Uttar Pradesh who have gone abroad for studies during the same period at their own expenses ?

The Minister of Cultural Affairs in the Ministry of Education (Shri Hajarnavis): (a) 1963-64—Four
1964-65—Four

(b) Canada—2
U.S.A.—5
U.S.S.R.—1

(c) Ministry of Education has no information on this point.

Translation of Manuals

2704. Shri Rananjai Singh : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the Ministry and Department-wise number of Manuals which were received by the Central Hindi Directorate from the Ministries and Departments for the purpose of their translation and the number of books among them which have been returned to the Ministries and Departments concerned till December, 1964 ;

(b) whether any date has been fixed for the completion of translation of these books ;

(c) if so, whether this work will be completed by that date ; and

(d) if not, the reason therefor ?

The Deputy Minister in the Ministy of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) A statement is placed on the Table (Place in the Library *See* No. LT-4293/65)

(b) to (d) : No specific time-limit has been prescribed for the completion of the work, mainly for the reason that the manuals are still coming in for translation from the various Ministries and Departments. Every effort is however, made to complete the work as soon as possible with the existing staff engaged on this work.

दिल्ली में नई जेल

2705. **श्री श० ना० चतुर्वेदी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में नये जेल की इमारत बनाने में कितनी लागत लगी;

(ख) वह इमारत कितने क्षेत्रफल में बनी हुई है;

(ग) इमारत की जमीन का कुल कितना क्षेत्रफल है; और

(घ) भूमि की लागत कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) (क) बिजली तथा स्वच्छता प्रबन्ध के उपकरणों को मिला कर 64,96,875 रुपये ।

(ख) 433118 वर्ग गज़ ।

(ग) 178 एकड़ ।

(घ) 3,96,108 रुपये ।

केरल की विय्यूर जेल में बन्दियों की अत्यधिक संख्या

2706. श्री अ० क० गोपालन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शिकायत मिली हैं कि विय्यूर की स्पेशल सब-जेल में नजरबन्द व्यक्तियों को बहुत बड़ी संख्या में रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो शिकायतें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या यह सच हैं कि त्रिवेन्द्रम और कण्णनूर जेल में भी नजरबन्द व्यक्तियों को बहुत बड़ी संख्या में रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) श्री ए० के० गोपालन से एक शिकायत प्राप्त हुई है।

(ख) जेल की कोठरियों में भीड़-भाड़ न होने देने के लिये जेल के पुराने ब्लण्ड में भण्डार गृहों में रोशनी, रोशनदान तथा शौचालय आदि का प्रबन्ध करके उन्हें संनिरोध-कक्षों (लाकअप रूम्म) में बदल दिया गया है। जेल अधीक्षक को यह हिदायतें भी दी गई हैं कि जहां कहीं व्यावहारिक हो वहां खिड़कियां, बिजली आदि लगा कर वह वर्तमान स्थान में भी सुधार करे।

(ग) और (घ). त्रिवेन्द्रम जेल में नजरबन्दों को दी गई चारपाइयों और कुर्सियों से, एक तरह से, खण्ड में चलने फिरने की जगह कम हो गई है। वहां कोई भीड़-भाड़ नहीं है। फिर भी स्थान की सुविधाएं बढ़ाने के लिए उपाय किये जा रहे हैं। कन्नानूर की केन्द्रीय जेल में, जहां नजरबन्द रखे जाते हैं, कोई भीड़-भाड़ नहीं है।

कोट्टायम (केरल) में पोनकुन्नम हाई स्कूल की इमारत

2708. श्री अ० क० गोपालन : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कोट्टायम में पोनकुन्नम हाई स्कूल की इमारत बनाने में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) यह इमारत कब तक बन कर तैयार हो जायेगी; और

(ग) इस इमारत के पूरा होने में देरी के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) :

(क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Hindi Directorate

2709. **Shri M. L. Dwivedi**
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the Hindi Directorate has been making endeavours to carry out its functions satisfactorily since its inception ;

(b) the special features of the work done by the Directorate as compared to the work done departmentally before its inception ;

(c) the increase in the recurring and non-recurring expenditure annually as a result of the establishment of this Directorate as compared to the work done departmentally ;

(d) whether some separate building for the Directorate has been provided, if not, when it is likely to be provided ; and

(e) whether a statement showing the details of the important functions performed by the Directorate towards the development and propagation of Hindi would be placed on the Table of the House ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) Yes, Sir.

(b) The Directorate was set up for the effective implementation of the schemes relating to the development and propagation of Hindi previously handled by the Ministry such as evolution of terminology in scientific and technical subjects etc., translation, preparation and publication of standard works of University level ; preparation of English-Hindi Dictionaries of Scientific and technical terms, printing and publication of terminology finalised and provisionally evolved and Hindi Extension Programmes. It was also entrusted with the work of translation of administrative manuals and procedural literature other than that of statutory nature in use for the various Departments and Ministries of the Government of India.

(c) The exact information is not readily available. However, the expenditure incurred annually from the first year of the establishment of the Directorate to January, 1965 is given in the attached statement. [**Placed in the Library. See No. L.T. 4294/65**]

(d) Efforts are being made to provide compact office accommodation to the Directorate.

(e) A statement is being compiled and will be laid down on the Table of the Lok Sabha in due course.

राजस्थान विश्व-विद्यालय

2710. **श्री यशपाल सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने संघ सरकार से प्रार्थना की है कि वह राजस्थान विश्व विद्यालय को अपने हाथ में ले ले; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नंगल में पालीटेक्नीक

2711. श्री दलजीत सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से नंगल में एक पोलीटेक्नीक खोलने के लिये प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Activities of Rani Guidaliu's Followers

2712. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :
Shrimati Jyotsna Chanda :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the activities of the followers of Rani Guidaliu are on the increase in Kachhar area ;

(b) whether it is also a fact that the followers of Rani Guidaliu abduct people for the purpose of sacrifice ; and

(c) if so, the action taken by Government in this matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) With the influx of some Nagas from Manipur in September-October, 1964, into North Cachar Hills the activities of Rani Guidaliu's party appeared to increase.

(b) There is no evidence to this effect.

(c) As a precautionary measure, police strength in the district has been increased and an officer with a thorough knowledge of the district has been posted as incharge. The situation appears to be now normal.

Secondary Schools Teachers of Delhi

2713. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Secondary Teachers Association has decided to go on hunger strike as a protest against Government's decision not to increase their dearness allowances ; and

(b) if so, the Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Mrs. Soundaram Ramachandran) : (a) No such report has been received by Government.

(b) Does not arise.

कलकत्ता विश्वविद्यालय को फोर्ड फाउंडेशन से सहायता

2714. श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या शिक्षा मंत्री 4 मार्च, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 869 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोर्ड फाउंडेशन विशेषज्ञ दल ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उस प्रतिवेदन की छानबीन कर ली है;

(ग) फोर्ड फाऊंडेशन ने किन शर्तों पर विश्वविद्यालय को सहायता देना मंजूर किया है, और

(घ) इस सहायता की रकम कितनी है ?

शिक्षा मंत्रालय के उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) अंतरिम प्रतिवेदन पर उपकुलपति ने विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों से परामर्श करके विचार किया था । उपकुलपति ने पश्चिम बंगाल सरकार को विश्वविद्यालय के लिए नए संघटन अधिनियम के लिए अपने सुझाव भेजे हैं ।

(ग) और (घ) फोर्ड फाउंडेशन ने अभी तक विश्वविद्यालय को अनुदान देने का कोई प्रस्ताव नहीं किया है ।

Tours of Ministers

2715. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have laid down any definite policy about the tours undertaken by Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers in various States during normal conditions ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) and (b) Ministers undertake tours, when necessary, in connection with the performance of their duties. This is, therefore, not a matter in which any rules can be prescribed.

भित्ति चित्रण

2716. श्री प्र० के० देव :
श्री क र सिंह :
श्री प्र कु० घोष :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय पुरातत्वीय विभाग के संरक्षण में उन प्राचीन स्मारकों के भित्ति चित्रों पर पुनः रंग कराने का है जिनका रंग फीका पड़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के अन्तर्गत किन किन स्मारकों के भित्ति चित्रों पर रंग किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी, हां ।

(ख) अजन्ता और एलोरा (महाराष्ट्र), बाग (मध्य प्रदेश), सित्तन्नवासल व थनजावुर (मद्रास), लेपाक्षि व सोमापल्ली (आन्ध्र प्रदेश), सीता भिंजी (उड़ीसा), तम्बेकरवाडा (गुजरात), मत्तनचेरी पैलेस (केरल), महाकाली मंदिर, चांदा (महाराष्ट्र) ।

भारतीय प्रशासन सेवा के लिये आपातकालीन भर्ती

2717. **प्र० के० देव :**
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय प्रशासन सेवा के लिये आपातकालीन भर्ती करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कब निर्णय किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अखिल भारतीय सेवा अधिकारी

2719. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले एक वर्ष में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के जनता और उनके प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार के किन्हीं मामलों का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा की तकनीकी संस्थाओं के लिये अनुदान

2720. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की प्रत्येक तकनीकी संस्था को योग्यता-व-साधन छात्रवृत्तियों के लिये 1964–65 में कितनी धन राशि दी गई; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये उस राज्य को 1965–66 में कितनी धन राशि देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क)

संस्था का नाम	धनराशि
	(रुपये)
1. यूनीवर्सिटी कालेज आफ इंजीनियरिंग, बुरला	57,525
2. ब्रहामपुर इंजीनियरिंग स्कूल	8,625
3. उड़ीसा स्कूल आफ इंजीनियरिंग, कटक	3,525
4. झरसुगुडा स्कूल आफ इंजीनियरिंग	1,950
5. केन्द्रापारा स्कूल आफ इंजीनियरिंग	2,700
6. उड़ीसा स्कूल आफ माईनिंग इंजीनियरिंग	1,200
7. भद्रक स्कूल आफ इंजीनियरिंग	2,700
योग	78,225

(ख) 1,01,525 रुपये ।

विदेशों में व्यावहारिक प्रशिक्षण

2721. **श्री रामबन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा प्रशासित छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये 1964–65 में कितने छात्र विदेश भेजे गये;

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने छात्र थे; और

(ग) इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक को कितनी छात्रवृत्ति दी गई ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरतवीस) : (क) 88.

(ख) कोई नहीं ।

(ग) छात्रों को दी गई छात्रवृत्ति की रकम सभा-पटल पर रखे गये विवरण में बतायी गई है ; **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल.टी. 4295/65]**

सरकारी कर्मचारियों की ऋणग्रस्तता

2722. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों में व्याप्त ऋणग्रस्तता का सर्वेक्षण करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय के उपमंत्री(श्री ल० ना० मिश्र) : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । :

उड़ीसा में सांस्कृतिक केन्द्र

2723. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा को राज्य में सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना के लिये 1964–65 में कोई वित्तीय सहायता दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय के सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी हां ।

(ख) 40,000 रुपये की केन्द्रीय सहायता की अन्तिम किस्त के रूप में प्रजातंत्र प्रचार समिति, कटक के भवन के साथ लगे दर्शककक्ष के निर्माण के लिए 16,000 रुपये ।

अरब संसार तथा भारत संबंधी गोष्ठी

2724. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री चांडक :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1965 में दिल्ली में हुई अरब संसार तथा भारत संबंधी विचार गोष्ठी में शिक्षा, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में अधिक सहयोग के लिये सुविधायें प्राप्त करने के हेतु जिस 24 सूची कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई थी, उस पर सरकार ने विचार कर लिया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रस्तावित नेहरू यूनिवर्सिटी में एक अरब अध्ययन की संस्था स्थापित करने का है ;

(ग) क्या सरकार विचार गोष्ठी की मुख्य सिफारिशों का समर्थन करती है ; और

(घ) यदि हां, तो इनको कार्यरूप देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) से (घ) गोष्ठी की सिफारिशों पर अभी विचार किया जा रहा है और इस समय कोई राय व्यक्त करना संभव नहीं है ।

अन्दमान और निकोबार

2725. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या गृह-कार्य मंत्री 2 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 814 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "मैसर्स अरोजिया जखेत ट्रेडिंग कम्पनी" का एक जहाज अप्रैल-मई अथवा उसके आस पास अन्दमान तथा निकोबार के जलप्रांगण में चलते हुए एक अन्य अनियमितता में फंस गया था ;

(ख) यदि हां, तो यह अनियमितता कैसी व कितनी थी ;

(ग) सरकार ने जहाज अथवा इस मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) फर्म के जहाजों द्वारा भविष्य में ऐसी या अन्य अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : जी, हां । कहा जाता है जहाज के मालिक ने तटीय सामान के बिल नहीं दिये और "उचित अधिकारी" से बंदरगाह छोड़ने का लिखित आदेश प्राप्त किये बिना ही जहाज को रवाना कर दिया ।

(ग) मामले की जांच की जा रही है ।

(घ) "उचित अधिकारी" को कानून इस प्रकार की अनियमितताओं में हस्तक्षेप करने और उपयुक्त कार्यवाही करने का अधिकार है ।

Central Hindi Directorate Employees

2726. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Y.D. Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of employees in Central Hindi Directorate who have more than three years service to their credit but have not been declared permanent so far ; and

(b) the reasons for not declaring 80 per cent employees as permanent in accordance with the assurance given by the former Education Minister ?

The Deputy Minister in the Ministry of Eduation (Shri Bhakt Darshan) : (a) 188 excluding 39 deputationists who are temporary in the Directorate but hold liens on their permanent posts in their parent departments.

(b) The matter is already under consideration.

Unauthorised Occupation of Evacuee Land

2727. **Shri P.L. Barupal. :**
Shri Samnani :

Will the Minister of **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that the property and land left behind in District Ganganagar by thousands of Muslims who went to

Pakistan after partition, and which should have normally gone to the Custodian, has been occupied by some eminent persons without obtaining any permission from Government ; and

(b) if so, whether Government propose to recover the land from them or to appoint a private Citizen's Committee to look into the matter ?

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi): (a) Government are not aware of any instances involving occupation of evacuee property in District Ganganagar by any "eminent persons". Properties left by Muslims evacuees have vested in the Custodian of Evacuee Property under the provision of Administration of E.P. Act, 1950. Occupation, allotment or disposal of such property is governed by the provisions of the aforesaid Act and the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954.

(b) If information is received that any land is evacuee property and it has not so far been administered as such, the Custodian will take necessary action to complete his records and administer such land in accordance with the law.

Issue of Hindi Versions of Orders

2728. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Rameshwaranand :
Shri P. L. Barupal :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Madhu Limaye :
Shri Utiya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether his Ministry has issued any directions to the effect that all orders relating to welfare work and other standing orders should be accompanied by Hindi version thereof ;

(b) if so, whether his Ministry is acting according to the said directive ;

(c) the number of circulars relating to welfare work issued by his Ministry since 1st January, 1964 onwards and the number of circulars out of those which were accompanied by Hindi versions thereof ; and

(d) the reasons for which the remaining circulars were not accompanied by Hindi versinos ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) and (b) : Yes, Sir.

(c) : In all, 10 circulars were issued. All the circulars were accompanied by Hindi versions thereof.

(d) Does not arise.

Appointment of Hindi Officers

4729. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri P.L. Barupal :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Utiya :
Shri Rameshwaranand :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether his Ministry issued any orders to the effect that at least one Hindi officer be appointed in each Ministry and Department ;

(b) the names of Ministries and Departments which have not carried out these orders so far ; and

(c) the reasons for which they have not done so ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) The Hindi Salahkar Samiti had recommended that there should be at least one Hindi Officer in each Ministry. The suggestion was commended to all Ministries for necessary action.

(b) and (c) : Hindi Officers have been appointed so far in 11 Ministries / Departments. The matter is still under examination in the remaining Ministries.

Mohammed Ali School of Biawar

2730. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the names of 22 Hindu students studying in Mohammed Ali School at Biawar were changed into Muslims names and then the students were coached ;

(b) if so, the action taken by Government against the teacher concerned ; and

(c) whether it is also a fact that the whole family of the Headmaster is living in Pakistan and he is carrying on espionage activities ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Smt. Soundram Ramachandran) : (a) to (c) . The Government of Rajasthan has informed that the names of 13 students of Mohammed Ali School at Biawar were changed. The original names of the students have since been restored in the School Register. The Headmaster of the School who was responsible for this action has already left the institution and hence the State Government could not take any further action in the matter.

Salaries to Language Teachers

2731. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Central Government have suggested to the State Governments to bring uniformity in the salaries of Sanskrit teachers and teachers of other languages ; and

(b) if so, the reaction of State Governments to this suggestion ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) Yes, Sir.

(b) the reactions of the State Governments are still awaited.

केरल में वामपक्षी साम्यवादी नजरबन्दी

2732. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में नजरबन्द किन्हीं वामपक्षी साम्वादियों को उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा उन्हें क्या शिकायतें है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

इस बारे में केरल सरकार द्वारा दी गई सूचना इस प्रकार है ;

1. सेंट्रल जेल विय्यूर में नज़रबन्द श्री सी० एल० वर्के जल परिवृषण (हाइडोसील) के इलाज के लिये त्रिचूर के जिला हस्पताल में भर्ती किये गए थे किन्तु बाद में उन्हें हस्पताल से छुट्टी मिल गई ।

2. सेंट्रल जेल, विय्यूर में नज़रबन्द श्री एम० ए० कृष्णन को आंतों में फोड़ के कारण 19-2-1965 को त्रिचूर के जिला हस्पताल में भर्ती किया गया किन्तु बाद में उन्हें हस्पताल से छुट्टी मिल गई ।

3. त्रिवेन्द्रम की सेंट्रल जल में नज़रबन्द श्री पी० के० कुंजाचन को गठिया के इलाज के लिये 20-3-65 को त्रिवन्द्रम के आयुर्वेद कालिज हस्पताल में भर्ती किया गया और अभी तक इलाज जारी है ।

4. सेंट्रल जल, विय्यूर में नज़रबन्द श्रीमती सुशीला गोपालन को रक्तस्राव और दर्द के कारण 27 जनवरी 1965 को त्रिचूर के प्रसूति चिकित्सालय में भर्ती किया गया और बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई । बाद में उन्हें जिला चिकित्सा अधिकारी की सलाह के अनुसार जांच और इलाज के लिये 25-3-65 को त्रिचूर के जिला हस्पताल

में भर्ती किया गया । फिर उन्हें विय्युर की सैंट्रल जेल में स्थानांतरित किया गया और विशषज्ञ-चिकित्सा और जांच के लिये 12-4-65 को मैडिकल कालिज हस्पताल में भर्ती किया गया ।

5. त्रिवेन्द्रम की सेंट्रेल जेल में नज़रबन्द श्री ज० एस० स्टनले को 1-4-65 को त्रिवन्द्रम के मैडिकल कालिज हस्पताल में जांघ के जोड़ तक आंत बढ़ने के इलाज के लिये भर्ती किया गया ।

वैज्ञानिक अनुसंधान

2733. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, पूसा की हीरक जयन्ती समारोह में खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा दिये गये भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में कुछ कमियों का उल्लेख किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इन कमियों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सौन्दरम : (क) जी, हां ।

(ख) यद्यपि खाद्य और कृषि मंत्री के व्यक्त विचार मुख्य रूप से कृषि वैज्ञानिकों की समस्याओं के बारे में थे, फिर भी जहां तक शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाले वैज्ञानिक संगठनों का प्रश्न है, वैज्ञानिकों की कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए बहतर वातावरण तैयार करने और कमियों को दूर करने की हर कोशिश की गई है ।

केरल पर्यटन केन्द्र

2734. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० ब० राघवन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन केन्द्रों में महत्वपूर्ण जल-विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिये केरल प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) 1965–66 में किन परियोजनाओं को लिये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये 1965–66 में कितनी धनराशि नियत की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) राज्य की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं निर्माण की अवस्था में हैं । इन स्थानों पर पर्यटन की सुविधाओं का विकास करने के प्रश्न की जांच की जा रही है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

बिहार के पहाड़ी ज़िलों में स्कूल

2735. **श्री ह० च० सोय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के कई पहाड़ी जिलों में, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में, इस समय माध्यमिक हाई स्कूलों तथा बहुप्रयोजनीय हाई स्कूलों की संख्या बहुत कम है, और

(ख) केन्द्र सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक राज्य में ऐसे स्कूल खोलने के लिए बिहार सरकार को सहायातार्थ कितना वित्तीय अनुदान दिया ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) राज्य सरकार से सूचना उपलब्ध की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दीजाएगी ।

(ख) नए बहुद्देशीय स्कूल तथा माध्यमिक स्कूल खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार की कोई योजना नहीं है, इसीलिए राज्य सरकार को इस विशेष कार्य के बिए कोई अनुदान नहीं दिए गए ।

मेरठ का क्षेत्रीय जनशक्ति सर्वेक्षण

2736. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री न० प्र० यादव :

क्यया **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्था, दिल्ली ने मेरठ जिले का क्षेत्रीय जनशक्ति सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और अपना सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रकाशित करा लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन कब तक प्रकाशित हो जायेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्थान ने मेरठ जिले का क्षेत्रीं जनशक्ति सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और सम्बन्धित संस्थाओं को काम चलाऊं विवरण भेज दिया है । प्राप्त होने वाली सम्मतियों के आधार पर प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया जायगा ।

पूर्व-भारत में तूफान

2737. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पूर्वी भाग में, आसाम तथा पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों में एक भीषण तूफान आया था ;

(ख) यदि हां, तो उससे कितनी क्षति हुई ; और

(ग) अधिकारियों ने पीड़ितों को क्या सहायता दी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी

Punjabi as Associated Language of Delhi

2738. **Shri Yudhvir Singh :**
Shri Lahri Singh :
Shri Bade :
Shri Daljit Singh :
Shri Chuni Lal :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it has been decided to accept Punjabi as an associate language for Delhi ; and

(b) if so, when this decision is likely to be implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L.N. Mishra) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Girls' Education in Mysore

2739. Shri Veerappa : Will the Minister of **Education** be pleased to state the expenditure incurred by the Government of India on girls' education in Mysore State during the Third Plan period so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Smt. Soundram Ramachandran) : The expenditure incurred on the special schemes relating to girls' education in Mysore State during the Third Plan upto 1963-64 was Rs. 18.20 lakhs and the anticipated expenditure for 1964-65 is Rs. 17·90 lakhs. In addition to this, part of Central allocation for General Education has also been spent on the education of girls.

युवक होस्टल

2740. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री कपूर सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 में सारे देश में कितने युवक होस्टल बनाये जायेंगे; और

(ख) 1964–65 में ऐसे कितने होस्टल बनायें गये हैं और उन पर कितना व्यय हुआ है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) और (ख). कोई नहीं।

उर्वरक कारखाना

2741. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कानपुर में या उसके निकट एक उर्वरक कारखाना स्थापित किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) इस पर कितना व्यय होगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). चौथी योजना के दौरान में कानपुर में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना की उपयुक्तता (Suitability) के प्रश्न को जांचा जा रहा है। कारखाना सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में होगा; इस प्रश्न पर यथासमय निर्णय किया जायेगा।

पूर्वी-पाकिस्तान राइफल्स द्वारा गोलीबारी

2742. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्रीमती जोहरा बेन चावडा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी-पाकिस्तान राइफल्स ने 5 अप्रैल, 1965 को आसाम-पूर्वी-पाकिस्तान सीमा पर आसाम के कछार जिले में गोविन्दपुर में सीमा पार बिना किसी कारण के गोलीबारी आरम्भ कर दी थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि 7 अप्रैल, 1965 को पूर्वी-पाकिस्तान राइफल्स के आदमी साधारण कपड़ों में उसी क्षेत्र में भारतीय राज्य-क्षेत्र में घुस आये थे;

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार से इसके विरुद्ध शिकायत की गई है ;

(घ) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा अकारण गोलीबारी करने के बाद भारतीय सेना ने क्या कार्यवाही की ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी): (क), (ग), (घ) और (ङ). आसाम के कछार जिले में पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स द्वारा गोलीबारी और घुसपैठ सम्बन्धी ध्यान दिलाऊ सूचना के उत्तर में मैंने पहले ही लोक-सभा में 12 अप्रैल, 1965 को एक वक्तव्य दे दिया है।

(ख) जी, हां।

पेट्रो-रसायनिक निगम

2743. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में पेट्रो-रसायनिक विकास को बढ़ाने तथा समन्वित करने के लिए एक निगम स्थापित करने की योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) (क) सरकारी क्षेत्र में एक पेट्रो-रसायनिक निगम की स्थापना के प्रस्ताव की केवल अफ़सर स्तर पर अब तक जांच हुई है और आगामी ब्यौरों को तैयार किया जा रहा है।

(ख) उपर्युक्त "क" को दृष्टि में रखते हुए इस स्थिति पर सूचना को बताना सम्भव नहीं होगा ।

भारत-अमरीकी महिला अध्यापिकाओं का आदान-प्रदान कार्यक्रम

2744. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत में अमरीकी शिक्षा फाउण्डेशन ने अमरीकी और भारतीय कालेजों में महिला अध्यापिकाओं के आदान-प्रदान का कार्यक्रम आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हा, तो इस कार्यक्रम मैं की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) कार्यक्रम के कब से आरम्भ होने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) (क). जी, हां।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4296/65**]

(ग) कार्यक्रम 1964 से ही लागू किया जा रहा है।

National Laboratories

2745. **Shri Kishen Pattnayak :** Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 774 on the 7th April, 1965 and state :

(a) the processes that proved successful in National Laboratories and resulted in the saving of Rs. 22 crores worth of foreign exchange ; and

(b) the names of articles whose imports were stopped as a result of which this saving has been effected ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Smt. Soundram Ramachandran) : (a) The attention of the hon. Member is drawn to the pamphlet entitled 'research for industry' which gives the list of processes etc. which have resulted in the saving of foreign exchange, copies of which are available in the Library of Parliament. Besides these, the saving in foreign exchange has been achieved through technical reports and design projects etc. Teaching and training activities, exchange of periodicals and books, consultancy services, testing etc. have also contributed towards the saving of foreign exchange.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

दिल्ली में यातायात समस्या

2746. **श्री शिव चरण गुप्त:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में जी० बी० रोड और रोशनारा रोड पर ट्रक और दिल्ली के बड़े स्टेशन के बाहर बसें खड़ी की जाती हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि भीड़-भाड़ का यह भी एक कारण है; और

(ग) यदि हां, तो यातायात की भीड़-भाड़ कम करने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) और (ख). जी, हां।

(ग) उन ट्रकों और बसों के ड्राइवरों के खिलाफ उपयुक्त कानूनी कार्यवाही की जाती है जो इन सड़कों पर रुकावट डालते पाये जाते हैं। दिल्ली की मास्टर प्लान में भाण्डागारों, गुड्स ट्रान्स्पोर्ट बुकिंग आफिसों तथा गोदामों को जी० बी० रोड तथा रोशनारा रोड से राष्ट्रीय राजपथों के नजदीक चुने गये स्थानों पर ले जाने का प्रबन्ध है। इसी तरह रोशनारा रोड की गाड़ियों की सफाई तथा मरम्मत की दुकानें भी, जो भीड़-भाड़ का मुख्य कारण हैं, निश्चित स्थानों पर ले जाई जायंगी। दिल्ली के मुख्य रेलवे स्टेशन के दोनों ओर के वर्तमान बसों के अड्डे को भी काश्मीरी गेट के बाहर वाले रोड के पास ले जाया जाना है। रेलवे गुड्स साइडिंग को निजामुद्दीन और बदरपुर जैसी दूर की जगहों पर ले जाने का भी एक प्रस्ताव है। इससे पुरानी दिल्ली में भीड़-भाड़ कम करने में काफी मदद मिलेगी।

सेवा निवृत्त प्रोफेसरों को अनुसंधान भत्ता

2747. **श्री हो० ना० मुकर्जी:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालयों के सेवा निवृत्त प्रोफेसरों तथा अन्य शिक्षा विद्वानों को अनुसंधान अथवा छात्रवृत्ति भत्ते देने की कोई व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) किस किस को यह भत्ता दिया गया है और प्रत्येक को कितना भत्ता दिया गया है?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) जी, हां। विश्वविद्यालयों, कालेजों और ऐसी संस्थाओं के, जिनकी गणना विश्वविद्यालयों में होती है, अवकाश प्राप्त व सब व्यक्ति जिन्होंने स्नातकोत्तर कक्षाओं के शिक्षण और/या शोध का विशिष्ट रेकार्ड स्थापित किया है इस योजना में आ जाते हैं।

(ख) और (ग). अपेक्षित सूचना सभा पटल पर रखे गये विवरणों में दी गई है। [पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4297/65]।

केन्द्रीय यान्त्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्था

2748. **श्री करकरे**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय यान्त्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्था ने इस वर्ष यान्त्रिक इंजीनियरी अनुसंधान और विकास केन्द्र खोलने का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) यदि हां, तो कितने केन्द्र खोले जाने की संभावना है, और

(ग) वे कहां-कहां स्थित होंगे?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सोन्दरम रामचन्द्रन) : (क) से (ग). इस वर्ष पूना, लुधियाना, भोपाल और मद्रास में (मकेनिकल) यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान और विकास केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में परमाणु अनुसन्धान केन्द्र

2749. **श्री दो० वं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के भौतिक शास्त्र विभाग में परमाणु अनुसंधान केन्द्र खोलने की योजना को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 14 मेव न्युट्रान जनरेटर स्थापित करने के उद्देश्य से भवन निर्माण के लिए 2·00 लाख रुपयों के अनुदान का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव आयोग के विचाराधीन है।

माध्यमिक शिक्षा

2750. **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मुरली मनोहर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की हां कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय नें माध्यमिक शिक्षा के मूल्योंकंन की प्रक्रिया की सिद्धान्त-तकनीक का स्थितिज्ञान कराने हेतु माध्यमिक शिक्षा के विस्तार कार्यक्रम निदेशालय के तत्वावधान में दिल्ली में नवीकर पाठ्यक्रम आयोजित किये थे;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा तथा निष्पत्तियां क्या है ; और

(ग) नवीकर पाठ्यक्रमों में किसने भाग लिया?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परिक्षाओं में किये जाने वाले सुधारों के एक भाग के रूप में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई थी जिससे माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को उद्देश्यपरक परीक्षाओं की कार्यपद्धति तथा तकनीक का शिक्षण दिया जा सके। दिल्ली में 280 से अधिक माध्यमिक विद्यालयों से एकत्र किए गए लगभग 1070 अध्यापकों को अंग्रेजी, भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित जैविकी और समाज सेवाओं का प्रशिक्षण दिया गया। अध्यापकों द्वारा विकसित की गई सामग्री में से प्रत्येक विषय से लगभग 100 उद्देश्यपरक परीक्षा मदों को आखिरी तौर से चुन लिया गया और उन्हें सब स्कूलों में वितरित कर दिया ।

अखिल भारतीय खेलकूद परिषद्

2751. श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मुरली मनोहर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् की ठीक-ठीक स्थिति क्या है तथा उस के कर्त्तव्य क्या हैं ;

(ख) उसके नियंत्रण में जो बोर्ड अथवा फैडरेशन है उन का ब्योरा क्या है; और

(ग) अखिल भारतीय खेलकूद परिषद के पास कितना धन है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) यह एक सलाहकार संस्था है और इसका काम है:—

(1) खेल कूद से संबंधित सभी विषयों पर भारत सरकार को सलाह देना ;

(2) राष्ट्रीय खेल संघों और सरकार के बीच संपर्क का कार्य करना ;

(3) राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित ऐसे खेल कूद संघों को मान्यता प्रदान करना जिन्हें वह मान्यता के लिये उपयुक्त समझे ; और (4) इसके द्वारा मान्य खेल-कूद संस्थायों को सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करना।

(ख) इसके नियंत्रण में कोई बोर्ड अथवा संघ नहीं है।

(ग) परिषद् को कोई रकम नहीं दी जाती है, किन्तु उपयुक्त (क) (4) के अनुसार जिन खेल-कूद संघों को इसने मान्यता प्रदान की है उन्हें सहायता देने के लिये परिषद् केन्द्रीय सरकार से सिफारिश कर सकती है।

हिन्दी का प्रचार

2752. { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1963-64 और 1964–65 में अहिन्दी भाषी राज्यों को हिन्दी के प्रचार के लिये राज्यवार कितनी राशि का अनुदान दिया गया, और

(ख) उक्त अवधि में इन राज्यों ने केन्दीय सरकार से प्राप्त राशि से हिन्दी के प्रचार के लिये कितना कार्य किया ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4298/65।]

पुलिस आवास योजना

2753. **श्री धर्मलिंगम** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास सरकार ने पुलिस आवास योजना के अन्तर्गत 1964-65 में ऋण के रूप में कितनी राशि की मांग की और उसको कितनी राशि दी गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

मांगी गई राशि—50 लाख रूपये ।

दी गई राशि—24.26 लाख रुपये ।

मद्रास में नाइट्रोजन उर्वरक कारखाना

2754. **श्री धर्मलिंगम** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मद्रास राज्य में नाइट्रोजन उर्वरक कारखाना स्थापित करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ किया जायेगा, और

(ग) यह कारखाना किस जगह स्थापित किया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (ग). मद्रास में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस संबंध में अन्तिम निर्णय के निकट भविष्य में होने की सम्भावना है।

आश्रम में शरणार्थी

2755. **श्री बसुमतारी** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी, 1964 से 31 मार्च, 1965 तक पूर्वी पाकिस्तान से कितने शरणार्थी आसाम में आये ;

(ख) उन में से कितने शरणार्थी आदिम जाति के हैं; और

(ग) 31 मार्च, 1965 तक कितने परिवारों को जमीन दे कर बसाया गया?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) 1-1-64 से 4-3-65 की अवधि में पूर्वी पाकिस्तान से 1,80,840 विस्थापित आसाम में दाखिल हुये हैं।

(ख) 31-10-64 तक पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले आदिम जाति के साथ विस्थापितों की संख्या 45,802 थी।

(ग) लगभग 260 परिवारों को भूमि दे दी गई है और या उन्हें स्थायी पुनर्वास स्थानों पर भेज दिया गया है।

उच्च शिक्षा के लिए रूसी सहायता

2756. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री कनकसबै :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च तथा विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में भारत-रूस सहयोग के लिये रूस से हो रहे विचार-विमर्श तथा बातचीत के फलस्वरूप कुछ समझौते हुये हैं;

(ख) यदि हां तो ऐसे समझौतों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या भारत में प्रादेशिक इंजीनियरी कालजों का परिवर्धन करने के लिये सहायता के प्रश्न पर भी विचार विमर्श हुआ है ; और

(घ) यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी हां। 1965-66 के लिये जिस भारत-रूस सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम को 7 अप्रैल, 1965 को अन्तिम रूप दिया गया था उसके एक भाग के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में भारत-रूस सहयोग पर हाल ही में मास्को में विचार विमर्श हुआ था।

(ख) कार्यक्रम के शिक्षा संबंधी भाग की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित है :—

(1) दोनों देशों के विद्यार्थियों, विद्वानों और अध्यापकों के अध्ययन, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिये छात्रवृत्तियों की व्यवस्था ;

(2) दोनों देशों में शिक्षण के लिये भाषा अध्यापकों का आदान-प्रदान और वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में रूसी अध्यापकों की व्यवस्था करना;

(3) पारस्परिक विचार-विमर्श, सम्पर्क बढ़ाने, भाषण देने, एक दूसरे देश की शिक्षा पद्धति का अध्ययन और रूस के डाक द्वारा पाठ्क्रमों तथा सांयकालीन कालेजों के संचालन का अध्ययन करने के यिये शिक्षा-शास्त्रियों और विद्वानों के विनिमय के आधार पर दौरे ;

(4) सूचना, प्रकाशनों, सामग्री और विशेषज्ञ सहायता के आदान-प्रदान के द्वारा दोनों देशों की उच्च शिक्षा की संस्थाओं और विशिष्ट निकायों के बीच संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देना ;

(5) ताशकंद विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन के पीठ स्थापित करने और इसी प्रकार किसी भारतीय विश्वविद्यालय में रूसी अध्ययन के पीठ स्थापित करना।

(ग) जी हां। भारत में इंजीनियरों के 8 क्षेत्रीय कालेज स्थापित करने के लिये रूसी सहायता हेतु रूस से विचार-विमर्श किया गया था।

(घ) विषय अभी तक इसके विचाराधीन है।

चीनी जासूसों की गिरफ्तारी

2757. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में भारत-नेपाल सीमा पर रातौल में 4 अप्रैल, 1965 को कुछ तिब्बती चीनी गुप्तचर गिरफ्तार किये गये थे ;

(ख) यदि हां तो यह किन परिस्थितियों में किया गया है; और

(ग) उन के पास क्या सामान पकड़ा गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). 3 अप्रैल, 1965 को दो तिब्बती रक्सोल पर सीमा पार करने का प्रयत्न करते हुए पकड़े गये थे।

(ग) अभी इस सूचना को सदन के सामने प्रगट करना जनहित की दृष्टि से ठीक नहीं ।

केरल राज्य सेवा तथा अधीनस्थ सेवा नियम

2758. **श्री कोया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री केरल राज्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1958 के भाग 2 के नियम (2) में निर्धारित व्यवस्थानुसार, राष्ट्रपति के शासन से अब तक केरल राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी किये गये विशेष नियमों की सूची पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय वक्फ परिषद् नियम, 1965

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेसन) : मैं श्री हुमायूं कबिर की ओर से केन्द्रीय वक्फ़ अधिनियम, 1954 की धारा 8-डी की उप-धारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय

वक्फ़ परिषद् नियम, 1965 की एक प्रति जो दिनांक 10 अप्रैल, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 558 में प्रकाशित हुए थे सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—4289/65।]**

भारत प्रतिरक्षा (अधिनियम) नियम, 1965 तथा अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु एवं निवृत्ति लाभ) तीसरा संशोधन नियम, 1965

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : मैं निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) भारत प्रतिरक्षा अधिनियम 1962 की धारा 41 के अन्तर्गत भारत प्रतिरक्षा (संशोधन) नियम, 1965, जो 31 मार्च, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1087 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—4290/65।]**

(दो) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1961 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु एवं निवृत्ति लाभ) तीसरा संशोधन नियम, 1965, जो 17 अप्रैल, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 572 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4291/65।]**

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTION S

पैंसठवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पैंसठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

बयासीवां प्रतिवेदन

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : मैं शिक्षा मंत्रालय—दिल्ली विश्वविद्यालय—के बारे में प्राक्कलन समिति का बयासीवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

छत्तीसवां प्रतिवेदन

संचार तथा संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन से, जो 27 अप्रैल 1965 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन से, जो 27 अप्रैल, 1965 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

लोक-सभा की बैठक समाप्त होने के पश्चात् सभापरिसर का उपयोग

USE OF PRECINCTS OF THE HOUSE AFTER THE RISING OF LOK SABHA

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : It is all right that no Member of the House can stay inside the House after it rises as it is under the police custody after adjournment. But under what rule a member is not even allowed to sit in the outer lawns of the Parliament House. An hon. Member of this House was dragged out of the precincts of the House in a very discourteous manner. Was it done on the basis of a written order from you ?

Such a treatment should not be meted out to an hon. Member of the House.

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : सारा मामला यह है कि हमारी जानकारी में अध्यक्ष महोदय द्वारा ऐसे कोई आदेश पास नहीं किये गये हैं कि लोक-सभा के सदस्य संसद्-भवन की चार दीवारी में नहीं आ सकते हैं या उद्यानों में नहीं बैठ सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि अधिकारियों ने स्वामी रामेश्वरानन्द को वहां से क्यों हटाया। मैं उनके वहां बैठने के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। प्रश्न यह है कि जब वे वहां बैठना चाहते थे तब उन्हें वहां से क्यों हटाया गया ?

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : The discourteous manner in which Swami Rameshwaranand was dragged outside the precincts of the House is really very shameful. Such a treatment should not have been meted out to him.

Mr. Speaker : The precincts of the House cannot be used for holding any demonstrations. Swami Rameshwaranand was at liberty to sit inside or outside the House as he liked, during the sitting of the House and even an hour after that. But if any hon. Member has to stay even beyond that he

should seek my permission and without seeking my permission he can not stay beyond an hour after the rising of the House. When Swamiji continued to sit even beyond that hour, he was asked to leave the precincts of the House. But he refused to do so on his own. According to my information, he was taken outside the precincts on shoulders and he was not dragged as has been alleged. If it is shameful to take him out on shoulders, then I am answerable for it and I had ordered to do likewise....

Shri Bagri (Hissar): I may be allowed to give a clarification. Swamiji has been humiliated.

Mr. Speaker: Hon. Members should not interrupt when the Speaker is on his legs. They should hear me patiently.

Shri Bagri: As I had given notice of a question of privilege, I should be given an opportunity to speak.

Mr. Speaker: There is no question of privilege involved in it. I had got this matter enquired. After all he was to be taken outside the precincts and some means were to be adopted for that. But I can say that he was not dragged at all. Hon. Members should rather extend their cooperation to me in maintaining discipline here. But if the hon. Members still entertain any doubt regarding some kind of maltreatment in this case, I am prepared to make further enquiries in this regard.

Shri Rameshwaranand (Karnal): Sir, on a point of order.

Mr. Speaker: There is no point of order. We should proceed further.

Shri Rameshwaranand: I wanted to speak yesterday too, but I was not allowed to say anything. I am rising on a point of order.

Mr. Speaker: There is no point of order. One item has finished and we are going to the next item. There can be no point of order in the vacuum.

Shri Rameshwaranand: You are not allowing me to raise my point I am leaving the House in protest.

(इसके पश्चात श्री रामेश्वरानन्द सभा भवन से उठ कर चले गए।)

(Shri Rameshwaranand then left the House)

कच्छ सीमा पर पाकिस्तान के सशस्त्र बलों द्वारा बार-बार और लगातार किए जा रहे आक्रमणों से उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रस्ताव

MOTION REGARDING SITUATION ARISINGOUT OF REPEATED AND CONTINUING ATTACKS BY ARMED FORCES OF PAKISTAN ON KUTCH BORDER

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कच्छ सीमा पर पाकिस्तान के सशस्त्र बलों द्वारा बार-बार और लगातार किये जा रहे आक्रमणों से उत्पन्न स्थिति पर विचार किया जाये।"

[श्री लाल बहादुर]

हमारे जवान हमारी सीमाओं की प्रतिरक्षा अनुकरणीय शौर्य से कर रहे हैं (**करतलध्वनि**) और मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह सभा और इस देश के सारे लोग दृढ़ता से उनके साथ हैं, (**करतलध्वनि**) तथा हम अपनी क्षेत्रीय अखण्डता को दी गयी चुनौती का मुकाबला करने के लिये हर बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिये तैयार हैं (**करतलध्वनि**)

पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान गोलाबारी करता रहा है और भारत-पाक सीमा पर कई स्थानों पर उससे मुठभेड़ हुई है। हमारे जवानों ने इन सभी स्थानों पर प्रभावशाली प्रतिरक्षात्मक कार्यवाही की है । कुछ समय पूर्व पाकिस्तानी सैनिकों को कच्छ-सिन्ध सीमा के निकट एक पगडंडी पर देखा गया । जब हमारे जवानों ने उन्हें चुनौती दी तो उन्होंने दावा किया कि वह पगडंडी पाकिस्तानी राज्य क्षेत्र में है जिस पर वे चल रहे थे, यह भी देखा गया कि पाकिस्तान ने कंजरकोट पर कब्जा कर लिया है और वहां पर एक स्थायी चौकी भी स्थापित कर ली है । स्थल (ग्राउंड) नियमों की कंडिका 3 के अनुसार राजकोटरेंजर के पुलिस उपमहा निरीक्षक ने यह मामला पश्चिमी पाकिस्तान रेंजर के महानिदेशक से उठाया और उन्हें इस स्थितिपर विचार करने के लिये एक बैठक बुलाने का सुझाव दिया । पश्चिमी पाकिस्तान रेंजर के महानिदेशक इस बैठक में उपस्थित नहीं हुए परन्तु उन्होंने अपने स्थानीय कमांडर को भेजा । परन्तु इस बैठक से कोई परिणाम न निकला और हमारे सैनिकों तथा पाकिस्तानी सैनिकों के बीच मुठभेड़ होती रही ।

9 अप्रैल के दिन प्रातःकाल सरदार चौकी स्थित हमारी सीमा चौकी पर भारी तोपों तथा एम० एम० जी० गोलाबारी से आक्रमण किया गया जिसके बाद 25 पौंड की तोपों से तोपखाने द्वारा गोलाबारी शुरू कर दी गयी तथा उसकी आड़ में पाकिस्तान की इन्फैन्ट्री ब्रिगेड 51 की नियमित सेना की दो बटालियनें इस चौकी की ओर बढ़ीं । इस मुठभेड़ का ब्यौरा गृह-कार्य मंत्री ने 12 अप्रैल को दिये गये अपने वक्तव्य में पहले ही सभा को दे दिया था । पाकिस्तानी बन्दियों से बरामद हुए दस्तावेजों तथा उन से की गई पूछताछ से स्पष्ट हो गया है कि यह आक्रमण पहले से ही सोचा-विचारा हुआ तथा पूर्व-आयोजित था। पाकिस्तानी सेना ने हमारी चौकी पर हमले की योजना मार्च के दूसरे सप्ताह में बनाई थी तथा सैनिकों का स्थानान्तरण इस तारीख के पश्चात् आरम्भ हुआ । ऐसा प्रतीत होता है कि हमला करने के आदेश 7 अप्रैल को जारी किये गये थे और इस प्रकार 9 अप्रल प्रातःकाल हमला कर दिया गया । तभी से कच्छ-सिन्ध सीमा के दक्षिण में हमारे राज्य क्षेत्र के कई स्थानों पर पाकिस्तान द्वारा अधिक जोरदार हमले जारी हैं । 24 अप्रैल को प्वाइंट-84 पर हमारी चौकी पर प्रातः काल गोलाबारी की गई और तत्पश्चात् पाकिस्तानी इन्फैन्ट्री ने टैंको तथा अन्य बख्तरलैस सैनिकों ने उस चौकी पर हमला कर दिया। 26 अप्रैल को पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने टैंकों तथा अन्य बख्तरबन्द गाड़ियों से हमारी बियारबेट सीमान्त चौकी पर हमला कर दिया । यह हमले अब भी जारी हैं ।

पाकिस्तान द्वारा की गई यह सशस्त्र कार्यवाही स्पष्टतया अतिक्रमण की कार्यवाही है। उन्होंने सीमा के दक्षिण में 648 मील के अन्दर तक हमारे उस राज्यक्षेत्र पर हमला किया है जो कि पाकिस्तान के अपने कथनानुसार कभी उनके कब्जे में नहीं था । पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपने एक वक्तव्य में यह स्वीकार किया है "कि झगड़ा इसलिये उत्पन्न नहीं हुआ कि वहां सीमा का रेखांकन

नहीं किया गया बल्कि इसलिये कि वह विवादग्रस्त राज्यक्षेत्र भारत के प्रतिकूल कब्जे में था।" अन्य शब्दों में पाकिस्तान ने एक ऐसे राज्यक्षेत्र पर हमला किया है जो पहले उसके कभी कब्जे में नहीं था। अतः पाकिस्तान स्वयं-निन्दित है। उसने यथा पूर्व स्थिति को बदलने के लिये बल का प्रयोग किया है जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर तथा भारत-पाक सीमा करार, 1960 के अन्तर्गत बनाये गये स्थल नियमों के प्रतिकूल है। उस समय भी जब कि इस मामले को निबटाने के लिये राजनयिक स्तर पर बातचीत चल रही थी, पाकिस्तान ने हमारी चौकियों पर टैंकों तथा तोपखाने से लैस होकर अपने हमले को और अधिक सख्त कर दिया।

19 अप्रैल को हमारे विदेशी सचिव ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को इस बारे में एक सुझाव दिया जो कि लगभग वही था जो कि कुछ दिन पूर्व पाकिस्तान के विदेशी कार्यालय ने कराची स्थित हमारे उच्चायुक्त को दिया था, अर्थात् कि पहले युद्ध विराम होना चाहिये तथा तत्पश्चात् इसका फैसला करने तथा युद्धपूर्व यथास्थिति को पुनः पैदा करने के लिये शासकीय स्तर पर बातचीत होनी चाहिये और बाद में इस सीमा प्रश्न पर चर्चा दोनों सरकारों के बीच उच्च स्तर पर होनी चाहिये। 24 अप्रैल को प्रातःकाल, पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने हमारे वैदेशिक-कार्य सचिव को एक वैकल्पिक सुझाव दिया जिसके अनुसार युद्ध विराम के पश्चात् दोनों, भारत और पाकिस्तान, कुछ ऐसे क्षेत्रों से असैनिक अथवा सैनिक सशस्त्र बलों को हटायें, जिनको वह विवादग्रस्त राज्यक्षेत्र बताते हैं। परन्तु ऐसा सुझाव करने से पूर्व ही उस प्रातः को पाकिस्तान ने प्वाइंट-84 पर स्थित हमारी चौकी पर भारी तोपखाने से भारी हमला कर दिया।

इस कालावधि में पाकिस्तानी अधिकारी परस्पर विरोधी वक्तव्य देते रहे हैं। 15 फरवरी 1965 को उन्होंने कहा कि उन्होंने कंजरकोट पर कब्जा नहीं किया और वे कंजरकोट के दक्षिण में उस पगडंडी पर गश्त लगाते रहे हैं जो कि उनके अनुसार सुराय तथा डिंग को मिलाने वाली पुरानी सीमा-शुल्क पगडंडी है। हमारे 18 फरवरी, 1965 के विरोध पत्र के उत्तर में पाकिस्तान सरकार ने अपने नोट में कहा कि कंजरकोट दुर्ग पर इन्डसरेंजरस ने कब्जा नहीं किया है। इस समय पाकिस्तान ने न केवल कंजरकोट दुर्ग पर ही कब्जा कर रखा है परन्तु वे सीमा-शुल्क पगडंडी तक गश्त लगाने के अपने दावे से कहीं अधिक क्षेत्र पर अपना दावा बतला रहे हैं। पाकिस्तान अब कच्छ सिन्ध सीमा के दक्षिण तथा 24वीं पैरलल के उत्तर में काफी बड़े क्षेत्र पर अपना दावा जता रहा है। पाकिस्तान का यह दावा है कि कच्छ का रन आन्तरिक समुद्र है और इसलिये पाकिस्तान उसके आधे भाग का अधिकारी है। मैं यह स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि कच्छ का रन आन्तरिक समुद्र नहीं है और न ही कभी इसे ऐसा माना गया है। पाकिस्तान बनने से बहुत पहले ही तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने 1906 में औपचारिक रूप से यह फैसला किया था कि कच्छ के रन को एक झील अथवा आन्तरिक समुद्र कहने की बजाय इसे दलदल कहना अधिक अच्छा होगा। यह एक अविवादग्रस्त बात है कि कच्छ का रन दलदल है। वहां पर वे सभी वनस्पति और जन्तु पाये जाते हैं जो कि दलदल में मिलते हैं। वास्तव में होता यह है कि वर्षाकाल में निचान वाले क्षेत्रों में समुद्र तथा उन नदियों का पानी, जिनमें बाढ़ आ जाती है, आ जाता है और इस प्रकार यह पानी मई के मध्य से लेकर अक्तूबर के अन्त तक वहां पर रहता है। अन्यथा शेष महीनों में अधिकांश रूप में यहां पर भूमि खुश्क तथा आंशिक रूप से दलदल वाली होती है।

यद्यपि कच्छ-सिंध सीमा का सीमांकन नहीं हुआ है, परन्तु इस सीमा को 1872 से 1943 तक के मानचित्रों में भली प्रकार दिखाया गया है। भारत का विभाजन होने से पूर्व

[श्री लाल बहादुर]

यह ब्रिटिश-भारतीय प्रांत सिंध और कच्छ राज्य को अलग अलग करती थी। चूंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय सीमा नहीं थी इसलिये इसका सीमांकन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। भारत का विभाजन होने से पूर्व के 75 वर्षों के सरकारी दस्तावेजों में इसकी सविस्तर व्याख्या उल्लिखित है। 15 अगस्त, 1947 से पूर्व अविभाजित भारत के सरकारी मानचित्रों में दिखाई गई सीमा पर आपत्ति नहीं की जा सकती। मार्च, 1907 में प्रकाशित सिन्ध प्रान्त के सरकारी राजपत्र में 1909 में छपे बम्बई प्रेजीडेंसी के भारत के राजपत्र में तथा 1908 में ब्रिटिश सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इण्डिया द्वारा प्रकाशित भारत के शाही राजपत्र में यह स्पष्ट रूप में बताया गया है कि कच्छ का रन सिंध प्रांत से बाहर है। 1937, 1939 तथा 1942 के तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार के राजनैतिक विभागों के सभी दस्तावेजों में कच्छ की रन को वैस्टर्न इण्डिया स्टेट्स एजेंसी के अन्तर्गत दिखाया गया है और इसे सिंध प्रान्त के अन्दर कभी भी नहीं दिखाया गया। जैसा कि सभा को पता है कि वैस्टर्न इण्डिया स्टेट्स एजेंसी समूचे रूप में भारत में शामिल हो गई थी। इन सब चीजों से पता चलता है कि सिंध प्रान्त तथा कच्छ के बीच सीमा सम्बन्धी किसी झगड़े का कोई आधार ही नहीं है।

जब से उन्होंने यह आक्रमण आरम्भ किया है तभी से हमने पाकिस्तान को बात-चीत करने के कई सुझाव दिये हैं। उदाहरण के तौर पर हमने सुझाव दिया था कि इस सीमा का सीमांकन करने के लिये दोनों देशों के महा-सर्वेक्षक मिलें परन्तु पाकिस्तान ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। हमने 18 फरवरी के अपने नोट में सुझाव दिया था कि जिस स्तर पर पाकिस्तान सरकार उचित समझे उसी स्तर पर दोनों देशों के प्रति-निधियों के बीच एक बैठक बुलाई जानी चाहिये और बाद में और भी कई सुझाव दिये, परन्तु इन प्रयत्नों के बावजूद पाकिस्तान ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई 13 अप्रैल, 1965 को पाकिस्तान सरकार ने युद्ध-बन्दी, पूर्व स्थिति को पैदा करने के लिये दोनों सरकारों के बीच बैठक बुलाने तथा उच्चस्तरीय बैठक बुलाने के त्रि-सूत्तीय प्रस्ताव को रखा था, भारत सरकार ने उनके इस सुझाव की दूसरे दिन ही मान लिया था परन्तु खेद है कि पाकिस्तान सरकार अपने प्रस्ताव से भी पीछे हट गई।

19 अप्रैल को भारत सरकार ने फिर कहा कि युद्धविराम का प्रस्ताव तुरन्त मान लिया जाये परन्तु 23 अप्रैल को पाकिस्तान ने नये प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये जिन के अनुसार भारती सेना को उस क्षेत्र से पीछे हटना है जिस को पाकिस्तान विवाद ग्रस्त क्षेत्र कहता है। परन्तु वास्तव में वह भारतीय क्षेत्र है। मैंने सभा को पूरी स्थिति बता दी है और पाकिस्तान द्वारा बल की कार्यवाही ब्यौरा भी दिया है। पाकिस्तान समाचार पत्र तथा नेता भारत के प्रति झूठा प्रचार कर रहे हैं। हमें इन से बहुत दुख है। भारत सदैव शान्ति का इच्छुक रहा है। भारत अपने आर्थिक विकास में लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में वह युद्ध के बारे में कैसे सोच सकता है। परन्तु हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन ने भारत के विरुद्ध गठबन्धन कर लिया है। भारत इस समस्या के प्रति पूर्णरूप से सतर्क है। वह अपना कर्त्तव्य ठीक प्रकार से निभायेगी। भारत का प्रत्येक व्यक्ति आज देश

की प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा के लिये हर प्रकार का बलिदान करने को तैयार है। हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। हमें विचार करना है कि हम किस मार्ग पर चलें। हम शान्ति के मार्ग पर जाना चाहते हैं परन्तु पाकिस्तान को अपनी आक्रामक गतिविधियां छोड़नी होंगी। भारत पाकिस्तान सीमा के सीमांकन में कोई बड़ी बात नहीं है इसे दोनों देशों के विशेषज्ञ निर्धारित कर सकते हैं। पाकिस्तान को यथापूर्व स्थिति पर चले जाना चाहिये। कच्छ सीमा पर पाकिस्तान को बहुत सुविधायें प्राप्त हैं। हमारे सैनिक जहां पर हैं वहां पानी भर जायेगा और उन्हें वहां से हटना होगा। यदि पाकिस्तान अपनी इस प्रकार की कार्यवाहियां नहीं छोड़ता तो हमें स्थिति सेना को सौंपनी होगी। और सेना इससे निपटेगी। हमें मित्र देशों ने युद्धविराम के लिये कहा है। हम इस के लिए तैयार हैं परन्तु हमें अन्य बातों के लिये तैयार रहना है। मैंने ये बातें पूरी जिम्मेदारी के साथ कहीं हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण समय है। इस समय सब कुछ सम्भव है। हमारी सेना ने बहुत वीरता का परिचय दिया है।

मैं आशा करता हूं कि पाकिस्तान अपने 13 अप्रैल के प्रस्तावों के अनुसार युद्ध विराम मान लेगा। उन प्रस्तावों को हमने स्वीकार कर लिया है। इस समय सभी भारतवासी देश की अखण्डता की रक्षा में योगदान देने के लिये तैयार हैं। मेरी उन से अपील है सभी को अपनी पूरी शक्ति से कार्य करके एकता का एक प्रमाण प्रस्तुत करना है। मैं इस सदन से अनुरोध करता हूं कि इस संकट पूर्ण समय में सरकार को पूरा सहयोग दे।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कच्छ सीमा पर पाकिस्तान के सशस्त्र बलों द्वारा बार-बार और लगातार किये जा रहे आक्रमणों से उत्पन्न स्थिति पर विचार किया जाये।"

कुछ स्थानापन्न प्रस्ताव हैं जो प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

Shri Sarjoo Pandey (Rassa) : Sir, I beg to move :

1. That for the original motion the following may be substituted namely:—

"This House, having considered the situation arising out of the repeated and continuing attacks by the armed forces of Pakistan on the Kutch border, urges upon the Government to have the aggression on Indo-Pak border by Pakistanis vacated forth with." (1)

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि मूल संकल्प के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात्:—

"कच्छ सीमा पर पाकिस्तान के सशस्त्र बलों द्वारा बार-बार और लगातार किए जा रहे आक्रमणों से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के पश्चात इस सभा की यहा राय है कि सरकार देश की सीमाओं की रक्षा करने में असफल रही है और यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि आक्रमणकारियों को तत्काल निकाल बाहर करने के लिए सुदृढ़ कदम उठाए।" (2)

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Sir, I beg to move:

That for the original motion, the following be substituted, namely:—

"This House , having considered the situation arising out of the repeated and continuing attacks by the armed forces of Pakistan on the Kutch border, is of the opinion that the Government have failed to face situation and tension created by Pakistan on the Indo-Pak border and urges upon the Government to leave no stone unturned to maintain the territorial integirty of the country." (3)

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि मूल संकल्प के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात् :—

"कच्छ सीमा पर पाकिस्तान के सशस्त्र बलों द्वारा बार बार और लगातार किए जा रहे आक्रमणों से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के पश्चात् और देश की सीमाओं की अनुलंघनीयता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता की अपनी पूरी शक्ति से रक्षा करने के सभी प्रयत्नों में एक होकर जुट जाने के लिए देश की जनता से अनुरोध करते हुए यह सभा खेद प्रकट करती है कि भारत-पाक सीमा की रक्षा के प्रश्न के संबंध में अब तक सरकारी नीति में दृढ़ता तथा स्थिरता का और राजनयिक तथा सैनिक स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिन्ता का नितान्त अभाव रहा है।"(4)

श्री फ्रेंक एन्थनी (नाम निर्देशित-आंग्लभारतीय) : श्रीमान मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि मूल संकल्प के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात् :—

"कच्छ सीमा पर पाकिस्तान बलों द्वारा बार-बार और लगातार किये जा रहे आक्रमणों से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के पश्चात् इस सभा की यह राय है कि भारत को सीमा आक्रमणों में उलझाये रखने को चीन-पाकिस्तान की स्पष्ट युद्धनीति का सामना करने के लिए सरकार एक दृढ़ नीति निश्चित करे।"(6)

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I beg to move:

That for the original motion, the following be substituted , namely:—

"This House, having considered the situation arising out of the repeated and continuing attacks by the armed forces of Pakistan on the Kutch border, is of the opinion that there should be neither any cease-fire by Indian forces nor any armistice between India and Pakistan without taking back every inch of Indian territory." (7)

Shri Bagri (Hissar) : Sir, I beg to move:

That for the original motion, the following be substituted, namely:—

"This House , having considered the situation arising out of the repeated and continuing attacks by the armed forces of Pakistan on the Kutch border, severely criticises the Government for,—

(a) its failure to take stringent and retaliatory measures to face the persistent attacks on the long borders of India contiguous with China and Pakistan,

(b) declaring the territory under aggression as disputed and barren land,

(c) failure to declare the policy of not resorting to ceasefire without recovering every inch of Indian territory while always agreeing to enter into negotiations with Pakistan on the basis of Indo-Pak confederation, and

(d) failure to display the requisite will power to face the aggression and to create the required morale in the public." (8)

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

(एक) कि मूल संकल्प के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात् :—

"कच्छ सीमा पर पाकिस्तान के सशस्त्र बलों द्वारा बार-बार और लगातार किये जा रहे आक्रमणों से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के पश्चात यह सभा हमारे सशस्त्र बलों के जवानों और अफसरों और पुलिस बल के हमारी सीमाओं की रक्षा करते समय वीरतापूर्ण मुकाबले की प्रशंसा करती है और जिन शहीदों ने अपनी मातृभूमि के सम्मान और एकता की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया है, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है, और भारत की पवित्र भूमि से आक्रांता को खदेड़ कर बाहर निकालने के लिए भारतीय जनता के दृढ़ निश्चय का समर्थन करती है।" (9)

(दो) कि मूल संकल्प के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात् :—

"कच्छ सीमा पर पाकिस्तान के सशस्त्र बलों द्वारा बार-बार और लगातार किये जा रहे आक्रमणों से उत्पन्न स्थिति पर विचार करते हुए यह सभा इस बात पर खेद प्रकट करती है कि सरकार :

(क) कच्छ के क्षेत्र को छीन लेने के बारे में पाकिस्तान के कुचक्रों और योजनाओं का पहले से अनुमान लगाने में ;

(ख) पाकिस्तान की चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त सैनिक तैयारियां करना ;

(ग) पाकिस्तानी सेनाओं को उन नगरों और चौकियों से जो उन्होंने जबर्दस्ती हथिया लिये हैं, निकाल बाहर करने में;

[श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी]

(घ) आक्रान्ता को दंड देने और राष्ट्रीय सम्मान बनाये रखने की स्पष्ट और दृढ़ नीति बनाने; और

(ङ) राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में चीन-पाकिस्तान गठबंधन के सैनिक प्रभाव का अनुमान लगाने में असफल रही है।" (10)

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : श्रीमान मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि मूल संकल्प के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये ; अर्थात्:—

"कच्छ सीमा पर पाकिस्तान के सशस्त्र बलों द्वारा बार-बार और लगातार किये जा रहे आक्रमणों से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के पश्चात इस सभा की यह राय है कि सरकार स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त और तुरन्त कार्यवाही करने में असफल रही है और यह सभा सरकार से आग्रह करती है—

(क) भारतीय राजयक्षेत्र पर कब्जा किये हुए आक्रमणकारियों को अविलम्ब बाहर खदेड़ा जाँये ; और

(ख) जब तक पाकिस्तान के सशस्त्र बल तुरन्त भारतीय राज्य क्षेत्र से वापस न लौट जाय तब तक पाकिस्तान के साथ कोई सम्मेलन अथवा बातचीत न की जाये।"(11)

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि मूल संकल्प के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात् :—

"कच्छ सीमा पर पाकिस्तान के सशस्त्र बलों द्वारा बार-बार और लगातार किये जा रहे आक्रमणों से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के पश्चात इस सभा की यह राय है कि सरकार ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में परिवर्तन करने की जो नीति अपनायी है उसके कारण देश को विनाश और अपमान का सामना करना पड़ रहा है और पाकिस्तान की चुनौती का सामना करने के लिए वर्तमान नीति के स्थान पर दृढ़, उचित और तर्कबद्ध नीति बनाने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये।"(12)

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रस्ताव और स्थानापन्न प्रस्ताव अब सभा के समक्ष हैं ।

श्री रंगा (चित्तूर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे हर्ष है कि प्रधान मंत्री ने इस सभा को विश्वास में लेकर, देश को इस विकट स्थिति से अवगत करा दिया है। यदि हम से यह पूछा जाए कि आप अपने देश की गरीबी तथा उसकी स्वतंत्रता में से किसे चुनना अधिक पसन्द करेंगे तो निस्सन्देह हम स्वतंत्रता को वरीयता देंगे और उस की रक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा कुर्बानी करेंगे। इसके साथ-साथ इस बात पर भी विचार करना युक्तिसंगत होगा कि हम इस विकट स्थिति में कैसे फंस गये

हैं, ताकि हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भविष्य में किये जाने वाले उचित उपायों का अनुमान लगा सकें ।

प्रधान मंत्री महोदय ने यह ठीक कहा है कि पाकिस्तानियों ने हम पर बिना कारण प्रत्यक्ष आक्रमण किया है और हमारी सेनाओं तथा हमारे क्षेत्र पर हमला किया है । संसार में—संयुक्त राष्ट्र और अन्यत्र कहीं भी यदि आज कोई सत्यात्मा जीवित है तो उसे अवश्य ही हमारे दावे का समर्थन करके पाकिस्तान से बिना शर्त तुरन्त पीछे हट जाने के लिए कह कर—हस्तक्षेप करना चाहिए । किन्तु संयुक्त राष्ट्र के गत 17–18 वर्ष के अनुभव के आधार पर हमारी सरकार को भली भांति यह जानकारी होनी चाहिए कि इस प्रकार की भावना वाली आज कोई सत्ता विद्यमान नहीं है । इसलिए सरकार का यह कर्तव्य था कि वह हर संभव तरीके से सैनिक और राजनयिक दृष्टि से पूरी तैयारी करते रहती ताकि आज हम इस आकस्मिकता का सफलतापूर्वक सामना करने में सफल होते । मुझे यह शंका है कि हमारी सरकार अब भी आवश्यक कार्यवाही में नहीं जुटी हुई है ।

प्रधान मंत्री महोदय ने विरोधी-दलों के नेताओं को बुला कर उस सम्मेलन में बताया था कि सरकार को पाकिस्तान द्वारा आक्रमण के इरादों का पता जनवरी के आरम्भ में ही लग गया था । वे कंजरकोट में पहले ही आकर जम गये थे । क्या यह उचित नहीं था कि उसी समय सैनिक सहायता से वहां उचित कार्यवाही की गई होती ?

सरकार को यह जानकारी पहले से थी कि वहां पाकिस्तानी सेनाओं का भारी संख्या में जमाव हो गया है और उन्होंने वहां हवाई अड्डे भी बना लिये हैं और उस क्षेत्र में सड़कों का भी निर्माण कर लिया है और हमारी स्थिति के मुकाबले में उनकी स्थिति उस क्षेत्र में कहीं अधिक अच्छी है । इतनी जानकारी होने के बावजूद भी सरकार उस क्षेत्र को केवल चन्द पुलिस की टुकड़ियों के भरोसे पर छोड़ती रही । केवल दो दिन हुए जब कि यह सीमा-क्षेत्र सेना को सौंपा गया है । अब सरकार यह कहती है कि वह कठिन स्थिति में फंसी हुई है क्योंकि कच्छ का रन शीघ्र ही जल-मग्न होने वाला है इसलिए उसे अपने आदमियों की वहां पर रक्षा करने के लिये विशेष कदम उठाने पड़ेंगे । किन्तु में यह पूछता हूं कि क्या सरकार के पास कच्छ के रन के जलमग्न होने वाले छोर तक आवश्यक संचार-साधनों की व्यवस्था है ? सरकार की नीति केवल प्यास लगने पर ही कुआं खोदने की रही है । अब तक सरकार सोई पड़ी थी । अब सरकार राष्ट्रीय एकता के नाम पर हमें भी जगाकर आक्रान्ताओं को भगाने का प्रयत्न कर रही है ।

प्रधान मंत्री महोदय ने बताया है कि पाकिस्तान उसके साथ की हमारी सभी सीमाओं पर कुछ-न-कुछ गड़बड़ करता रहा है । पाकिस्तान ने जब यह देखा कि चीन के साथ हमारे सम्बन्ध बिगड़ते जा रहे हैं तो उसने अवसर का लाभ उठा कर, अवांछनीय रूप से, भारत के प्रति बुरे इरादे रखते हुए, राजनैतिक तथा राजनयिक रूप से चीन के साथ बातचीत करना आरम्भ कर दिया और उसमें वह सफल भी हो गया । हमारी गलती न होते हुए भी चीन की मित्रता से हमें हाथ धोना पड़ा किन्तु पाकिस्तान आज चीन का मित्र बना हुआ है । आज वह भी संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन की सदस्यता के लिये लड़ रहा है । वियतनाम में साम्यवादी आक्रमण के विरुद्ध प्रजातंत्र के लिये चल रहे संग्राम में हमारी तरह वह भी अमरीका की निन्दा कर रहा है । इससे वह चीन का और भी समर्थन प्राप्त करके उसके साथ अपनी मित्रता बढ़ा रहा है । पाकिस्तान, तुर्की, इन्डोनेशिया आदि

[श्री रंगा]

देशों से भी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये हुए है । हम मलेशिया के साथ भी अपनी मित्रता नहीं निभा सके । आज अमरीका तथा इंगलैंड की हमारे प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, हमारी नीति अच्छी प्रकार समझने के बाद आज वे भी केवल तटस्थता का रवैया अपना कर शान्ति से मामला सुलझाने के लिए कह रहे हैं । इससे पाकिस्तान को लाभ हुआ है ।

चीन को भी अफ्रीकी देशों से मित्रता बनाने में सफलता मिली है, परन्तु जहां तक हमारा सम्बन्ध है, अरब देशों के सिवाय, जिनकी मित्रता को हम इजराइल से बिगाड़ कर बनाये हुए थे, अन्य देश हमारे मित्र नहीं थे । हमारे राजदूतों के आश्वासनों पर सरकार हमें निर्भर रखना चाहती है । किन्तु वे जिस प्रकार की सेवा तथा व्यवहार कर रहे हैं, वह बहुत खेदजनक है । इस समय एशिया तथा अफ्रीका में हमारे कोई विश्वासपात्र तथा सक्रिय मित्र नहीं हैं । बर्मा—भयभीत है—और श्रीलंका की सरकार में हाल ही में हुए परिवर्तनों के बावजूद भी वह चीन से मित्रता बनाये रखने के लिये चिंतित है । इस प्रकार आज हम मित्रहीन हैं । हम अपने स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू तथा वर्तमान प्रधान मंत्री की दोषपूर्ण नीति के परिणामस्वरूप दूसरों से अलग हो गये हैं । हमें इतिहास का स्मरण रहना चाहिये और उसी समय से अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिये था जब से हमें मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है ।

पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम से अधिक शक्तिशाली बन गया है और वह साम्यवादी चीन का गहरा मित्र बन गया है । हमारे देश के वामपक्षी साम्यबादी भी चीन तथा पाकिस्तान दोनों के लिए बल के अतिरिक्त स्रोत हैं और चीन के अलावा पाकिस्तान के और भी कई ऐसे मित्र हैं जो समय-समय पर अपने अस्तित्व का प्रमाण काश्मीर, दिल्ली तथा अन्य कई स्थानों पर बम-विस्फोटों द्वारा देते रहते हैं ।

जब हम इतने निर्बल हो चुके हैं तो सरकार का कर्तव्य है कि वह अब भी अपनी कुछ मिथ्या धारणाओं तथा विचार और पहले के अविचारपूर्ण निर्णय तथा अपनी वर्तमान कार्यप्रणाली का परित्याग करे । प्रतिरक्षा मंत्री के ऐसे वक्तव्य कि हम चीन और पाकिस्तान दोनों का मुकाबला करने के लिए काफी समर्थ हैं—उचित नहीं हैं । यदि कहीं ऐसा हो ही गया तो पता नहीं रूस क्या रवैया अपनायेगा ।

में, अपनी मातृभूमि की अखण्डता तथा उसकी सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले जवानों, अफसरों तथा सुसज्जित सैनिकों के प्रति अपनी निष्ठापूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । में प्रधान मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह देश की रक्षा करने तथा उस को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायें जिससे कि उन्हें देश का सक्रिय सहयोग मिल सके । हमें यह विश्वास नहीं होता कि वर्तमान सरकार अथवा शासी दल के पास वह नैतिक बल है जिस द्वारा वह उदार, दूरदर्शी तथा साहसपूर्ण नेतृत्व प्रदान कर सके जिसकी केवल आज अथवा कल ही नहीं अपितु तब तक आवश्यकता है जब तक कि चीन तथा पाकिस्तान से खतरा बना हुआ है ।

प्रधान मंत्री को समय-समय पर विरोधी दलों के नेताओं को विश्वास में लेकर उनसे बात-चीत करनी चाहिये ताकि वे वास्तविक स्थिति से उचित रूप से अवगत होकर सरकार को अपना सहयोग दे सकें ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता—मध्य) : अध्यक्ष महोदय, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आज हम घोर संकट का सामना कर रहे हैं। यह हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है और हमें इसमें सफल हो कर दिखाना है।

भारत ने स्वतंत्रता के बाद से ही सहनशीलता की नीति का अनुसरण किया है तथा पाकिस्तान को अपना मित्र देश समझा किन्तु पाकिस्तान की ओर से आरम्भ से ही निरन्तर उत्तेजनात्मक कार्यवाहियां की जाती रही हैं। अभी हाल में पाकिस्तान ने उत्तरपूर्व में अनेक बार गोलाबारी की और कई बार सीमा का उल्लंघन किया। अन्त में यहां तक कि कच्छ के कुछ क्षेत्र में पाकिस्तान ने भारी आक्रमण कर दिया।

पिछले सप्ताह जब मैं गजरात में था तो मझे वहां पर पाकिस्तान की गतिविधियों का कुछ पूर्वाभास मिला था। फिर भी सरकार ने सतर्कता से कार्य नहीं किया। इस समय हमारे लिए यही उचित है कि हम पिछली गलतियों की छानबीन न करके उचित कार्यवाही करें। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम एक होकर दृढ़ संकल्प करें कि पाकिस्तान द्वारा भारतीय भूमि पर सैनिक दबाव और चालबाजी से अनुचित दावों को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। यदि पाकिस्तान हमें अपमानित करना चाहता है और हमारी भूमि पर अनचित कब्जा करना चाहता है तो हमें उसे ऐसा सबक सिखाना चाहिए जिसे वह हमेशा याद रखे। हम सदा समझौता करने के लिए तैयार हैं किन्तु यह समझौता अपने गौरव तथा आत्मसम्मान के बदले में कभी भी नहीं करेंगे। आज हम देश की अखडता बनाए रखने तथा बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करने के लिए दृढ़ निश्चय होकर तैयार हैं।

यह बात सर्वविदित ही है कि पाकिस्तान हमारे विरुद्ध अमरीका द्वारा दिये गये हथियारों का प्रयोग कर रहा है। आज यह समझना आवश्यक है कि पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा राजनैतिक हथियार आंग्ल-अमरीकी साम्राज्यवादियों चें साथ सांठ-गाठ है। पाकिस्तान इस हथियार का प्रयोग भारत के विरुद्ध कर रहा है।

मौलाना अबुलकलाम आजाद ने अपनी पुस्तक 'इंडिया विन्स फ्रीडम' में, जो उनके मरणोपरान्त प्रकाशित हुई है, स्पष्ट लिखा है कि अंग्रेजों द्वारा पाकिस्तान बनाने का उद्देश्य यह है कि वे उसे भारत के विरुद्ध अपना अड्डा बनाना चाहते थे। सरकार को यह बात अच्छी तरह समझ लेंनी चाहिये कि ब्रिटेन तथा अमरीका हमारी स्वतंत्रता, स्वतंत्र विदेशी नीति तथा स्वतंत्र रूप से हमारे आर्थिक विकास को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वे हिन्द महासागर में अपने परमाणु अड्डे बना कर हम पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। हमें यह बांत भी कतई नहीं भूलनी चाहिए कि संयुक्त राज्य अमरीका अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पाकिस्तान का सब से बड़ा संरक्षक है। यह बात इस से और भी स्पष्ट हो जाती है कि उसने पाकिस्तान को निरंतर आधुनिक हथियार दिये हैं जब कि भारत को आधुनिक हथियार देने से मना कर दिया। हमारी सरकार के पास इस बात के निश्चित प्रमाण हैं कि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध लड़ाई में सदा अमरीकी हथियारों का प्रयोग करता है। अमरीका ने भारत को दिये इस वचन की प्रत्यक्ष रूप से अवहेलना की है कि पाकिस्तान को दिए गये हथियार भारत के विरुद्ध प्रयोग नहीं किये जायेंगे। उनका प्रयोग केवल साम्यवादी देशों के विरुद्ध ही किया जायेगा। जहां तक अमरीका द्वारा भारत को दिये गये हथियारों का सम्बन्ध है, अमरीकी सैनिक अधिकारी भारत में इस बात की जांच करने के लिए आते रहते हैं कि कहीं हम अमरीका द्वारा दिए गए हथियारों

[श्री हो० ना० मुकर्जी]

तथा युद्ध सम्बन्धी साज सामान का प्रयोग पाकिस्तान के विरुद्ध तो नहीं कर रहे हैं। उनके सामने यह बात पूर्णतः स्पष्ट है कि हम इस सामान का प्रयोग पाकिस्तान के साथ होने वाली मुठभेड़ में नहीं करते हैं। किन्तु अमरीका यह जानते हुए भी चुप है कि पाकिस्तान अमरीकी हथियारों का प्रयोग भारत के विरुद्ध खुले तौर पर कर रहा है और विद्रोही नागाओं को भी अमरीकी हथियार दे रहा है। हम पाकिस्तान के साथ कभी भी लड़ाई करना नहीं चाहते हैं। हम सदा यही चाहते हैं कि हमारे पड़ौसी देश के साथ हमारा झगड़ा नहो।

चीन और पाकिस्तान का उद्देश्य भारत के विरुद्ध कार्यवाही करना है। दोनों देशों की इस प्रकार कार्यवाहियां एक भयंकर रूप धारण कर रही हैं। चीन के खतरे के कारण हमने अमरीका को अपना गहरा मित्र बनाया और हम उस से यह आशा करते हैं कि बाहरी आक्रमणों से वह हमारी रक्षा करेगा। किन्तु ऐसा सोचना हमारी भूल है क्यों कि अमरीका कभी भी ऐसा नहीं करेगा। यदि हम अपने देश की सुरक्षा तथा खाद्यान्नों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे, जैसा कि हम कर रहे है, तो हम बहुत बड़ी विपत्ति में फंस जायेंगे, हमें सफलता तभी मिल सकती है जब कि हम दृढ़ निश्चय होकर आत्म निर्भरता का दृष्टिकोण अपनायें। हम जितना अधिक अपनी दुर्बलता का परिचय देंगे उतना ही हमें विश्व की शक्तियों के सामने झुकने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। पाकिस्तान द्वारा कच्छ के रन में की गई कार्यवाही इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है। हमें कच्छ के रन में अथवा अन्य किसी स्थान में पाकिस्तान की कार्यवाही के सामने नहीं झुकना चाहिए। हमें पाकिस्तान को उस के किये का पूरा पूरा जवाब देना चाहिए, यदि पाकिस्तान चाहे तो हमें समझौते के उद्देश्य से बातचीत के लिए तैयार रहना चाहिये किन्तु इसमें भारत के गौरव अथवा मान को किसी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए।

हमें इस बात का भी अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए कि पाकिस्तान अपने राजनैतिक तथा सैनिक चालों से विश्व के सामने भारत का गलत रूप प्रदर्शित करने का प्रयत्न कर रहा है। पाकिस्तान भारत को फंसाने के लिए तरह तरह के जाल बिछा रहा है हमें उनके प्रति सतर्क रहना चाहिए। हमें अपने मित्र देशों को तथा सारे विश्व को पाकिस्तान की करतूतों के बारे में पूर्णरूप से जानकारी देनी चाहिए ताकि हम यह सिद्ध कर सकें कि हम पाकिस्तान के प्रति कितनी सहनशीलता से कार्य ले रहे हैं। उदाहरणार्थ हमें अल्जीयर्स में होने वाली अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन के लिए तैयारी करनी चाहिए और सम्मेलन में सभी देशों के सामने सारी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए।

सरकार से मेरा अनुरोध है कि सरकार को किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार करते समय विरोधी पक्ष के सदस्यों को भी विश्वास में लेना चाहिए और कोई निर्णय लेने से पहले उनकी भी राय लेनी चाहिए। मेरी अपनी राय यह है कि यदि पाकिस्तान हम पर हमला करता है तो हमें भी जवाब में उस पर ऐसे स्थान पर आक्रमण करना चाहिए जहां पर हमारी स्थिति अच्छी है और पाकिस्तान के लिए वहां पर मुकाबला करना कठिन है। इस से पाकिस्तान को स्वयं सबक मिल जायेगा और वह फिर भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस नहीं करेगा। आज सम्पूर्ण देश सरकार के साथ है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि साम्प्रदायिक तथा अन्य राष्ट्र विरोधी तत्व जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिये खतरनाक हैं कुचल दिया जाना चाहिए अन्यथा हमारा विनाश निश्चित है।

भारत और पाकिस्तान के बीच किसी प्रकार का युद्ध होना दोनों देशों के लिए घातक है क्योंकि यह दोनों देशों के बीच रहने वाले अल्पसंख्यकों के लिए एक विनाशकारी बात साबित होगी। पाकिस्तान पूर्वी बंगाल में रहने वाले अल्प संख्यकों को मिटाने में लेश मात्र भी संकोच नहीं करेगा। किन्तु हमें यह बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि इस प्रकार की कोई घटना किसी भी देश में न घटने पाये। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है और हमें हर कीमत पर देश में सब धर्मों में सामंजस्य तथा शान्ति बनाये रखनी होगी। यह खुशी की बात है कि गृह-कार्य मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में आश्वासन भी दिया है।

अन्त में मैं सरकार से मूल्यस्तर निर्धारित करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं। इस के लिए जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी समाप्त की जानी चाहिए, आज देश का प्रत्येक व्यक्ति देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है किन्तु उसे कम से कम आवश्यक भोजन व कपड़ा तो अवश्य ही मिलना चाहिए।

श्री अन्सार हरवानी (बिसौली) : यह सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में कोई कार्य नहीं किया। भारत के नेताओं के सतत प्रयासों तथा बलिदानों से ही देश स्वतंत्र हुआ और जिसका भागीदार पाकिस्तान बिना कुछ प्रयास किये ही बन गया। इस के बदले में पाकिस्तान ने सीमान्त गांधी खान अब्दुल ग़फार खां को जेल में बन्द कर रखा है और भारत पर पिछले सत्रह वर्षों से किसी न किसी स्थान से आक्रमण करता रहा है।

मुझे इस बात का गर्व है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है और इस बात का विश्वास है कि भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी जाति का हो, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। इस के विपरीत पाकिस्तान की नींव साम्प्रदायिकता पर है। आज स्वतंत्रता के 17 वर्षों के बाद भी वहां पर कोई एक स्थायी सरकार कायम नहीं हो पाई है। पाकिस्तान में प्रभु सत्ता सम्पन्नता एक ढोंग मात्र है। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके दो भागों के बीच 1,300 मील का अन्तर है और उनका आपस में किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। धर्म के अतिरिक्त इन दो भागों में किसी बात में एकरूपता नहीं है, इन दोनों भागों की भाषा, संस्कृति, इतिहास आदि में लेशमात्र भी समानता नहीं है। किन्तु इन सब के बावजूद इन में एक बात समान है और वह है, भारत के प्रति घृणा और भारत से भय। आज पाकिस्तानी आक्रमण का सामना करने के लिए देश का प्रत्येक वर्ग सरकार के साथ है।

आज यह बात पूरी तरह साबित हो गई है कि पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध अमरीका द्वारा दिये गये हथियारों का प्रयोग किया है। अतः हमें अमरीका को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि पाकिस्तान की यह कार्यवाही बिल्कुल अनुचित है। उसे भारत के विरुद्ध इन हथियारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राष्ट्र मंडलीय नेता के रूप में ब्रिटेन को बताया जाना चाहिए कि राष्ट्र मंडल के एक सदस्य देश में दूसरे सदस्य देश पर आकारण आक्रमण किया है अतः उसे राष्ट्रमंडल से निकाला जाना चाहिए।

मैं उन समाजवादी नेताओं के विचारों से सहमत नहीं हूं जो यह कहते हैं कि भारत-पाकिस्तान का एक संघ बनाया जाये। जो नेता ऐसी बातें करते हैं उन्हें पाकिस्तान की नीति को अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करना चाहिए। पाकिस्तान की वर्तमान नीति को ध्यान में रखते हुए संघ बना कर समझौता करना संभव नहीं है।

[श्री अन्सार हरवानी]

इन शब्दों के साथ मैं सरकार का समर्थन करता हूं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : पाकिस्तान का सदा यही उद्देश्य रहा है कि भारत जिस बात का समर्थन करेगा वह उसके अवश्य विरोध करेगा, यदि यह कहा जाये ब्रिटेन ने पाकिस्तान की उत्पत्ति ही इसी उद्देश्य से की है तो अत्युक्ति नहीं होगी । वास्तव में पाकिस्तान को अपनी जनता के प्रति कोई प्रेम नहीं है । उसे उनके हितों तथा सुख सुविधाओं की कतई परवाह नहीं है । इतिहास इस बात का साक्षी है कि सरकार अपने हित के लिए जनता के हितों का हनन करती रही है । पाकिस्तानी नेता भारत पर आक्रमण करके अपनी जनता के ध्यान को प्रजातंत्र के मूल सिद्धान्तों की ओर से हटाना चाहते हैं क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में सरकार के निरंकुश शासन के विरुद्ध जनता बराबर संघर्ष करती रही है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *ine th Chair*]

मेरा सरकार से अनुरोध है कि पाकिस्तान में अल्पख्यकों को पाकिस्तान के हाथों बचाने के लिये उन्हें खुले रूप में भारत आने की अनुमति होनी चाहिए । यदि वे भारत न आ सके तो पाकिस्तान उन्हें समाप्त कर देने में कोई कसर नहीं रखेगा । सरकार को पाकिस्तान के साथ हमारी सीमाओं को बन्द नहीं करना चाहिए, हमें यह बात याद रखनी चाहिए अब भी पूर्वी पाकिस्तान में 85 लाख अल्प-संख्यक रह गये हैं । यदि वे भारत आना चाहें तो उन्हें मानवता के नाते यहां पर आश्रय दिया जाना चाहिए । उन लोगों के लिए भारत आने के लिये प्रमाणपत्र की कोई शर्त नहीं होनी चाहिए ।

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : Mr. Deputy Speaker, no doubt we are committed to peace but there can be absolutely no question of achieving it by surrendering any part of our territory. The facts given by the Prime Minister has convincingly proved that Pakistan has committed an inexcusable act of aggression.

Although we have always extended our hand of freiendship to Pakistan from the very beginning and have tried to settle every issue with them by peaceful talks and negotiations, and in many cases have been even over-liberal to them, they have not reciprocated to any of our such gestures. Had we also tried to pay Pakistan in their own coins we could have taught them a very good lesson in regard to canal waters etc.

Today all the people of our country are one in demanding strong action and effective measures to counter Pakistani aggression. We should not be deterred by any initial set backs for, as history shows, totalitarian countries have always certain advantages in the beginning.

Recently I visited some of the foreign countries. There I found the stand of India in this regard is being appreciated very much by those countries.

I hope the statement made by the Prime Minister will be appreciated by the world. The Prime Minister has made it clear that no doubt we follow the policy of peace but not at the cost of our territorial integrity. Inspite of the repeated assurances given by the American President that the arms supplied by America to Pakistan would not be used against India, Pakistan is using them against us. We, therefore, urge upon our Government to face the aggressor boldly and take all the necessary steps required for the defence of our borders.

The charge made by the opposition that the Government have lost the confidence of the public is baseless. I can emphatically say that they are neither in a position to form a Government nor win the confidence of the public in general.

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : While India had lodged a protest regarding the arms aid to Pakistan by U.S.A., the Secretary of State of U.S.A. Mr.Dulles had assured India that those arms would not be used against India. I want to know from U.S.A. leaders as to what has happened to their assurance.

Now U.S.A. and U.K. want cease-fire. Perhaps some such proposal is expected to be put before India. Discussions are also going on in Cairo regarding cease-fire. We are already having two cease-fire with Pakistan and China. We have had a bitter experience of cease-fire . Therefore we are not prepared for a third cease-fire.

We should take note that unless Pakistan vacates Kanjarkot, unless status-quo is established, the question of cease-fire does not arise.

No U.K. has offered to supply one sub-marine to Pakistan. U.K. Government should speak as to what is the guarantee that it will not be used against Indian Navy. Therefore I urge upon U.K. and U.S.A. to immediately stop the military aid that is being given to Pakistan. If that is not done India will have to think whether or not she should remain in Common-wealth.

Pakistan has committed intrusion at 9 points on Indian territory. Therefore we are facing danger at 9 points. They, are , two points in Kashmir, International boundry of Jammu, Punjab, Assam, Tripua, Lathitila, Karimganj and Dahagram. I exhort the people of India to get together to defend our motherland.

There is dictatorship in Pakistan. A dictator never cares for the wishes and sentiments of the public. They are misleading people. The slogans of *Jehad* are raised. All these things are directed aginst India. We are the descendents of those gallant fighters whose wives burnt themselves as satis and who themselves died in action. We have to maintain those high tradaions of chivalry.

Today the dictatorship in Pakistan is following Hitler and Mussolini. I want to say to the people of East Bengal and to the common people of Pakistan that India has no enmity with them. They are our brothers and sisters. But Pakistan wants to capture India forcibly. We are fully prepared to meet Pakistan on the battlefield.

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur) : Today, our Prime Minister said the attack which has been made upon us is a "naked and reckless use of force". The attack which has been made upon us at Kutch border cannot be called a border dispute. Nature has clearly demarcated our boundry at that place. Rann of Kutch cannot be called the Rann of Indus.

Pakistan was silent for the last 17 years. Now because she has attacked India she must find one or the other excuse. Mr. Bhutto has said that Pak forces will stay in Kutch and that he will take 3400 square miles of land from us forcibly. We have to teach them a lesson. We have to get our territories vacated. The Prime Minister should remain firm on the two things which has said today.

[Shri U. M. Trivedi]

If the Government remains firm in its poiicy, 45 crores of people of India are prepared to lay their lives, they are with you. You have resolved to push out the enemy. We have them a lesson who have taken a vow to destroy our country. Unless we teach them a lesson we cannot get peace. If we do not do that we shall be putting the honour of our country at stake. The world will think us to be weak and impotent. We shall lose Kanjarkot. Regarding Kanjarkot you called the I.G.P. That I.G.P. was responsible for the coming in of 3 lakhs of intruders into Assam. He did not tell the Home Minister. Shri Hitendra Desai that Pakistan was in the unauthorised occupation of 13,400 acres of land of India. The operator at the wireless receiver of our State Reserve passes on information to the enemy and rely on him. This is a matter of shame for you. You have to be alert and watchful. If somebody draws your attention to these things, you call him communal. I have received telegrams on behalf of Daoodi Vohra Pragati Mandal that you have permitted the Mohammedan leader His Holiness Tahir Saifuddin Mulla to visit Pakistan. This Mulla is running 11 companies in Pakistan with the money of our country. I can give their names. This man has sent crores of rupees to Pakistan and you are still relying on such a person.

You have given contract to the companies of this man to supply our military requisites. All the directors of those companies are Mohammedans.

In 1956 a blue-print was prepared for the manufacture of automatic rifles. Unfortunately a Minister came in the way and said that Russian should be consulted. He went to consult Russia and took six years. In 1960 a rifle was manufactured which could not fire. That defect was looked into and some rifles were manufactured in 1964. Two thousand rifles should be manufactured in day. I want to know how many rifles are being manufactured at present. During the last few days Government demobilised 40,000 persons why was it done in such a critical situation ? You are simply talking here. I do not find even one man who can provide leadership to this Country.

Pakistan has occupied our territory. We want to settle this dispute across the table. It cannot be solved this way. The proper way is to push out the enemy and to enter 10 miles inside the territory of the enemy and asking them to have talks to settle their dispute.

Pakistan has committed about 7,000 aggressions on our territory, and we are sitting silent. Lahore is not very far off. If we want we can capture it in a day. The time has come when we should teach Pakistan a lesson.

We should follow the policy of retaliation while dealing with Pakistan. We are uselessly talking of Vietnam and criticising America. America wants to make friends with us and we are unnecessarily harming our interets. While China is engaged by America in Vietmnam, we should beat Pakistan away. It is heared that in August China will attack on India from the East and Shiekh Abdulla will march with his army in Kashmir. Pakistan will attack from the other side, I do not know what have we thought about all these things. We are not looking to our own problems and trying to solve the problems of their people and creating troubles for ourselves.

We are not prepared to manufacture arms in our Country. We have unnecessarily created Public and Private Sectors. There are manufacturers in Private Sector who can manufacture very good rifles but you do not permit

them to do so. We shall have to be firm in our talks with Pakistan for defending our country. I want that the Government should sit together with the leaders of the opposition and consider this issue.

The motion which is before the House should be firmly implemented. Pakistani agressors should be pushed away from our borders. But if you will follow the old policy face defeats, as usual and lower the honour of our motherland. You are certainly not fit to occupy these seats.

Shri S. N. Chaturvedi (Firozabad) : The firm resolve that we see in the speech of the Prime Minister will have a good hearning upon our people.

Pakistani Policy is based on hatred and jealously against India. She wants to malign India. We have to be very alert and vigilant in chalking out our policy. We have to look to the history. India is second to none in chivalry and gallantry and yet we had to live in slavery for hundreds of years. We have remember why Prithvi Raj was defeated by Mohummad Gori for no lack of heroisum, Valour and bravery on his side.

Likewise Britishers came here, overpowered us and ruled us for 200 years. Since independence we have formulated the policy of non-aligument. We have to see that can this policy bring us any good when we are weak. We should make more countries our friends. We should have the friendshtp of countries which are enemy of our enemies. But we are unecessarily enraging and displeasing our friends. For no reason in matters which do not concern us directly

Take the case of Kashmir. Whenever we hear of talks about Kashmir, we fear that we may not give new conscessions to Pakistan. These talks are more dangerous than the attacks. First, we were saying that Pakistan was an aggressor and that we would take back our unauthorisedly occupied Territory. Later on we advanced the formula of "Hold what you have". After that we were even prepared for the adjustment of cease-fire-line and now in the end the mediation has also come in. Now the matters have advanced to the stage that Shiekh Abdulla has ventured to say about self-determination. He is making propgaganda against India in foreign countries. Pakistan has interpreted our willingness to hold negotiations as a sign of weakness.

We are engaged in our development work, but I want to tell that unless the attacks that are made upon us are retaliated, these attacks will have a very bad effect on the mental strength of the nation. It is a matter of great satisfaction that the Government have now taken a resolve that we will not negotiate unless the status-quo-ante is established i.e., Kutch is completely vacated by the enemy.

The policy of Pakistan is to first attack upon India and occupy some territorry and then to say for holding negotiations accross the table. It is wrong to call that territory as disputed territory. We should say in unequivocal terms that this is our territory. To-day Pakistan is claiming 3500 square miles of our territory. There will be no end to it and the day will come when whole of India will be declared as disputed territory. They are intraders and should be driven away first and then we talk about negotiations. This is not the time for holding talks, but for action. We should supply all the requirements of the soldiers who are fighting the enemies on the fronts. For the present we should lay aside our petty differences because they divert our attention from the main issue.

[Shri S. N. Chaturvedi]

We have also got to be watchful about the traitors in the country. We should not be liberal to the point as would imperil the security of our country. We should not allow such persons at or near the strategic points. In the end, my submission is that we should be firm in our resolve and stick to it and maintain the integrity and solidarity of the Country.

श्री ओझा (सुरेन्द्रनगर) : पिछले कुछ दिनों में मैं ने अपने राज्य के क. भागों का दौरा किया । वहां मैं ने देखा कि लोगों में सीमाओं पर जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बड़ी चिन्ता और उत्सुकता सी है । मैं ने उन में देखा कि वे देश के लिये बड़ी से बड़ी कुरबानी करने के लिये तैयार हैं । परन्तु इसके साथ साथ, सरकार जिस तरीके से स्थिति को सुलझाने का प्रयत्न कर रही है उसके प्रति उनमें निराशा की भावना नजर आती है ।

प्रधान मंत्री ने आज जो कुछ कहा उससे बड़ी आशा बन्धती है । उन्होंने कहा यदि हमें प्रतिरक्षा और विकास कार्य दोनों में से एक को प्राथमिकता देनी है तो हमें प्रतिरक्षा को चुनना होगा । फर भी विरोध के सदस्य अपने आप को सरकार की आलोचना करने से रोक न सके ।

19 अप्रैल को सेना ने वहां पर सीमा की रक्षा का भार संभाला । इससे पहले राज्य रक्षित पुलिस ने शत्रु से लोहा लिया । जो जवान शहीद हो गये हैं । मैं उन को श्रद्धांजलि भेंट करता हूं ।

अब प्रश्न यह उठता है कि सीमा की रक्षा करने की जिम्मेवारी किस की है । मेरे विचार में राज्य रक्षित पुलिस को केवल तस्कर व्यापार और सीमा पर होने वाली छोटी मोटी लड़ाइयों को रोकने के लिये ही काम में लाया जा सकता है । परन्तु जब हमें ज़रा भी शक हो कि पाकिस्तान हमारा इलाका छीनने की गर्ज़ से हमला करने का इरादा रखता है तो मैं समझता हूं कि सेना को तुरन्त अपने हाथ में सारी कार्यवाही ले लेनी चाहिये । इस मामले में भी मैं समझता हूं कि सेना ने कार्य को अपने हाथ में लेने में देर लगाई है ।

प्रधान मंत्री ने बताया कि पाकिस्तान ने कच्छ के बारे में हमारी कुछ कठिनाइयों का फायदा उठाया है । यह ठीक है कि वहां पर मौसम हमारे अनुकूल नहीं है । परन्तु भारत और पाकिस्तान के बीच की सारी सीमा में कुछ ऐसी जगह भी हैं जो युद्ध की दृष्टी से हमारे लिए काफी अच्छी हैं और पाकिस्तान के लिये बुरी हैं । अब समय आ गया है जब कि हमें पाकिस्तान को मुह तोड़ जवाब देना चाहिये । भारत वर्ष की जनता आज यह अनुभव कर रही है कि पाकिस्तान हमारी शराफत से अनुचित लाभ उठा रहा है ।

अब समय आ गया है जबकि, यदि हम अपनी सेना और लोगों का हौसला बुलन्द रखना चाहते हैं तो सरकार को अधिक दृढ़ होना चाहिये और सीमा पर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये । हमें बहुत से जवान मिलते हैं जो कहते हैं कि हम पूरी तरह तैयार हैं और पाकिस्तान से अच्छ टक्कर ले सकते हैं । नवम्बर, 1962 में हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में हम सब ने एक साथ खड़े होकर यह शपथ ली थी और संकल्प किया था कि हम हर कीमत पर अपनी सीमा की रक्षा करेंगे । आज भी वैसा ही अवसर है और हमें एक साथ आवाज़ उठानी चाहिये कि हम अपने किसी भी पडौसी देश को अपने साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे । बस, श्रीमन्, मैं इतना ही कहना चाहता था ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : 1962 में जो स्थिति थी आज उस से भी गम्भीर स्थिति है ।

प्रधान मंत्री ने एकता बनाये रखने के लिये जो अपने भाव प्रकट किये हैं मैं उनसे सहमत हूं । परन्तु लोगों से दुबारा अपील करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं । चीनी आक्रमण के पश्चात् लोगों ने यह सिद्ध कर दिया है कि उनमें देशभक्ति की भावना कितनी है । हम ने अपनी सरकार को बहुत अधिक शक्तियां दे रखी हैं । परन्तु शत्रुओं को खदेड़ने के लिये सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है ।

मैं प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं कि कच्छ में जो कुछ हुआ है क्या वह एक अकेली घटना है अथवा एक अप्रत्याशित आक्रमण है । 1962 में मध्य खाने के बाद भी यदि सरकार यह कहती है कि हम हमले के लिये तैयार नहीं थे तो मैं कहूंगा कि यह सरकार हमारे देश की रक्षा करने के योग्य नहीं है, इसमें शत्रु से लड़ने की शक्ति नहीं है ।

इस सरकार ने हमारे देश का एक भाग शत्रु को दे दिया है । इस सरकार में अवश्य कोई मोठी कमी है । अब तो कांग्रेस के सदस्य भी यह चाहते हैं कि सरकार को दृढ़ नीति अपनानी चाहिये । यह एक अच्छी निशानी है । यह खुशी की बात है कि प्रधान मंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी है । प्रधान मंत्री नेहरू ने भी अगस्त, 1960 में, जहां तक कच्छ के क्षेत्र का सम्बन्ध है, यह कहा था कि कोई सीमा विवाद नहीं है । केवल सीमांकन किया जाना है । इस में युद्धबन्दी का कोई प्रश्न नहीं है । परन्तु पाकिस्तान की एक चाल है जैसाकि विदेश मंत्री भुट्टो ने साफ साफ कह दिया है । वे आधा कच्छ मांगते हैं । कच्छ के रण के 9,000 वर्ग मील के क्षेत्र में से वे 3500 वर्ग मील क्षत्र की मांग करते हैं । पाकिस्तान यह समझता है कि युद्ध की दृष्टि से कच्छ की स्थिति हमारे पक्ष में नहीं है । सारा क्षेत्र पानी में डूब जायेगा ; हमारी सरकार वहां पर कोई सैनिक कार्यवाही नहीं कर सकेगी । पाकिस्तान ने जानबूझ कर 3500 वर्ग मील के क्षेत्र पर अपना कब्जा किया है । वह क्षेत्र को अपने कब्जे में रखना चाहता है ताकि बाद में जब वास्तविक लड़ाई आरम्भ हो जाये तब वे क्षेत्र उनके ही कब्जे में रहेंगे जिन को वे चाहते थे । यही उनकी चाल मालूम पड़ती है । जबकि हमारे देश की सारी सीमा चैतन्य है, और हम भी सतर्क हैं तब हम पाकिस्तान के इरादों को क्यों नहीं समझ सके हैं ।

पाकिस्तान और चीन दोनों के मामलों में यह साफ हो गया है कि उन्होंने हमारी सीमा के सब से कमज़ोर स्थानों को चुना है । जब हम ने प्रश्न उठाया कि चीन लद्दाख में सड़कें बना रहा है तो हमें बताया गया कि वहां पर घास की पत्ती तक नहीं उगती है इसलिये कुछ करने की जरूरत नहीं है । यहां भी यही तर्क दिया जा सकता है । क्या कारण है कि पंजाब में इतने आक्रमण नहीं किये जाते हैं ? क्योंकि वहां के किसान बहुत मज़बूत हैं और वे पाकिस्तानियों से टक्कर ले सकते हैं । हमारी सरकार की यह गलती रही है कि सरकार ने इन क्षेत्रों में सड़कें नहीं बनाई हैं और संचार साधनों का निर्माण नहीं किया है । इन क्षत्रों का देश के अन्य भागों से सम्पर्क नहीं है । इसलिये वहां पर आबादी न होने के कारण इन क्षेत्रों पर आक्रमण होते रहे हैं ।

हमारी सरकार अपनी गलती का अनुभव उस समय करती है जबकि हमें चोट पहुंचा दी जाती है । त्रिपुरा के बाद कूच बिहार में युद्ध विराम किया गया । 3 महीने के पश्चात् वे करीमगंज में आ गये । फिर वे कंजरकोट में आ गये और कंजरकोट में, प्रधान मंत्री हमें यह समझाने का प्रयत्न

[श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी]

कर रहे थे कि किस प्रकार एक घटना के बाद दूसरी घटना घटती गई और समाचार मिलते ही इस सरकार ने किस प्रकार जो भी कुछ संभव था किया। यदि आज प्रधान मंत्री जी से कोई यह कहता है कि आप नेहरू जी की नीति पर नहीं चल रहे हैं तो वह चिड़ जाते हैं। इसलिये वह उस नीति पर सख्ती से चलने का प्रयत्न करते हैं। वह नीति क्या है ? यदि देश पर आक्रमण किया जाता है, तो विरोधपत्र भेज दो--यह नीति है। अतः विरोध पत्र भेजने में उन्होंने कोई देरी नहीं की है। पाकिस्तानी सिपाहियों ने 10 फरवरी को कंजरकोट पर कब्जा किया था, परन्तु 17 फरवरी को भारतीय गश्ती दस्तों को पता लगा कि कंजरकोट का किला छोड़ दिया गया है। 17 फरवरी से 1 मार्च तक कंजरकोट क्षेत्र में कोई भी पाकिस्तानी सिपाही नहीं था। फिर हम ने उस क्षेत्र को खाली क्यों छोड़ा और अपना कब्जा क्यों नहीं किया जबकि वह हमारा अपना क्षेत्र था। 9 अप्रैल तक हम ने इस मामले को अपनी सेना को नहीं सौंपा। इस मामले को राज्य स्तर पर छोड़ दिया गया था।

केन्द्रीय सरकार और गुजरात की राज्य सरकार के बीच कोई समन्वय नहीं था। गुजरात सरकार तो यह कहती है कि कोई आक्रमण हुआ ही नहीं।

जो कुछ भी हो रहा है मुझे उसमें एक गहरी चाल नजर आती है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान कभी इस देश को जीत सकता है। चीन और पाकिस्तान मिले हुए हैं। ये सब घटनायें चौनलाई के पाकिस्तान के दौरे के पश्चात् हुई हैं। अखबारों में खबर थी कि चीन के कुछ चोटी के सैनिक अधिकारी पूर्व पाकिस्तान आय हैं। पाकिस्तान हमारे शत्रु का मित्र है। हमें कोई भी कार्यवाही करने से पहले इस पर अच्छी तरह गौर करना है।

मैं इस सरकार को और प्रधान मंत्री को इस बात के लिये दोषी ठहराता हूं कि उन्होंने इस प्रश्न के इस पहलू की गंभीरता को नहीं समझा है। मैं यह कभी भी नहीं सोच सकता था कि जबकि पाकिस्तान ने हमारे क्षत्र पर कब्जा कर रखा है और हमारे प्रधान मंत्री जी नेपाल जाते हैं, पाकिस्तान की ओर से खतरे के बारे में कहने के लिये उनके पास कुछ भी नहीं है। यह औरों को तो सलाह दे रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो, उत्तर वियतनाम पर बम मत डालो। परन्तु अपने हित की ओर ध्यान देने के लिये उन के पास समय नहीं है। हमें तथ्यों की ओर ध्यान देना चाहिये। आप को दृढ़ होना चाहिये। केवल चीन ही नहीं अमरीका भी अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर आक्रमण करने में पाकिस्तान की सहायता कर रहा है। अमरीका के लोगों ने अनेक स्पष्टीकरण दिये हैं, परन्तु यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि जबकि इसका प्रमाण मिल चुका है कि भारत के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा अमरीका का गोला बारूद इस्तेमाल किया जा रहा है, अमरीकी सरकार के किसी भी वक्ता ने इसके बारे में एक भी शब्द नहीं कहा है। अमरीका ने इसकी निन्दा में एक भी शब्द नहीं कहा है।

स्थिति बहुत गम्भीर है। हमें यह आशा नहीं करनी चाहिये कि 1962 की तरह हमें विदेशों से भारी सहायता मिल जायेगी। अमरीका के प्रशासन में जो अन्तर आ गया है हमें उस की ओर भी ध्यान देना चाहिये। श्री जानसन कनेडी नहीं हैं। 1964 में जब श्री जानसन ने उपराष्ट्रपति के रूप में पाकिस्तान का दौरा किया था तो क्या श्री अयूब खां ने उन्हें साफ साफ नहीं बताया था कि पाकिस्तान गोलाबारूद को अफगानिस्तान और भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करेगा ? यदि अमरीका

वास्तव में भारत की मित्रता चाहता है तो उसे पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध अमरीकी शस्त्रास्त्र को इस्तेमाल करने से रोकना होगा ।

यदि वियतनाम में अमरीका और रूस में लड़ाई हो जाये तो इस पर आश्चर्य न होगा कि चीन उस समय अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाये जब कि हम अपनी सारी फौजें पाकिस्तानी खतरे का सामना करने में लागाए हुए हों । ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा । हमें अपनी ही शक्ति पर निर्भर करना पड़ेगा । तब हम पश्चिमी देशों की सहायता पर नहीं रह सकते । इसलिये हम अपने पड़ोसी देशों से बहुत अच्छे सम्बन्ध रखने चाहिये । नेपाल से हमारे सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं और आशा है कि श्रीलंका की नई सरकार से भी अच्छे होंगे ।

प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि बहुत से देशों ने यूद्ध–विराम का सुझाव दिया है । परन्तु मरे विचार से इस समय हमें युद्ध–विराम तथा मध्यस्थता सम्बन्धी कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं करने चाहिये । हमें इसे मसले को संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा किसी दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था में ले जाने की भूल विल्कुल नहीं करनी चाहिये । हमें इचे संकट का स्वयं अपनी शक्ति से मुकाबला करना चाहिये ।

मैं प्रधान मंत्री जी के इस विचार से चेहमत हूं कि हमें अपनी सेना को स्वतंत्र रूप से इस सभेस्या का मुकाबला करने देना चाहिये । प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में सेना को छुट दी जानी चाहिये कि वे इस बारे में स्वयं निर्णय करें । सेना को जवाबी कार्रवाई करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिये । इस से यह होगा कि शत्रु अपनी रक्षा करने में लग जायेगा तथा आक्रमण नहीं कर सकेगा । हमारी सेना कमजोर नहीं है । वह शत्रु को खदेड़ सकती है । और उन्हें सबक सिखा सकती है । ऐसा करने से शत्रु यह समझ जायेगा कि आक्रमण करना कोई आमान बात नहीं है चाहे चीन जैसा देश उसेसहायता क्यों न देता हो ।

इस देश में पाकिस्तान और चीन के दूतावास जासूसी का काम कर रहे हैं । पाकिस्तान का दूतावास तो कुछ पुस्तिकायें भी प्रकाशित कर रहा है जो आपत्तिजनक है । क्या पाकिस्तान और चीन भी हमारे राजनयिकों को वहां ऐसा करने देते हैं । इसलिये उनके राजनयिकों पर यहां भी प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये ।

हमें अपने सेना कार्यालयों को सुरक्षा को भी सुदृढ़ बनाना चाहिये । वहां जानें वाले व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिये । मुझे पता चला है कि कुछ ही दिन हुए पाकिस्तान की सेना का एक अधिकारी हमारे नाविक मुख्यालय में चला गया था । हमारे अपने लोगों को वहां जाने की अनुमति नहीं है परन्तु यह पाकिस्तानी अधिकारी अपनी वर्दी में अदन्र चला गया था । मुझे पता नहीं कि उस ने वहां किस से बात की और क्या किया । इललिये ऐसे कार्यालयों में कड़ी पाबन्दी होनी चाहिये । चाहे सेनापति को ही क्यों न जाना हो जसे अपना पहचान–पत्र दिखाना चाहिये ।

सरकार को ऐसे लोगों की गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिये जो स्थिति का लाभ उठाकर साम्प्रदायिकता फैलाना चाहते हों ।

हमें इस संकट का सामना करने के लिये शक्तिशाली नेतृत्व की आवश्यकता है क्योंकि अच्छा नेतृत्व होने से लोगों में ऐसी भावना पैदा हो जायेगी कि इस संकट का मुकाबला करने के लिये वे स्वयं तैयार हो जायेंगे । किसी भी वक्ति को अपील करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी देश–भक्त हैं । आज आवश्यकता यदि किसी चीज की है तो वह है शक्तिशाली नेतृत्व की । हम आपस में

[श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी]

कितना ही क्यों न लड़ें, हमारे म कितने ही भेब–भाव क्यों न हों परन्तु संकट के समय हमें. एक हो जाना चाहिये तभी हभे शत्रु का मुकाबला कर सकते हैं ।

श्री बाकर अली मिर्जा (वारंगल) : पाकिस्तान की कार्रवाई के सम्बन्ध में इस सभा में जो चिन्ता व्यक्त की गई है मैं उस से सहमत हूं । अब हमें दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिये कि हमने क्या करना है । परन्तु ऐसा निश्चय करने से पहले हमें भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो कुछ वर्षों से सम्बन्ध रहे हैं उन पर विचार कर लेना चाहिये । पिछले 17 वर्षों के अनुभव से हमने यहीं देखा है कि पाकिस्तान का रवैया भारत के प्रति अच्छा नहीं रहा है । सबसे पहले शरणार्थियों की समस्या उत्पन्न हो गई थी । वे लाखों की संख्या में भारत आये और अब भी आ रहे हैं । पहले उन्होंने हिन्दुओं को निकालना आरम्भ किया । उस के पश्चात इसाईयों की बारी आयी । और अब ऐसा सुना जा रहा है कि पश्चिमी पंजाब तथा उत्तर–पश्चिमी सीमान्त क्षेत्र के 'अन्सार' समुदाय के लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान से बंगाली मुसलमानों को निकालना आरम्भ कर दिया है । इसलिये पूर्वी बंगाल में असन्तोष तथा विद्रोह की लहर फैल गई है । परन्तु उन का अपना कोई नेता न होने के कारण उन की समझ में नहीं आता कि क्या यिा जाये । मैं मानता हूं कि भारत से भी लोगों ने पाकिस्तान जाना आरम्भ कर दिया था परन्तु यह चीज तब हुई थी जब कि साम्प्रदायिकता की भावना जोर पकड़ रही थी । उस के पश्चात् देश में धर्म निरपेक्षता स्थापित हो गई और प्रत्येक चीज़ ठीक हो गई थी । इस समय भी भारत में 5 करोड़ मुसलमान हैं । यहि नहीं पाकिस्तान से जो मूसलमान आसाम में आये हैं वे वापिस नहीं जाना चाहते हैं । इसका यही कारण है कि भारत में अल्पसंख्यकों को पूर्ण स्वतन्त्रता है । फिर क्या कारण है कि पाकिस्तान ने पिछले 17 वर्षों से यह रवैया अपनाया हुआ है ।

पाकिस्तान को मि० जिन्ना ने नहीं बल्कि ब्रिटेन की सरकार ने बनाया है, ऐसा मेंरा विचार है । यही कारण है कि पाकिस्तान ब्रिटिश सरकार की नीति पर चल रहा है । मुझे याद है कि लगभग 40 वर्ष पूर्व जब मि० लियाकत अली खां शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और मैं भी वहां उनके साथ ही पढ़ रहा था तो उन्होंने मुझ से मुस्लिम लीग में शामिल होने के लिये अनुरोध किया था परन्तु मैंने उनको यही उत्तर दिया था कि तुम ब्रिटिश सरकार के पिट्ठू बने हुए हो तथा समझते ऐसा हो जैसे तुम देश की सेवा कर रहे हो । मैं उन माननीय सदस्य के विचारों से सहमत हूं जो पहले कह चुके हैं कि ब्रिटिश सरकार को जो भारत ने अपना देश स्वतन्त्र करा कर घाव किया है वह उसे भूले नहीं हैं और इसीलिये उन्होंने पाकिस्तान को बनाया था तथा अब उसे भारत के विरुद्ध प्रयोग में ला रहे हैं ।

बी० बी० सी० रेडियो को सुनने से पता चलाता है कि वह हमेशा पाकिस्तान का पक्ष लेता है । वह पिछले 17 वर्षों से हमारे विरुद्ध प्रचार कर रहा है । अभी कल ही उन्होंने प्रसारित किया था कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति तो शान्ति के लिये अपील कर रहे हैं परन्तु भारत अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है । उन्हें शायद यह मालूम नहीं है कि हम अब भी युद्ध विराम सन्धि पर हस्ताक्षर करने को तैयार हैं यदि पाकिस्तान ऐसा करने के लिये राजी हो । उन्हें शायद यह भी पता नहीं कि हमारे प्रधान मन्त्री जी अब भी पाकिस्तान के साथ शान्ति शान्ति वार्ता आरम्भ करने को तैयार हैं जबकि सारे देश में यह भावना फैली हुई है कि पाकिस्तान से बदला चुकाया जाना चाहिये और अपनी भूमि को पहले वापिस लेना चाहिये । इस प्रकार बी० बी० सी० जो पाकिस्तान के हित में भारत के विरुद्ध प्रचार कर रहा है यह ठीक बात नहीं है ।

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए
SHRI THIRUMAL RAO *in the Chair*]

पाकिस्तान ने चीन के साथ जो सांठगांठ की है अब मैं उसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। इस समय इजरायल ने इंग्लैण्ड के साथ जो गुप्त समझौता किया था वह बात मुझे याद आ रही है। जब इज़रायल की काहिरा से लड़ाई हो रही तो उन्होंने इंग्लैण्ड के प्रधान मन्त्री से ऐसा गुप्त समझौता किया था जिसे वहां के कई संसद् सदस्य भी नहीं जानते थे। उसी प्रकार से आज पाकिस्तान भी चीन से सांठ-गांठ कर रहा है। इसके पीछे राजनीतिक चाल है। यही कारण है कि अमरीका भी चुप बैठा हुआ है। इस सांठ गांठ पर अमरीका ने इतना शोर नहीं मचाया है जितना कि किसी साम्यवादी कार्रवाई पर वह मचाता है। क्या यह सम्भव नहीं है कि पाकिस्तान ने अमरीका को कह दिया हो कि हम यह सब कुछ काश्मीर का फैसला कराने के लिये कर रहे हैं वरना कोई बात नहीं है। चीन के साथ सांठ गांठ करने पर भी पाकिस्तान का 'सियाटो' का सदस्य बने रहने से ऐसा प्रतीत होता है कि अमरीका निहित स्वार्थों के लिये यह सब कुछ सहन कर रहा है। इसलिये हमें अपने तथाकथित मित्रों के प्रति सावधान रहना चाहिये। अब समय आ गया है जबकि हमें स्वयं अपनी शक्ति पर निर्भर करना चाहिये हभारी अपनी शक्ति क्या है ? हमारी अपनी शक्ति वही है जो कि हमारे 45 करोड़ नागरिकों की शक्ति है। यदि हम एक हो जाय तो संसार की कोई शक्ति हमारे राज्य क्षेत्र पर हक नहीं जमा सकती।

अब मैं विरोधी दलों के सदस्यों से भी प्रार्थना करूंगा कि वह आलोचना करना छोड़ दें और सरकार के काम में हाथ बंटवायें। श्री द्विवेदी ने ठीक ही कहा कि प्रधान मन्त्री को विरोधी दलों के सदस्यों को समय समय पर बुला कर पूछना चाहिये कि वे देश के लिये क्या योगदान दे सकते हैं।

मैं एक प्रार्थना और करना चाहता हूं। यह हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का सवाल है। इसे हिन्दुओं और मुसलमानों का सवाल नहीं समझा जाना चाहिये। मनुष्य की दयानतदारी तथा गैर-दयानतदारी देखी जानी चाहिये न कि उसकी जातपात। बहुत से लोग चीन का हित करने के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिये गये थे। वे मुसलमान तो नहीं थे। इसलिये मनुष्य की जाति नहीं बल्कि उसकी दयानतदारी देखी जानी चाहिये।

मुसलमानों को भी आगे आकर देश की प्रतिरक्षा में अपना योगदान देना चाहिये। यह उनका कर्तव्य है कि वे देशवासियों में अपने प्रति विश्वास की भावना पैदा करें कि वे भी देश के लिये अपने जीवन का बलिदान दे सकते हैं।

हम सब को जो कुछ भी हम कर सकते हैं अपने देश के लिये करना चाहिये।

हम सदा शान्ति के पुजारी रहे हैं और रहेंगे भी। जब कभी भी हमने कोई बात कही है तो वह दूसरे देशों को आजाद कराने की कही है।

हमने अपनी सेना इसलिये नहीं बढ़ाई थी क्योंकि हम शान्ति चाहते थे परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि हम अपने देश का सम्मान खो बैठेंगे। यदि हमारे पास शस्त्र नहीं भी हैं तो भी हम बाजुओं के बल से शत्रु को अपनी धरती से बाहर निकाल फैंकेंगे।

अन्त में मैं फिर कहना चाहता हूं कि हमें शान्ति बनाये रखने के लिये पूरा प्रयत्न करना चाहिये तथा साथ ही किसी भी मुकाबले के लिये तैयार रहना चाहिये।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : The need of the hour is strong determination. When I say so, the memory of Sardar Patel comes in my mind. He was a man of strong will. He used to take firm stand on every situation. We should also follow his foot steps. We should stick to the stand that we once take. We should not have fickle-minded policy.

We have already lost much. We have lost Longju, Barahoti, Ladakh, Aksai Chin and also Kutch. The people of the country have now started feeling that any part of the country can be lost at any time. Therefore you should now take a final decision than at any cost , we will regain our Kanjarkot. We should once for all make this policy that in future we will not lose a single inch of territory even if we have to fight to the last.

Now I come to the relations between India and Paskitan. Either the relations between the two countries will be very cordial and even both the contries can be amalgamated or they will remain the sworn enemies of each other. There cannot be any middle course. It may be possible that the relation can remain friendly for two, three or four years but after that cannot be a permanent affair. I can remind you of the canal water agreement. At that time the people had formed this opinion that with this agreement our relations with Pakistan will befriendly for ever. But what happened ? Again new problems crept in. Therefore, as I said earlier, it is not possible that we can have friendly relation with Pakistan permanently.

I want to make it clear to the people of India as well as Pakistan that India and Pakistan will either remain sworn enemies or they will merge together. Otherwise the two countries can not maintain friendly relations with each other. If we want to regain Kanjarkot let us not talk of floods, rains etc. You should not say that Longju is a hill and Chinese have the logistic advantage of being on the higher side. These are all useless things. Pakistan is the union of two unnatural and artificial posts like *'Jarasandh*. If the trouble between the two countries takes a serious turn, it is hardly a matter of four or five for India to occupy East Pakistan. It is not an easy affair that Pakistan will occupy this territory or that territory. Pakistan is fully conscious of this fact, which make her nervous. If you act a little wisely you will be a complete master.

I have been receiving numerous telegrams and letters from East Pakistan. I do not say much about it. I have a picture of a confederation in my mind. One day or the other there is bound to be a union. If the Government of India adopts a socialistic approach, it will be possible for the people of Pakistan to revolt against dictatorship of President Ayub and there may be reunion of the two countries. It is a long term affair. We have to make a distinction between the government and the people of Pakistan. The people of the two countries were kith and kin and are so even today and are bound one day to unite into one nation. Whatever force we may have to use we should create a sense of security in the minds of Pakistan.

I want to draw your attention to the statement of an ex-American ambassador in India, published to-day that he had advised India at the time of Chinese attack, not to resort to air strikes. What business an ambassador of a foreign country has got to give such an advice when China had occupied 20,000 sq. miles of our territory ? If 20,000 sq. miles of American territory is occupied, will any American say that do not defend your country and do not launch an air attack. This leads us to one thing that the big nations are not worried about

the loss of territories as far as coloured and weaker nations are concerned. I am one of those who wished that the government of India should not comment on the situation in Vietnam because we do not want to say any thing which might strengthen China or North Vietnam. In contrast to it is the statement of an American professor, who had been ambassador to India.

During the course of discussions on Korea, Joseph Stalin had drawn the attention of Shri K. P. S. Menon, the Indian ambassador to artificial position of India and had suggested a confederation. I do not know what are the views of Brezhnov or Kosygin but I want to point out that any person, with foresight and just and peaceful approach to international matters, will have to follow the principle in some form or the other that any country artificially partitioned into two nations will have to be merged to form a Confederation.

It is often mentioned here that Pakistanis were found using American weapons. But question of a Russian weapons with Chinese has never been raised. We do not know the event or aid being given by Russians to Chinese but now they say there is a rift between them. So my point is that ignoring these petty matters we should ask America and Pakistan whether they are amendable to Indo-Pak Confederation in the interest of world peace. I have already said that the same principle applies to Germany, Vietnam, Korea and other places.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

We must make clear our resolve to defend every inch of our territory and fight to the finish till we get back the lost territory. The Defence Minister should come out with such statement. Our Government have every often proposed a no-war pact to Pakistan. I would recall that near about 1959 President Ayub had also offered to India a Joint-Defence Plan. In my view India should suggest a Confederation. We should be prepared to make sacrifices for it. President may be a Pakistani and the Prime Minister an Indian.

The Prime Minister has appealed for national integration, This is all useless talk. I do not want to boast but can say that we are all eager about it. The Prime Minister compared poverty and independence. It is impossible to defend independence if we remain poor. If we raise the standard of living of 48 crores people of our country and make them rich, then only we can face China and Pakistan. Government should sit and consider seriously how to get rid of their failings and weak points in the interest of an effective defence of the country. The use of the word 'disputed' with reference to any territory should be stopped.

श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित (फूलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह इतिहास की एक विचित्र घटना है जो कंजरकोट क्षेत्र में हो रही है जहां पाकिस्तान दक्षिण-पूर्व एशिया में चीन के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिये अमरीकी शस्त्रों का प्रयोग कर रहा है। ये नई गड़बड़ पैदा करने के लिये पाकिस्तान द्वारा विशेष क्षेत्र के चुनाव ने हमें चकित कर दिया है लेकिन उसके द्वारा अपनाये गये प्रत्येक तरीके से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह चीनी मस्तिष्क का आयोजन है।

[श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित]

1954 में भारत सरकार व विदेशों में उसके प्रतिनिधियों ने अमरीकी सरकार को यह समझाने का प्रयत्न किया था कि साम्यवाद के विरुद्ध तथाकथित प्रतिरक्षा के लिये दिये गये हथियार भारत के विरुद्ध प्रयोग किये जा सकते हैं। यह आशंका अब सत्य सिद्ध हुई है। 1946 में मैंने अमरीका में अपने एक रेडियो भाषण में इस बात की आलोचना की थी कि एशिया में स्वतंत्रता को स्वतंत्रता के समर्थकों की सहायता से कुचला जा रहा है। इस पर राष्ट्रपति ट्रूमैन ने मुझे बुलाकर कहा था कि जो हथियार दे दिये गये हैं उनका प्रयोग हम कैसे रोक सकते हैं। जब पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर यह सहायता दी जाने लगी तो राष्ट्रपति आइजनहावर तथा विदेश सचिव श्री डलेस ने यह आश्वासन दिया कि इस सहायता के किसी भी भाग का भारत के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जायेगा। भारत सरकार ने यह समझाने का भरसक प्रयत्न किया कि दोनों देशों की स्थिति को देखते हुए यह कैसे संभव होगा। पाकिस्तान की इस कार्यवाही से भारत में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है तथा हमारे और अमरीका के बीच एक खाई बन गई। इससे अफ्रीकी-एशियाई देशों को गम्भीर चिन्ता हो गई है जिनसे हम अपने अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये मैत्री-भाव व समर्थन की आशा करते हैं।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिये चीन ने पिछले दस वर्षों में दक्षिण-पूर्व एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में गड़बड़ी बनाये रखी है। दक्षिण वियतनाम से लड़ने के लिये वियतकांग को प्रेरित किया है तथा इसी तरह लाओस में पाथेट लाओ को। चीन इंडोनेशिया को मलयेशिया पर आक्रमण करने के लिये भड़का रहा है। और अब भारत पर भारी आक्रमण व छेड़छाड़ से चीन की युद्धप्रणाली दृष्टिगोचर होती है। पिछले कुछ महीनों के दौरान उच्च-स्तरीय परामर्श के चीन तथा पाकिस्तान के बड़े-बड़े राजनैतिक तथा सैनिक अधिकारियों ने एक-दूसरे के देश की यात्रा की है। चीन ने भारत पर आक्रमण करने के लिये पाकिस्तान को भड़काने का यह विशेष अवसर ढूंढा ताकि वियतनाम में उसकी असफलता पर पर्दा पड़ जाये। जब हमारे प्रधान मंत्री शान्तिपूर्ण तथा सभ्य तरीकों से झगड़े सुलझाने की बात कहते हैं तो सारा देश उनके साथ है। अभी वियतनाम के बारे में गुट-निरपेक्ष 17 राष्ट्रों की सार्थक अपील में सहयोग किया। इसी प्रकार की एक अपील पाकिस्तान से भी की गई है। वियतनाम ने अपील को ठुकरा दिया है और हम जानते हैं कि पाकिस्तान का उत्तर क्या होगा ?

आज सभा में कार्यवाही करने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, जिसका संभवत: अर्थ युद्ध से है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : आवश्यक नहीं है।

श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित : मैं जानती हूं कि इस शब्द का यह अर्थ नहीं है। एक-एक इंच भूमि वापस लेने की बातें कही गई हैं। संभवत: हम शक्ति प्रयोग करके ऐसा कर सकें। अतएव, अत्यधिक आदर के साथ मैं सुझाव दूंगी कि हमें सब को झगड़ा सुलझाने के लिये प्रधान मंत्री द्वारा मर्यादापूर्ण तरीके खोजने का समर्थन करना चाहिये ताकि पाकिस्तान को हम यह दिखा दें कि शान्ति स्थापित करने के लिये हम सभ्य तरीके अपनाना चाहते हैं। परन्तु यदि ऐसा सम्भव न हो यद्यपि हम ने अहिंसा की नीति का वचन ले रखा है, तो भी हमें दूसरी कार्यवाही करने से

पीछे नहीं हटना चाहिये । प्रत्येक राष्ट्र के इतिहास में ऐसे अवसर आते हैं जबकि बिल्कुल उलटी नीति अपनानी पड़ती है । यही राष्ट्र की इच्छा होगी ।

वर्तमान सरकार तथा स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू की नीतियों को समय के प्रतिकूल बताया गया है और यह कहा गया है कि इनके कारण देश को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है । मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यदि हम ने गुट-निरपेक्ष नीति न अपनाई होती तो जो स्थान हमें विश्व में आज प्राप्त है वह न होता । हम ने ऐसी नीति बनाई जो विकासशील देशों के उपयुक्त थी जिसे एशिया के प्राचीन तथा अफ्रीका के नये देशों ने अपनाया । आज उनके हाथ में वह शक्ति है जो घटना-चक्र को जिस तरफ चाहे मोड़ सकती है । (**अन्तर्बाधा**)

मैं इस बात के पक्ष में हूं कि आवश्यकता पड़ने पर हमें अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिये यदि भारत के हित के लिये इसकी आवश्यकता हो क्योंकि कोई भी नीति भगवत-गीता, कुरान या बाइबिल की तरह पवित्र नहीं है कि उसको बदला नहीं जा सकता । लेकिन मैं यह अवश्य कह दूं कि हमें उन नीतियों के बारे में नीची बातें नहीं कहनी चाहियें, जो हमें लाभ पहुंचा रही हैं । मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार कोई भी परिवर्तन करने से पहले सभी पहलुओं पर पूर्णतः विचार करेगी । दबाव के कारण कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिये ।

यह प्रश्न बार-बार उठाया जाता है कि क्या कारण है कि विश्व में भारत के मित्र कम होते जा रहे हैं जबकि पाकिस्तान के मित्र बढ़ रहे हैं । इसका कारण हमारी स्वतंत्र नीति तथा वह मत व्यक्त करने का साहस है जो भले ही विश्व में लोकप्रिय न हो । इससे उन लोगों को चोट पहुंचती है जो अभी कुछ दिन पहले तक हमारे देश के शासक थे । इसके विपरीत पाकिस्तान निष्पक्षता से सोचे समझे बिना उन देशों की बात का समर्थन करता है जिनसे उसे सहायता मिलती है । किसी भी परिस्थिति में इसका अनुसरण करने से भगवान भारत को बचाये । हम किसी के पिछलग्गू नहीं बनना चाहते । (**अन्तर्बाधा**)

हमें यह ध्यान में रखना है कि हमें चीन की आगे की गतिविधियों को सावधानी से देखना चाहिये तथा उसका सही अनुमान लगाना चाहिये । यह कहा जा सकता है कि चीन अब भी नये मोर्चे की योजना बना रहा है । निस्सन्देह कंजरकोट का मोर्चा किसी और उद्देश्य के लिये चीन तथा पाकिस्तान की सांठगांठ का एक चिह्न है । यदि यह ठीक है तो हम एक-दूसरे की आलोचना बन्द कर दें । (**अन्तर्बाधा**) इस समय शिष्टता, देश भक्ति और सभ्यतापूर्ण व्यवहार इस बात की मांग करते हैं कि हम प्रधान मंत्री को पूर्ण सहयोग दें तथा अपने मतभेदों को भूलकर पाकिस्तान को सही ढंग से उत्तर दें । केवल तब ही हम संसार पर प्रभाव डाल सकते हैं । यह कहा गया है कि शान्तिपूर्ण तरीकों से हम अपनी भूमि वापस नहीं ले सकते । मैं तो केवल इतना कहना चाहती हूं कि हम ऐसा कोई गलत कदम न उठा लें जिससे पीछे हटना असंभव हो जाये । हम जो भी कार्यवाही करें वह भारत के तथा मानव जाति के हितों को ध्यान में रख कर करनी चाहिये जिसके लिये युगों से महापुरुष जीवनदान करते आये हैं ।

श्री फ्रैंक एन्थोनी (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय) : इन घटनाओं के देखने से पता चलता है कि हमारी सैनिक तथा विदेशी नीति असफल रही हैं । मैंने अनेक बार स्वर्गीय प्रधान मंत्री से पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों में तनाव कम करने के बारे में कहा था क्योंकि मेरा विश्वास था कि केवल भारत और पाकिस्तान ही चीनी साम्यवाद से महाद्वीप की रक्षा कर सकते थे ।

[श्री फ्रेंक एन्थोनी]

उन्होंने कहा था कि काश्मीर दे देने से ही बात समाप्त नहीं हो जाती क्योंकि पाकिस्तान घृणा पर पला है यह हमेशा तनाव उत्पन्न करने के लिये कोई न कोई कारण ढूंढ लेगा। मुझे दु:ख के साथ यह कहना पड़ता है कि मेरी धारणा गलत थी। अब यह निस्संदेह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान का नीति-शास्त्र घृणा पर आधारित है। यह एक ऐसा सिद्धान्त है जिससे उसकी विदेशी नीति पर ही प्रभाव नहीं पड़ा है बल्कि इसका प्रभाव सामान्य पाकिस्तानी सरकारी कर्मचारियों तथा वहां की जनता पर भी पड़ा है।

हाल में मैंने राष्ट्रमंडलीय सम्बन्ध सम्मेलन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। (**अन्तर्बाधा**) वहां मुझ से अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने पूछा कि क्या कारण है कि भारतीय पाकिस्तान से घृणा करना तो क्या उसके लिये बुरी भावना भी नहीं रखते जबकि दूसरी ओर पाकिस्तानी प्रतिनिधियों की दिनचर्या ही भारत के प्रति विष वमन से आरम्भ होती है। मैं एक घड़ी के लिये भी यह नहीं सुझा रहा हूं कि हम इस प्रवृत्ति को अपनायें क्योंकि मेरा विश्वास है कि एक व्यक्ति की तरह एक राष्ट्र भी जो घृणा पर पलता है उसकी नींव खोखली हो जाती है तथा अन्ततोगत्वा घृणा उसे नष्ट कर देती है।

हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान दक्षिण-पूर्व एशियाई संधि संगठन का सदस्य है, जिसका प्रमुख उद्देश्य चीनी साम्यवाद को बढ़ने से रोकना है। लेकिन पाकिस्तान का उद्देश्य क्या था ? उसका एकमात्र उद्देश्य चीन के विरुद्ध प्रयोग के नाम पर अमरीका तथा ब्रिटेन से शस्त्र प्राप्त करना है जिनका प्रयोग वह भारत के विरुद्ध कर सके जैसा कि वह कच्छ में कर रहा है। घृणा के सिद्धान्त से पाकिस्तानी नेता इतने अन्धे हो गये मालूम होते हैं कि वे इस बात को भूल रहे हैं कि यदि किसी समय भारत साम्यवाद की लपेट में आ गया, तो स्वतंत्र देश के रूप में पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो जायेगी कि वह एक सप्ताह में समाप्त हो जायेगा। मैं समझता हूं कि यह चीन और पाकिस्तान की सांठ-गांठ है कि भारत की सीमा पर आक्रमण करके हमारी सैनिक शक्ति को इधर-उधर बखेर दें तथा राष्ट्र-निर्माण के कार्यों से हमारा ध्यान हटा दें।

आज यह सरकार से पहले भारत की जनता व प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र को चुनौती है। यदि हम इसका उत्तर अनुशासनहीन होकर तथा छोटे-छोटे राजनैतिक झगड़ों में पड़ कर देंगे तो हम केवल अपने आप को निर्बल बनायेंगे जिससे केवल चीन और पाकिस्तान की मनोकांक्षा ही पूरी होगी। चीन और पाकिस्तान भी नियमित युद्ध नहीं चाहते। हमें लम्बे समय तक 'शीत युद्ध' का सामना करना पड़ेगा जो एक प्रकार से वास्तविक युद्ध से अधिक कठिन तथा जटिल होगा। जब तक यह संकट रहे, यह हमारे चरित्र, अडिगता, दृढ़ता, सहनशीलता तथा संगठित रहने की शक्ति की परीक्षा होगी। मैं यह नहीं कहता कि इसकी त्रुटियों के लिये सरकार की आलोचना न करें। न केवल सारा देश बल्कि शास्त्री जी की सरकार पिछले 17 वर्षों में की गई गल्तियों के बवंडर का सामना कर रही है। इस समय हमारी सेना कमज़ोर है और आचार्य कृपालानी उन व्यक्तियों में से हैं जो सेना पर अधिक व्यय न करने पर जोर देते थे।

श्री जी० भ० कृपालानी (अमरोहा) : नहीं, नहीं।

श्री फ्रेंक एन्थनी : आन्तरिक रूप से देश में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जैसी भारी भूल की गई।

श्री जी० भ० कृपालानी : क्या मेरे माननीय मित्र ने इसका विरोध किया ?

श्री फ्रंक एन्थनी : केवल मैं ने ही सभा में इसका विरोध किया था । मैं ने इस घोर भूल का विरोध किया था । फिर सरकार को खाद्य के क्षेत्र में असफलता मिली । इसका कारण यह है कि राज्य-सरकारें आपस में राजनीतिक झगड़ों में व्यस्त हैं । लोकतंत्र राष्ट्र का सब से बड़ा गुण यह है कि वह संकट के समय अपने सभी मत-भेदों को मिटा कर एक हो जाता है और आज हमें ऐसे ही संकट का सामना करना पड़ रहा है ।

श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने कहा कि गुट-निरपेक्षता की नीति अपनाने से हमें काफी सफलतायें मिली हैं । मैं यह पूछता हूं कि वे सफलतायें क्या हैं ? इस नीति से हमारा अपमान हुआ है, हमें लज्जित होना पड़ा है और हमारे देश के कोई भी मित्र नहीं रह गये हैं । आज सरकार को सत्तारूढ़ दल में घुस आये साम्यवादियों, गुप्त-साम्यवादियों तथा ऐसे अन्य लोगों के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहिये ।

इस समय तात्कालिक आवश्यकता इस बात की है कि हमारी स्पष्ट और दृढ़ सीमा नीति होनी चाहिये । पाकिस्तान का यह प्रयत्न है कि वह हमारी सेनाओं को एक सुदृढ़ सेना नहीं रखना चाहता और वह चाहता है कि यह सेना स्थान-स्थान पर बिखरी हुई हो ताकि हमें देश की प्रतिरक्षा में और यदि आवश्यकता हो तो आक्रमण करके शत्रू को खदेड़ने में सफलता न मिले । इस सम्बन्ध में मैं सरकार से इस बात पर विचार करने के लिये कहूंगा कि हमारी सीमाओं की रक्षा का कार्य भार राज्य सरकारों के पुलिस दल पर नहीं छोड़ा जा सकता । उनको दिये गये उपकरण घटिया प्रकार के हैं और उन लोगों का प्रशिक्षण भी उचित प्रकार से नहीं हुआ है । सीमा पर पुलिस का काम किसी सैनिक संगठन द्वारा किया जाना चाहिये । इसमें सशस्त्र सेना के अधिकारी होने चाहियें तथा सेना का ही अनुशासन होना चाहिये । यह संगठन प्रतिरक्षा की दूसरी महत्वपूर्ण पंक्ति होगी जिसका आज हमारे देश में अभाव है ।

लोगों ने पाकिस्तान के अच्छी स्थिति में होने के बारे में कहा है और भारत सरकार की इस सम्बन्ध में आलोचना की है । परन्तु हमें यह समझ लेना चाहिये कि एक आक्रमणकारी को आरम्भ में सदैव ही लाभ रहता है क्योंकि वह एक ऐसे स्थान पर आक्रमण करता है जहां से उसे लाभ होना हो । उन्होंने कच्छ पर इसलिये आक्रमण किया है क्योंकि वहां उन्हें सेना तथा युद्धोपकरण लाने लेजाने की सुविधा थी । कंजरकोट तथा वह क्षेत्र जिस पर पाकिस्तान ने अब आक्रमण किया है, सिंध प्रान्त का कभी भाग नहीं था । भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में यह बात स्वीकार की गई है कि उस क्षेत्र में पाकिस्तान की सीमा वही होगी जो सिन्ध के पुराने प्रान्त की सीमा थी और सिन्ध के पुराने प्रान्त में कंजरकोट तथा वह क्षेत्र जिस पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया है कभी सम्मिलित नहीं था ।

किसी जानकारी के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि आज हमारी सेना सुदृढ़ है, उसका मनोबल ऊंचा है और और उसे अच्छा प्रशिक्षण दिया जा रहा है । आज भारत में जो शस्त्र तथा उपकरण बन रहे हैं, वे बहुत अच्छी किस्म के हैं । आज हमें युद्ध के स्थानों पर युद्धोपकरण पहुंचाने के सम्बन्ध में कठिनाई हो सकती है परन्तु हमारे अनुभवी जनरलों और ऐसी सेना जिसका मनोबल बहुत ऊंचा है के होते हुए हम शीघ्र ही, यदि पाकिस्तान आक्रमण करता ही रहा, उसे पूरा पूरा जवाब देने के योग्य हो जायेंगे ।

[श्री फ्रेंक एन्थोनी]

यह सुनिश्चित करने के लिये कि देश आन्तरिक रूप से सुदृढ़ रहे, गृह-कार्य मंत्री को कदम उठाने होंगे ।.उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि साम्यवादी पंचमांगी तथा शरारत करने वाले साम्प्रदायिक तत्व हमें कमज़ोर न बना दें ।

मुझे आशा है कि पाकिस्तान इस झगड़े को युद्ध का रूप नहीं देगा । यदि पाकिस्तान युद्ध आरम्भ करता है, तो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी । परन्तु हम ऐसा नहीं करना चाहते । आशा है कि पाकिस्तान बुद्धिमत्ता दिखायेगा । हमारा झगड़ा चीन से है और इस झगड़े को निपटाने के लिये हमें प्रयत्नशील रहना चाहिये ।

हमें विदेशों से मित्रता स्थापित करनी है । विगत दिनों में कांग्रेस दल में साम्यवादियों तथा अर्द्ध-साम्यवादियों के दबाव के कारण सरकार ने कुछ अन्य देशों को अप्रसन्न किया है । यदि हम अपने मित्र-देशों की आलोचना करते हैं तो हम ऐसे देशों की आलोचना भी क्यों नहीं करते जो हमारे शत्रु बन सकते हैं ।

हमें झगड़ों को निपटाने के लिये बातचीत का तरीका अपनाना चाहिये । हमें यह भी याद रखना चाहिये कि हमारे पास एक विशाल सेना है और उसमें और भी बढ़ोतरी हो रही है । यदि शत्रु देशों ने बातचीत के तरीके की उपेक्षा की तो उन्हें इस विशाल सेना का सामना करना पड़ेगा ।

श्री **कृष्ण मेनन** (बम्बई–उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ने सरकार की नीति की घोषणा कर के गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं रखी है । उन्होंने यह कहा है कि सरकार सैनिक तथा राजनयिक दृष्टि से देश की रक्षा करने के लिये दृढ़-संकल्प है । यही एक साधन है जिससे हम देश की अखण्डता बनाये रख सकते हैं ।

मैं सभा को याद दिला दूं कि लगभग 17 वर्ष पूर्व भारतीय क्षेत्र अर्थात् जम्मू तथा काश्मीर पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया था और इस आक्रमण के बाद पाकिस्तानियों द्वारा भारतीय क्षेत्र पर और आक्रमण किये जाते रहे । कई बार उन्होंने हमारी सीमाओं का उल्लंघन किया है और तोड़-फोड़ की कार्यवाहियां भी की हैं । इस प्रकार पाकिस्तान भारत से स्थायी रूप से शत्रुता रख रहा है ।

पाकिस्तान एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न पृथक देश है । वे हमारे साथ नहीं रहना चाहते । उनके साथ किसी प्रकार का प्रसंधान बनाने से हमें कोई लाभ नहीं होगा और उनको भी सन्देह होगा । इसलिये हमें यह मान लेना चाहिये कि भारत तथा पाकिस्तान पृथक पृथक देश हैं ।

मैं यह बता देना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री के प्रस्ताव को हम कच्छ-सिन्ध सीमाओं की घटनाओं तक ही सीमित रख कर गलती करेंगे । शायद यह स्थिति, कुछ ही दिनों में जब वर्षा आरम्भ हो जायेगी, सुधर जायेगी । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि जो लड़ाई लगभग 17 वर्ष पहले आरम्भ हुई, वह इस प्रकार बन्द हो जायेगी । यहां यह बात बार-बार कही गई है कि आज हमारे पास पहले की तुलना में बड़ी सेना है और काफी अस्त्र-शस्त्र हैं और आज हम इस कठिनाई का सामना पहले की अपेक्षा दृढ़ता से कर सकते हैं ।

हमें यह दखना है कि पाकिस्तान का इरादा क्या है । पिछले दस से पन्द्रह वर्षों में उसने दस खरब डालरों के सैनिक उपकरण प्राप्त किये हैं । पिछले दो वर्षों को छोड़ कर उसका आध से अधिक सैनिक आय-व्ययक विदेशों से प्राप्त हुआ है । वास्तव में 1955 से पहले कभी भी

पाकिस्तान ने काश्मीर के बारे में हमें धमकी नहीं दी । इसके बाद में ही उन्होंने हमें धमकी देना आरम्भ किया । उसने भारी मात्रा में उपकरण प्राप्त कर लिये हैं और उसकी सेना का प्रशिक्षण मिला है तथा सशस्त्र सेना का आधुनिकीकरण हुआ है । कुछ समय से उसने चीन से भाई चारे का सम्बन्ध भी स्थापित कर लिया है । इसलिये हमें इस पर विचार करना है कि उनकी आक्रमण की शक्ति को कम करने के लिये हम क्या कर सकते हैं ।

अमरीका सरकार ने हमें बार-बार यह आश्वासन दिया कि पाकिस्तान को दिये जाने वाले सैनिक उपकरण साम्यवाद को रोकने के उद्देश्य से दिये जा रहे हैं और यदि इनका हमारे विरुद्ध प्रयोग हुआ, तो वे हस्तक्षेप करके पाकिस्तान को रोकेंगे । परन्तु हमें यह समझ नहीं आया कि दूसरे विश्व युद्ध के टैंक रूस के विरुद्ध रावलपिंडी से कैसे प्रयोग किये जा सकते हैं । यह स्पष्ट है कि ये उपकरण पाकिस्तान द्वारा इस प्रयोजन से प्राप्त किये कि हमारे विरुद्ध प्रयोग किये जायें । वास्तव में काश्मीर पर चर्चा के दौरान तथा अन्य अवसरों पर पाकिस्तानी नेताओं ने स्पष्ट रूप से यह बात मानी है । उन्होंने इस तथ्य को छिपाया नहीं । उन्होंने कहा कि हम पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, हमारे पास जो भी उपकरण हैं, हम उनका प्रयोग करेंगे । पाकिस्तान ने एक ओर तो साम्यवाद के विरुद्ध शस्त्र प्राप्त किये हैं और दूसरी ओर उसने चीन से अपने सम्बन्ध स्थापित किये हैं । पाकिस्तान तथा चीन का यह विचित्र सम्बन्ध हमारे लिये बहुत हानिकारक है ।

हम यह सोचते हैं कि अफ्रीका तथा मध्य-पूर्व के देशों में पाकिस्तान ने जो प्रचार हमारे विरुद्ध किया है, उससे वे लोग प्रभावित हो गये हैं । परन्तु मैं यह कहूंगा कि यह सच नहीं है । यह हो सकता है कि वे वही बात कहें जो हम कहते हैं, परन्तु पाकिस्तान द्वारा भारत के प्रति घृणा तथा पंडित नेहरू जैसे हमारे नेताओं के विरुद्ध जो प्रचार किया गया उससे मध्य-पूर्व -देशों की जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । वे अभी हमारे पारस्परिक सम्बन्धों को नहीं भूल रहे हैं । साम्राज्य-वाद के प्रति उनका वही दृष्टिकोण रहा है जो हमारा था ।

हमें ऐसी नीति बनानी चाहिये कि हम अपना राज्य क्षेत्र शत्रुओं के हाथों में न दें । वास्तव में हमने कोई भी राज्य-क्षेत्र नहीं खोया । हमारे राज्यक्षेत्र पर अवैध रूप में कब्जा किया गया है और वह समाप्त हो जायेगा । परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सीमाओं की रक्षा राज्य पुलिस द्वारा नहीं परन्तु हमारी सेनाओं द्वारा की जानी चाहिये ।

कंजरकोट पर आक्रमण के बाद से जम्मू तथा काश्मीर की युद्ध-विराम रेखा पर भारी अतिक्रमण हुए हैं । उस क्षेत्र में शस्त्रों का प्रयोग किया जाना उन सभी समझौतों का उल्लंघन है जिन पर पाकिस्तान द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं । पाकिस्तान द्वारा अतिक्रमणों की संख्या अब बहुत बढ़ गई है । पहले वे एक वर्ष में 100 के लगभग अतिक्रमण करते थे और अब इतने अति-क्रमण वे दो तीन महीनों में करते हैं । अब समय आ गया है जब हम इस बात पर विचार करें कि युद्ध-विराम रेखा पर पर्यवेक्षक-दल द्वारा किया जाने वाला सुरक्षा सम्बन्धी कार्य उचित रूप में किया जाये ।

दस वर्ष पूर्व बांडुंग सम्मेलन के समय एशिया तथा अफ्रीका के देशों में एकता थी ; आज भी है । परन्तु इन देशों के विकास के साथ-साथ ही कुछ कमियां भी सामने आ रही हैं और इसी-लिये एशिया के देशों में झगड़ा चल रहा है । इस आधार पर मैं यह कहता हूं कि जब कि हम पर पाकिस्तान के आक्रमण का जवाब हमारी सेनायें देंगी, प्रधान मंत्री तथा सरकार को यह ध्यान रखना चाहिये कि हम किसी भी समय बातचीत करके इन झगड़ों को निबटाने का विचार न छोड़ें । हम

[श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित]

इस दृष्टिकोण से किसी से भी बातचीत करने के लिये तैयार हैं परन्तु इस आधार पर नहीं कि हम अपनी प्रभुसत्ता पर आंच आने दें। हमारी यह स्थिति है और पहले भी यही स्थिति थी।

राष्ट्रपति अयूब भी यही कहते हैं। दो दिन पूर्व उन्होंने ढाका में कहा कि भारत तथा पाकिस्तान में कोई युद्ध नहीं होना चाहिये ; हमने युद्ध किये बिना तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में जाये बिना कई समस्यायें हल की हैं, तो हम इसी प्रकार अपने झगड़े क्यों नहीं निपटा लेते। कन्जरकोट तथा कच्छ का रन क्या है ? यह नमकीन पानी वाली निर्जन भूमि है। इस प्रकार राष्ट्रपति अयूब कहते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यदि यह नमकीन पानी वाली निर्जन भूमि है तो वह उस क्षेत्र पर आक्रमण क्यों करते हैं ?

जहां तक इस सम्बन्ध में प्रचार किये जाने का प्रश्न है, मेरा यह विचार नहीं कि केवल वही देश अधिक प्रचार सम्बन्धी साहित्य विदेशों में भेजता है। परन्तु यह देख कर आश्चर्य हुआ जब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक प्रैस विज्ञप्ति में यह कहा कि भारत सरकार यह कह कर एक सफेद झूठ बोल रही है कि कच्छ की रन में पाकिस्तान द्वारा टैंक भी प्रयोग किये गये थे। उन्होंने यह कहा कि कच्छ के रन के नमकीन पानी वाले क्षेत्र में टैंक नहीं चल सकते। परन्तु इस विज्ञप्ति में वे आगे यह कहते हैं कि भारत के टैंक वहां मौजूद थे।

अब मैं इस बात के राजनैतिक पहलू पर आता हूं। पाकिस्तानी पुलिस कर्मचारी हमारे राज्य क्षेत्र में आते हैं, लोगों को मारते हैं और फिर उनसे प्रश्न पूछते हैं। वे हमारे राज्य क्षेत्र में घुस आते हैं और फिर कहते हैं कि यह विवाद-ग्रस्त क्षेत्र है। आक्रमण करने के परिणामस्वरूप ही सदैव झगड़ा होता है। परन्तु पाकिस्तानी कहते हैं कि उन्होंने आक्रमण नहीं किया। उदाहरणार्थ जब कश्मीर पर आक्रमण हुआ तो हम यह मामला सुरक्षा परिषद् में ले गये। पाकिस्तान द्वारा यह तर्क दिया गया कि यह झूठा प्रचार है परन्तु बाद में उन्होंने यह स्वीकार किया कि वहां उनकी सेना के तीन ब्रिगेड थे।

इन परिस्थितियों को देखते हुये, मैं यह कहूंगा कि हमें अपनी सीमाओं के बारे में सावधान रहना चाहिये। यह हम सब संसद् सदस्यों तथा अन्य सभी लोगों का उत्तर-दायित्व है कि किसी प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न होने से पहले ही स्थिति का सामना करने के लिये हम तैयार रहें। पाकिस्तान की यही युद्ध-नीति रही है कि वे हमारी सीमाओं पर आक्रमण करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। हमें उनको यह बता देना होगा कि हम दोनों पृथक-पृथक देश हैं और यदि हम पर आक्रमण किया गया तो हम इसका पूरा पूरा जवाब देंगे।

जहां तक कच्छ की सीमा का सम्बन्ध है, झगड़े का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि कच्छ भारतीय संघ का अंग संसद के किसी अधिनियम द्वारा नहीं बना है। कच्छ "ब्रिटिश भारत" का भाग नहीं था। कच्छ रियासत का भारत संघ में विलयन हुआ था और इस प्रकार कच्छ भारत का भाग बना था। इसलिये वह सारा क्षेत्र जो कच्छ के महाराव के महाधिपत्य में था भारत संघ का भाग बना। इसलिये इस राज्यक्षेत्र

की कुछ फुट भूमि के इस ओर अथवा उस ओर होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । वहां कोई जनमत सं ह का प्रश्न नहीं था और फिर पाकिस्तान ने पिछले 17 वर्षों से इस क्षेत्र के बारे में कोई दावा नहीं किया । यह लवण क्षेत्र नहीं है । पाकिस्तान 3,500 वर्ग मील क्षेत्र पर दावा करता है । यह एक बड़ा क्षेत्र है । कुछ दिनों में जब इस क्षेत्र में पानी आ जायेगा तो शायद किसी दूसरी ओर आक्रमण किया जायेगा और सरकार को स्वभाविक रूप से स्थिति का सामना करना पड़ेगा । संसद् तथा जनता को भी तैयार करना पड़ेगा ।

जहां तक राजनयिक पहलू का सम्बन्ध है, यह सोचना व्यर्थ है, कि सेनायें चाहे कितनी ही शक्तिशाली हों और देश चाहे कितने ही समृद्ध हों, विश्व-मत के बिना कोई देश अपनी मर्जी कर सकता है । इसलिये राजनयिक दृष्टि से अब यह पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि हम अफ्रीकी-एशियाई देशों को अपनी स्थिति के बारे में ठीक तरह समझायें । वे देश भारत का सम्मान करते हैं क्योंकि सर्वप्रथम हमें ही स्वतन्त्रता मिली थी और हमने स्वतन्त्रता के आदर्श को आगे बढ़ाया ।

मेरे विचार में यह भी आवश्यक है कि हम ब्रिटेन तथा अमरीका को, जिन्होंने बार-बार यह कहा था, कि उनके शस्त्रों का हमारे विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जायेगा, याद दिलायें कि ऐसा करने की अनुमति दे कर वह डलेस के इस सिद्धान्त को कार्यरूप दे रहे हैं कि एशिया के देश आपस में लड़ें ।

मैं सरकार की ठोस नीति की प्रशंसा करता हूं और आशा करता हूं कि यह प्रस्ताव बिना किसी विमति के पारित किया जायेगा ।

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी (बरहामपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित ने कंजरकोट पर पाकिस्तान द्वारा किये गये आक्रमण के बारे में कहा । वहां अमरीकी हथियारों का प्रयोग भारत के विरुद्ध किया गया जब कि यह हथियार साम्यवाद को दूर रखने के लिये उन्हें दिये गये थे और अमरीकी नेताओं द्वारा भारत को यह आश्वासन दिया गया था कि यह शस्त्र भारत के विरुद्ध प्रयोग नहीं किये जायेंगे ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

परन्तु इसी प्रसंग में उन्होंने गुट-निरपेक्षता के बारे में भी कहा । मुझे यह पता नहीं लगता कि पाकिस्तान तथा भारत के बीच युद्ध के संदर्भ में गुट-निरपेक्षता के बारे में कुछ कहना कहां तक संगत है । जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान, जिसने एक नये क्षेत्र में भारत पर आक्रमण किया है, अमरीका का मित्र देश है और उसे वहां से सैनिक सहायता मिल रही है तो हम अपने को एक विचित्र स्थिति में पाते हैं ।

मैं नम्रता से श्रीमती पंडित से कहूंगा कि भारत-पाकिस्तान के इस झगड़े में तटस्थता का प्रश्न कहां से आता है । हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने भी एक बार कहा था सीमाओं की रक्षा करने में तटस्थता का प्रश्न ही नहीं उठता । इस प्रकार तटस्थता की बात इस बारे में कहना बेकार तथा निरर्थक है ।

[श्री त्रिदिव कुमार चौधरी]

अब प्रश्न यह उठता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। जब प्रधान मंत्री ने यह कहा कि इस समय स्थिति बड़ी नाजुक है। एक कदम युद्ध है तथा दूसरा कदम बातचीत है। इसलिए हमें यही निर्णय लेना है कि ऐसी क्या कार्यवाही करें जिससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा हो सके। यह स्पष्ट है कि सामरिक दृष्टि से इनकी खाड़ी में हमारी स्थिति ठीक नहीं है और हमें सैनिकों पर ही यह छोड़ना ठीक है कि युद्ध की दृष्टि से वह जो चाहें करें। यदि हमने सैनिकों पर यह जिम्मेदारी नहीं छोड़ी तो हमें काफी नुकसान हो सकता है। हमें यह जिम्मेदारी उन पर केवल रन की खाड़ी के बारे में ही नहीं छोड़नी चाहिए अपितु पूरी सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी ही उन पर छोड़ देनी चाहिए।

हाल में ही पश्चिम बंगाल के कच बिहार में भी गोलीबारी हुई। मुझे प्रसन्नता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने वहां की सीमा की रक्षा करने की जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाई है। तथा कठोर कदम उठाया है। परन्तु पश्चिम बंगाल सरकार को इससे बड़ा ही असंतोष हुआ कि केन्द्रीय सरकार ने उनसे, बिना ही पूछे युद्ध विराम की घोषणा कर दी। बात ठीक नहीं हुई है।

यह प्रश्न केवल कंजरकोट तथा कच्छ का नहीं है अपितु यह प्रश्न भारत-पाकिस्तान की पूरी सीमा तथा आपसी संबंधों का है। इसलिए मैं सरकार से पूछना चाहता हूं क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो, सरकार देश की सीमा की रक्षा के लिए सभी प्रकार की कार्यवाही करने को तैयार है। यदि प्रधान मंत्री ने इस संबंध में कोई स्वीकारात्मक घोषणा कर दी तो समस्त देश को संतोष हो जायेगा।

श्री सेझियान (पेराम्बलूर): पाकिस्तानियों द्वारा किए गए उत्तेजनात्मक कार्यों में वर्तमान रन की सीमा पर मुठभेड़ योजनाबद्ध सैनिक कार्यवाही थी। रन की सीमा पूर्णत: निश्चित है। 1960 में अयूबखां ने स्वयं ीमा संबंधी नियमों को स्वीकार कर लिया था इन नियमों के अनुसार यह व्यवस्था थी कि जिस क्षेत्र में भी सीमा अंकित नहीं है वहां पर दोनों ओर के अधिकारी मिल कर सीमा निश्चित कर लेंगे। परन्तु सिंध तथा कच्छ की सीमा तो पूर्णत: अंकित है। यदि पाकिस्तान के मन में इसके बारे में कोई संदेह है तो उनको इस बारे में बातचीत करानी चाहिए और सीमा निश्चित कर लेनी चाहि। परन्तु हमारा ऐसा कहना संसार को हमारी कमजोरी नहीं मानना चाहिए। पाकिस्तान सरकार तथा संसार को मालूम होना चाहिए कि आक्रामक को अपनी भूमि से हटाने के लिए हम सभी कुछ करने को तैयार हैं। मैं प्रधान मंत्री को द्रविड़ मंत्री मुनेत्र कषघम की ओर से पूरा आश्वासन देता हूं कि आक्रमणकारी को अपनी भूमि से हटाने के लिए हम हमेशा उनका साथ देंगे। हम भारत को लोकतंत्र स्वतंत्र बनाये रखना चाहते हैं। इस संबंध में मैं आपका ध्यान उस प्रतिज्ञा की ओर दिलाना चाहता हूं जो हमने 14 नवम्बर, 1962 को सभा में ली थी कि भारत भूमि से आक्रामक को हटा कर ही दम लेंगे। परन्तु मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमने इस प्रकार की प्रतिज्ञा की थी और यह प्रतीज्ञा सरकार पूरी नहीं कर पाई। और इसलिए हमने जनता का विश्वास खो दिया। मैं चाहत हूं कि कहीं ऐसा न हो कि हम यहां पर पुन: कुछ उसी प्रकार की प्रतीज्ञा

करें और उसको पूरी न कर पायें । कुछ ऐसा लगता है कि पाकिस्तान भी चीन के समान ही कुछ करना चाहता है । उनका विचार भी ऐसा ही मालूम होता है कि कुछ भूमि ज़बरदस्ती दबा ले तथा बाद में युद्धविराम की घोषणा कर दो हमें स्पष्टतया ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार का आक्रमण हमें हटाना है । इस का यह अर्थ नहीं है कि हम लड़ाई चाहते हैं अपितु हमें किसी प्रकार पाकिस्तान को यह बताना है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए ।

इस संबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । सबसे पहले हमें अपनी परिवहन तथा संचार सुविधायें ठीक करनी चाहिए जिससे हम अपने सनिकों को शीघ्रता से आक्रमण होने पर सीमा पर भेज सकें । दूसरी बात यह है कि हमें साम्प्रदायिकता को नहीं फैलने देना चाहिएं । हम मुसलमानों के विरुद्ध नहीं लड़ रहे हैं अपितु पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ रहे हैं। तीसरे हम सभी को मिल कर आक्रमण को हटाना चाहिए । पार्टियों का ध्यान छोड़ देना चाहिए । आपसी पार्टी मतभेद हमें स्वयं अपने आप दूर करने हैं तथा लोकतंत्र को बनाय रखना है ।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : उपाध्यक्ष महोदय, 1950 में मैं नया नया संसद् का सदस्य बना था । उस समय कांग्रेस पार्टी की एक बैठक हुई थी जिसमें बड़े बड़े महारथी उपस्थित थे । चर्चा का विषय भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध थे । उस समय मैंने अपने भाषण में कहा था कि युद्ध की बात करना आसान नहीं है । युद्ध अगर हुआ तो बम्बई तथा दिल्ली भूमिसात हो जायेंगे । परन्तु अब वह ज़माना समाप्त हो गया है । अब अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि चाहे दिल्ली में संसद् भवन जैसे हज़ारों भवन नष्ट हो जायें तो भी हमें चिन्ता नहीं करनी चाहिए और अपनी प्रत्येक इन्च भूमि के लिए लड़ने मरने को तैयार रहना चाहिए ।

पाकिस्तानी सेना में वही अफसर इस समय हैं जो पहले भारतीय सेना में थे । यदि आप 1914 से 1930 के आंकड़े देखें तो आप को मालूम होगा कि 1914 से 1930 तक मुसलमान अफसरों की प्रतिशता सेना में बहुत बढ़ गयी थी । यह अफसर इस समय पाकिस्तानी सेना के कर्णधार हैं ।

महात्मा गांधी ने अन्त तक विभाजन का विरोध किया तथा इसी के कारण वह शहीद हो गये । वह नहीं चाहते थे कि विभाजन हो परन्तु कुछ लोगों ने यह समझ कर कि संभवतया विभाजन से हमारी समस्यायें दूर हो जायें, विभाजन करवाया । परिणाम हम देख रहे हैं कि आज विभाजन के बाद हमें 20 गुनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ।

हम जानते हैं कि पाकिस्तान किन लोगों के कारण बना । यह लोग और कोई नहीं अंग्रेज़ थे । और मैं बताना चाहता हूं कि यह अंग्रेज़ ही इस समय पाकिस्तान की पीठ पर हैं तथा गड़बड़ी करा रहे हैं । अंग्रेज़ चाहे इंगलैंड के हों चाहे अमरीका के एक समान ही हैं ।

पाकिस्तान ने उसके बाद चीन से संधि कर ली । जिसके द्वारा चीन के पास 10,000 वर्ग मील का काश्मीर का इलाका उसने चीन को दे दिया । इस प्रकार उसने हमारे तथा अपने साथ धोखा ही किया है । हमें चर्चिल के समान ही दृढ़ता से सामना करना चाहिए ।

[श्री ज़ोकीम आल्वा]

चीन तथा रूस के बीच भी आपसी समस्यायें हैं और स्पष्ट है कि इन समस्याओं के कारण दोनों एकमत नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें सभी प्रकार के प्रयत्न करने हैं जिनसे हमारा कंजरकोट हमें वापस मिल जाये। हमें अपनी इस चौकी को पाकिस्तान के हाथों में नहीं छोड़ना है। हमें अब सभी उचित कार्यवाही करनी चाहिए जिससे हमारी यह चौकी पुनः हमारे हाथ में आ जाये।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : आज हमारी परीक्षा का दिन है क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया है। इस सम्बन्ध में दिल्ली के एक समाचारपत्र में एक लेख निकला है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान का विचार भारतीय ज़मीन दबाने का नहीं है अपितु उसका विचार भारतीय भावनाओं को कुचलना है। उन्होंने योजनाबद्ध हो कर यह आक्रमण किया है। मैं बताना चाहती हूं कि भावनायें तथा मानसिक दृढ़ता बड़ी चीज़ हैं और हमें इसका प्रयत्न करना है कि हमारी जनता की मानसिक दृढ़ता बनी रहे। जब जर्मनी ने हमला किया तो वह बवंडर की तरह बढ़ता ही गया। परन्तु ब्रिटेन तथा फ्रांस ने हिम्मत नहीं छोड़ी और चार वर्ष की मुसीबतों के बाद जर्मनी को नीचा दिखा कर ही दम लिया। मुझे प्रसन्नता है कि अपने नेताओं में मैं भी ऐसी ही दृढ़ता पाती हूं। हमारे प्रधान मंत्री ने लोकतंत्रीय पद्धति को अपनाते हुए बिना घबराये लोक-सभा में चर्चा करने का प्रस्ताव पेश किया। मेरा यही कहना है कि हम संसद् सदस्यों को ऐसा दिखाना चाहिए कि हम सुदृढ़ हैं तथा हमारी भावनायें अभी गिरी नहीं हैं और हमारा उत्साह थका नहीं है।

हमारा कुछ क्षेत्र पाकिस्तान ने ले लिया है तथा हमारे लिए यही उचित है कि हम उसे वापस लें। परन्तु किस प्रकार। मैं बताना चाहती हूं कि ऐसा करने का काम हमें अपनी सेना पर छोड़ देना चाहिए। सेना को हम पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ वह करेंगे हम उसका समर्थन करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि ऐसा किया गया तथा हम सब ने अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतः निभाया तो देश से इन आक्रामकों को शीघ्र बाहर निकाल सकेंगे।

आज अंग्रेज़ तथा अमेरिकन इसका ढिंढोरा पीट रहे हैं कि लोकतंत्र बना रहना चाहिए। बातचीत से समस्यायें हल की जानी चाहिए। परन्तु उनसे मेरा यह कहना है कि कृपया थोड़ा सा मन को टटोलें और देखें कि उनके मन में क्या है।

पाकिस्तान ने रन की खाड़ी पर हमला किया। मालूम होता है कि वह रन की खाड़ी पर कब्ज़ा नहीं करना चाहते हैं। वह तो हम को उत्तेजित करना चाहते हैं। अन्त में मेरा यही कहना है कि हमें इन बातों से उत्तेजित नहीं हो जाना चाहिए तथा जो संभव हो ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे आक्रामक भारतीय भूमि से हट जायें।

Shri Prakash Shastri (Bijnauor). Mr. Deputy Speaker, Sir these days the ruler of Pakistan is such a man who does not under stand any other language except of war. Therefore our Government should take note of those wrongs done by her in relation to Pakistan. Firstly Hindus were driven out of Pakistan but our Government did not take any action. Secondly war in Kashmir was stopped without taking our territory back. Thirdly only 1965 miles of borders has been demarcated uptil now. The greatest blunder was made

that it has allowed those Pakistanis to settle down in Tripura, etc. who came there without any valid passports. In Kutch these Pakistanis came in large numbers and their percentage risen to 26 from 18. We can know by this, that how they are active in India. Pakistanis had constructed a road in Indian territory in Kanjarkot and I know that Pakistan is constructing another Road in Jaisalmer area of Rajasthan. Out Government should know it.

Our forces were in disadvantages conditions in Kutch but the way our forces repulsed their attack was something to be praised.

Now take the way that how Pakistanis are making propaganda against India in other countries. In Saudi Arabia, and in Indonesia there was a Muslim conference. Then Pakistanis said that the Muslims in India are not safe and therefore India again should be devided to free those Muslims who are in India. In this context I am of the opinion that Pakistan wants to create a bad impression in regard to India before the Algeria conference.

I am very happy to read in some newspapers yesterday that some nationalistic Muslims made statements to drive out Pakistan from India. But side by side I also want to say that there are some incidents going on in the country which should not be taken very lightly by our ministers. The attack on Vice Chancelor of Aligarh University was not done to reservation of seats in Collages but it was due to discussion held in U.P. Assembly in regard to molesting of girls of Tikaram Girls College.

I want to draw the attention towards the attitude of some english newspapers. They have published a Photo of our P.M. with Shri Chavan and Shri Nanda. This was a Photo showing given faces of our Ministers. These press photographers must have taken some other shapes also but it is my unfortunate that their Photo was published.

One more thing I want to say and that is the trick of Pakistan. Since the return of General Ayub from Russia and China he is trying to do the thing which China has done. First he attacked then proposed of cease fire. Therefore I appeal that our Prime Minister should try to avoid this. We should clearly state that unless our territory is vacated we are not going to negotiate.

We should enter into negotiations with Pakistan but not at the cost of our national interest. I have read in a book that at the time of Pakistan's attack on Kashmir in 1947 Gandhiji had said that we should not send our forces to Kashmir but we should retaliate by sending our forces to Karachi via Lahore. We should settle our retired serviceman in the border areas. I would request the hon. Defence Minister to deal with Pakistan firmly. Thereafter Pakistan will not dare to cast an evil eye on India.

Shri Iqbal Singh (Ferozepore): Pakistan is bent upon creating troubles for India. There are already many problems created by that country. The latest spot chosen by her is Kutch in Gujerat. She has opened a new front of tension there. Pakistan has occupied some of our area by force. We have toget it vacated. The climatic and geographical situation there is favourable for Pakistan, but the illegal occupation cannot continue for long. This area is very near to Karachi. Our forces will come close to Karachi. Pakistan should under-

[Shri Iqbal Singh]

stand that. 60 percent of her forces are on our border and thus they are a great threat to our security. The number of border incidents has increased. They enter our territory and start unprovoked firing. In return our Jawans have to fire in self defence. I come from border areas of Punjab. The morale of our people there is very high. People cultivate their land right upto border. The farmers are not afraid of Pakistan. These farmers should be provided with arms. It will be beneficial for them and they will drive the Pakistan intruders away.

The border was guarded by Police. It was rightly so, but now the situation has changed. As I said, Pakistan is creating trouble. We should also introduce necessary change in our border security set up. A semi-military organisation should be created. It should be under the command of military Officers. Keeping in view the present situation on our border it is very essential that necessary changes are made. Ths question should be considered seriously and promptly. About 15 thousand persons retire from army every year. They should be settled on border areas. They will then serve as deterrent to Pakistan.

Pakistan and China have entered into agreements simply because they do not like India's progress. They do not have anything commion between them.

Their ideology is quite different. Their main object is to harm India, but on the other hand India wants to have friendly relations with Pakistan.

श्री जी० भ० कृपलानी (अमरोहा) : हम बहुत कठिन समय में चल रहे हैं। पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया। ऐसे ही चीन ने भी किया था। हम ने तिब्बत पर चीन के अधिकारों को स्वीकार किया था और हम ने समझा था कि चीन के अधीन यह प्रदेश प्रगति करेगा। तिब्बत पर चीन के कब्जे के विरुद्ध आवाज़ उठायी गई थी परन्तु हमारी सरकार ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हम चीन के हथकंडों को समझने में असफल रहे। 1962 में उस ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया। हमारी सरकार को मानना पड़ा कि हम से गलती हुई है। पाकिस्तान के इरादों को हम पहले ही भली प्रकार जानते थे फिर भी हम धोखा खा गये। इस प्रकार चीन ने हमारे क्षेत्र को आक्रमण कर के हथिया लिया है। इस को तीन वर्ष हो गये हैं परन्तु हम ने उस को वापस लेने की कोई कार्यवाही नहीं की है।

आज पाकिस्तान ने आक्रमण करके जो क्षेत्र ले लिया है उस पर उसने 1956 में भी आक्रमण किया था परन्तु उस समय उसे खदेड़ दिया गया था। मैं समझ नहीं पाया कि इतने वर्षों तक सरकार सतर्क नहीं हुई है। आज कहा जाता है कि पाकिस्तान अच्छी स्थिति में है हम उन को हटा नहीं सकते हैं। हमें अपनी वायुसेना को प्रयोग में लाना चाहिये और अपना क्षेत्र खाली कराना चाहिये। हमारे मंत्री बातें अधिक करते हैं परन्तु वास्तविक काम कम करते हैं। हमारे प्रतिरक्षा मंत्री एक मराठा हैं। उन्हें मालूम है कि छत्रपति शिवाजी कैसे कर्मठ नेता थे। उन्होंने अपनी खड़ग से बड़े बड़े राजाओं को ठीक कर दिया था। हमें उन से सबक सीखना चाहिये।

प्रधान मंत्री ने देश से अपील की है कि हमें एकता तथा सहयोग से कार्य करना चाहिये। मैं इस से सहमत हूं, परन्तु सरकार को भी अपने कर्तव्य निभाने में सतर्क रहना चाहिये। सरकार को देश की जनता को सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करानी चाहियें। लोगों ने अपने देश प्रेम तथा एकता का उदाहरण 1962 में चीनी आक्रमण के समय प्रस्तुत किया था। सम्पूर्ण देश बलिदानों के लिये तत्पर हो गया था। परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने देश के प्रति अपने कर्तव्य ठीक प्रकार से नहीं निभाये हैं। हम शान्तिप्रिय देश हैं परन्तु इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिये कि अन्य देश हमारे क्षेत्र को हथियाते जाय।

सरकार को देश में फैले भ्रष्टाचार को पहले समाप्त करना चाहिये फिर लोगों से सहायता की आशा करनी चाहिये। देश में लोग एकता तथा सहयोग चाहते हैं परन्तु सरकार को भी कुछ व्यावहारिक रूप में करना चाहिये। सत्ताधारी पार्टी अर्थात् कांग्रेस पार्टी को भी अपने आंतरिक झगड़ों को समाप्त करके देश के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये।

श्री नि. चं. चटर्जी (बर्दवान) : हम प्रधान मंत्री को आश्वासन दिलाते हैं कि सम्पूर्ण देश सरकार के साथ है। सरकार को इन शत्रु देशों की तुष्टि की नीति त्याग देनी चाहिये। हमें पाकिस्तान तथा चीन के प्रति कठोर नीति अपनानी होगी। काश्मीर के बारे में हमारी सरकार ने इसी प्रकार की नीति अपनायी थी और आज तक काश्मीर समस्या चल रही है। हमें काश्मीर में 1949 में युद्धविराम के लिये सहमत नहीं होना चाहिये था। हमारी कमज़ोर नीति के कारण हमें कई बार हानि उठानी पड़ी है। आज असम में 2 लाख 50 हज़ार के लगभग पाकिस्तानी अवैध तरीकों से आ गये हैं। मैं ने देखा है कि असम राज्य के कुछ अधिकारियों की जानकारी से यह हुआ है। इस सम्बन्ध में सरकार को सूचित भी किया गया था परन्तु सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। इस नीति के फलस्वरूप आज बहुत सी समस्यायें खड़ी हो गई हैं। हमें अपनी नीति स्पष्ट कर देनी चाहिये। हमें आक्रमणकारियों को अपने क्षेत्र से खदेड़ना है। हमें देश की अखण्डता को प्राथमिकता देनी है। प्रतिपक्ष वाले इस विषय में सरकार के साथ हैं। हमारे देश की सेना बहुत शक्तिशाली है। हमें इसकी वीरता पर पूरा विश्वास है और गर्व है, परन्तु हमारी सरकार तथा नेताओं को नीति में सुधार करना होगा। आज चीन और पाकिस्तान ने गठजोड़ कर लिया है। पाकिस्तान की सेनाएं हमारी सीमा पर जमा हो रही हैं। हमें इस समय हर प्रकार की परिस्थितियों के लिये अपने आप को तैयार करना है। पाकिस्तान आज हमारा शत्रु है। जब तक विदेशियों को अपने देश की भूमि से निकाल नहीं दिया जाता तब तक हमें कोई बातचीत नहीं करनी चाहिये।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

आज असम तथा पश्चिमी बंगाल को बहुत अधिक खतरा है। हमें इस ओर भी ध्यान देना होगा। हम प्रधान मंत्री तथा सरकार के साथ हैं परन्तु हमें अपना कतव्य निभाना है और देश की रक्षा करनी है।

प्रधान मंत्री तथा अनुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : हमारी नीति देश के हितों को सामने रख कर बनायी जाती है। उस पर पहले अच्छी तरह विचार किया जाता है। हमारी नीतियां बिल्कुल स्पष्ट हैं। हम तटस्थ रहना चाहते हैं। हम विश्व में शान्ति स्थापना के इच्छुक हैं और शान्तिमय सहअस्तित्व की नीति में आस्था रखते हैं। हमारे देश ने संसार में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

शान्ति के लिये अपना योगदान दिया है । कई बार गम्भीर स्थितियों में हम ने अच्छा कार्य किया है । यह भी ठीक है कि कई बातों में हम असफल भी रहे हैं परन्तु हम अपने निर्धारित मार्ग से विचलित नहीं हुए ।

पाकिस्तान ने गम्भीर स्थिति खड़ी कर दी है । वहां पर युद्ध-विराम हो सकता है यदि पाकिस्तान "जैसे थे" की स्थिति को सहमत हो जाये । हम तभी बातचीत करेंगे । इस बातचीत का परिणाम क्या होगा मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता । हम युद्ध नहीं चाहते । पाकिस्तान झूठे प्रचार में लगा हुआ है । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम ने किसी पर आक्रमण नहीं किया और हम अपनी सीमाओं के भीतर ही हैं । इस के विपरीत पाकिस्तान ने हमारे इलाके पर कब्जा कर लिया है और हम पर आक्रमण का आरोप लगा रहा है । यह बिल्कुल मिथ्या है । ऐसी बात में हम पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते । मैं कहना चाहता हूं कि हमें भी परिस्थितियों को देखते हुए कार्यवाही करनी होगी । हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान बुद्धिमत्ता से काम लेगा नहीं तो हम मजबूर हो जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2, 3, 4, 8, 10, 11 तथा 12 मतदान के लिये रखता हूं ।

स्थानापन्न प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The substantive motions were put and negatived.

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 9 स्वीकार करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह प्रस्ताव रखा जाये :—

"कच्छ सीमा पर पाकिस्तान के सशस्त्र बलों द्वारा बार-बार और लगातार किये जा रहे आक्रमणों से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के पश्चात् यह सभा हमारे सशस्त्र बलों के जवानों और अफसरों और पुलिस बल द्वारा हमारी सीमाओं की रक्षा करते समय वीरतापूर्ण मुकाबले की अतीव प्रशंसा करती है और जिन शहीदों ने अपनी मातृभूमि के सम्मान और अखंडता की रक्षा के लिये अपने जीवन का बलिदान कर दिया है, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है और आशा तथा विश्वास के साथ, यह सभा भारत की पवित्र भूमि से आक्रामक को खदेड़ कर बाहर निकालने के भारतीय जनता के दृढ़ संकल्प का समर्थन करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 9 के स्वीकृत होने पर स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1, 6 तथा 7 अवरुद्ध हुए ।

इसके पश्चात् लोक-सभा वृहस्पतिवार, 29 अप्रैल, 1965 / बैसाख, 9, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, the 29th April 1965/ Vaisakha 9, 1887 (Saka).

GMGIPND—LSIII—715(ai)LS—26-7-65—600